वर्ष 19
अंक 183
12 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

शनिवार, 19 सितंबर 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

पृष्ठ 4

बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 3 साल में सबसे कम

अश्विनी वैष्णव पृष्ठ 2

पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए बनेगा प्रिसिजन विनिर्माण संस्थान

डॉलर रु. 95.90 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 110.10 (अपरिवर्तित) | सोना (10 ग्राम) रु. 1,53,111 ▲ 1870 रु. | सेंसेक्स 74295.0 ▼ 19.60 | निफ्टी 23346.40 ▲ 75.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 23378.50 ▲ 32.10 | ब्रेंट क्रूड 111.9 (अपरिवर्तित)

एक नज़र

प्रतिभूति लेनदेन कर संग्रह 53 फीसदी बढ़ा

सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक 13 फीसदी बढ़कर 12.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। कॉरपोरेट क्षेत्र से बेहतर अग्रिम कर प्राप्ति से इसमें वृद्धि हुई। उधर वित्त वर्ष 2026-27 में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 17 सितंबर तक बढ़कर 40,214.36 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 53 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अग्रिम कर संग्रह 16.18 फीसदी बढ़कर करीब 5.22 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र से अग्रिम कर भुगतान 18 फीसदी बढ़कर 4.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक और गैर-कॉरपोरेट क्षेत्र (व्यक्तिगत तथा हिंदू अविभाजित परिवार) से अग्रिम कर संग्रह 9.24 फीसदी बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा। 17 सितंबर तक कर रिफंड 29.19 फीसदी बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 फीसदी बढ़कर 14.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पृष्ठ 4

विदेशी मुद्रा भंडार 4.92 अरब डॉलर घटा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.94 अरब डॉलर घटकर 780.78 अरब डॉलर रहा। इस गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा और स्वर्ण आरक्षित भंडार में आई कमी है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 44.90 अरब डॉलर बढ़कर 785.71 अरब डॉलर के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2.37 अरब डॉलर घटकर 645.79 अरब डॉलर रह गईं। पृष्ठ 4

आज का सवाल

क्या बदलते दौर में प्रबंधन शिक्षा के तौर-तरीकों में बदलाव की है दरकार?

www.bshindi.com पर राय भेजें।

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो Y और यदि न है तो N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अमेरिकी रुख से व्यापार वार्ता में आएगी दिक्कत?

हां	नहीं
71%	29%

पूंजी बाजार में यूपीआई भुगतान पर 5 रु. शुल्क!

अजिंक्य कावले
मुंबई, 18 सितंबर

पूंजी बाजार में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 0.02 फीसदी के बजाय 5 रुपये प्रति लेनदेन शुल्क तय किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। शेयर ब्रोकरों द्वारा इस पर चिंता जताई गई थी।

सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित बदलाव के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से औपचारिक प्रस्ताव की जरूरत होगी, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (अरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी। यह बदलाव बिल भुगतान और बीमा प्रीमियम के लिए यूपीआई के माध्यम से पहले से उपयोग की जा रही एकसमान शुल्क संरचना के अनुरूप होगा।

घटनाक्रम के जानकार एक व्यक्ति ने कहा, 'शेयर ब्रोकरों की मांग है कि पूंजी बाजार के लिए यूपीआई लेनदेन पर 5 रुपये का एकसमान शुल्क लगे। जब बाजार नियामक की तरफ से औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो आरबीआई और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिसूचित किया जा सकता है। यह यूपीआई के जरिये बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए लगने वाले शुल्क की तरह होगा।'

इस बारे में जानकारी के लिए सेबी और एनपीसीआई को ईमेल भेजे गए मगर खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया।

एमडीआर वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को देता है।

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा था कि बाजार नियामक यूपीआई के माध्यम से बड़ी रकम के भुगतान के लिए नई एमडीआर व्यवस्था पर शेयर ब्रोकरों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगा।

पूंजी बाजार के लिए एमडीआर को लेनदेन मूल्य के 0.02 फीसदी तक निर्धारित किया गया है, जिसमें म्युचुअल फंड, प्रतिभूतियों, शेयर ब्रोकरों, डीलरों और निवेश सलाहकारों को किए गए भुगतान के लिए 300 रुपये की अधिकतम सीमा है। एमडीआर शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

उक्त शख्स ने कहा, 'कुल मिलाकर उद्योग को सालाना लगभग 125 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता। भारत में अधिकांश शेयर ब्रोकरों के पास सुदृढ़ व्यवसाय मॉडल है और वे इन लागत को वहन करने में सक्षम हैं।'

आंकड़ों के अनुसार अकेले अगस्त में शेयर ब्रोकर और डीलरों की श्रेणी में 8.41 करोड़ से अधिक यूपीआई लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका कुल मूल्य 63,667.21 करोड़ रुपये था। एमडीआर ढांचे के सार्वजनिक होने के बाद ब्रोकर संगठनों ने सेबी को अपनी चिंताओं के बारे में लिखा था और परिचालन लागत में वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए सक्रियता से चर्चा कर रहे हैं।

जीरोधा के संस्थापक नितिन कामत ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे लगता है कि एमडीआर ठीक है। यह ग्राहकों द्वारा लेनदेन किए बिना पैसा हस्तांतरण करने की समस्या का समाधान नहीं करता है लेकिन 300 रुपये की उच्च सीमा के बजाय यह एकसमान 5 या 10 रुपये प्रति लेनदेन उचित होगा।'

शेयर ब्रोकरों ने एमडीआर शुल्क पर चिंता जताई थी क्योंकि सेबी के नियम के मुताबिक ब्रोकरों को समय-समय पर ग्राहकों का बचा हुआ पैसा उन्हें वापस करना होता है। सेबी ने यह नियम इसलिए बनाया था ताकि ब्रोकर इस पैसे का गलत इस्तेमाल न कर सकें।

पूंजी बाजार लेनदेन के लिए यूपीआई एमडीआर ढांचे को एकसमान शुल्क में बदलने का फैसला ऐसे समय में हो रहा है जब कई अन्य श्रेणी में भी इसी तरह की शुल्क संरचना लागू है।

एमडीआर का मामला

- शेयर ब्रोकरों ने एमडीआर शुल्क पर जताई थी चिंता
- यूपीआई भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपये शुल्क तय करने का प्रस्ताव
- बीमा, ईंधन, बिल भुगतान आदि की तरह एक समान शुल्क लगाने की मांग
- एकसमान एमडीआर शुल्क के लिए बाजार नियामक की ओर से औपचारिक प्रस्ताव की होगी जरूरत

इमेजिन : दीपक शर्मा

टाटा समूह के बाजार पूंजीकरण को चपत

शिल्पा रंगराजन
मुंबई, 18 सितंबर

टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में आज खासी गिरावट आई जिससे समूह का बाजार पूंजीकरण करीब 39,000 करोड़ रुपये घट गया। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन को तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने उनकी पुनर्नियुक्ति को अवैध करार दिया। शीर्ष नेतृत्व में खींचतान का असर आज समूह के शेयरों पर दिखा।

बाजार पूंजीकरण में नुकसान और नोएल टाटा की टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद टाटा संस की सूचीबद्धता पर शापूरजी पलोनजी समूह के समर्थन के बिल्कुल उलट है।

निफ्टी 50 में 0.33 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई जबकि निफ्टी टाटा 25 कैप सूचकांक 1.12 फीसदी नीचे बंद हुआ।

टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शेयर 3.9 फीसदी गिरकर 2,105 रुपये पर बंद हुआ। इससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 30,754 करोड़ रुपये की कमी आई। टाटा केमिकल्स भी 11 फीसदी नुकसान के साथ 603.25 रुपये पर बंद हुआ। समूह की अन्य कंपनियों में टाटा टेक्नॉलजीज 4.8 फीसदी और टाटा एलेक्सी 3.4 फीसदी नीचे बंद हुआ।

क्यूईडी कैपिटल एडवाइजर्स में मैनेजिंग पार्टनर अनीश टी. ने कहा, 'आम तौर पर शीर्ष नेतृत्व के बीच टकराव से बाजार में हलचल मच जाती है लेकिन टाटा समूह ऐसा संस्थान है जो तंत्र के मजबूत बुनियाद पर टिका है न कि किसी व्यक्तित्व पर। हालांकि कारोबारी संचालन और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को लेकर बोर्डरूम में चल रहे इस टकराव से कुछ समय के लिए हलचल हो सकती है लेकिन समूह की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वह इस मुश्किल दौर से निकल सकता है और लंबे समय में शेयरधारकों के मूल्यों को सुरक्षित रख सकता है।'

यह गिरावट निफ्टी आईटी सूचकांक में देखी गई व्यापक कमजोरी के अनुरूप थी जो दिन के अंत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला प्रमुख सूचकांक रहा।

नोएल टाटा के बयान का असर

- टाटा समूह का बाजार पूंजीकरण करीब 39,000 करोड़ रुपये घटा
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 3.9 फीसदी गिरकर 2,105 रुपये पर बंद हुआ
- टाटा केमिकल्स 11 फीसदी, टाटा टेक्नॉलजीज 4.8 फीसदी और टाटा एलेक्सी 3.4 फीसदी नीचे बंद हुआ

शापूरजी ने टाटा संस की सूचीबद्धता का किया समर्थन

टाटा संस में 18 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक शापूरजी पलोनजी समूह ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने का पुरजोर समर्थन किया है। 17 सितंबर को टाटा संस की हुई बोर्ड बैठक में कंपनी की सबसे बड़ा शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने सूचीबद्धता के प्रस्ताव का विरोध किया था लेकिन इसके एक दिन बाद शापूरजी पलोनजी समूह के चेयरमैन शापूरजी पलोनजी मिस्त्री ने आज विस्तृत बयान जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि कंपनी के लिए सूचीबद्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना क्यों सही है। पृष्ठ 3

MEET
THE SPEAKER

Anant Ladha
Financial Educator & Creator

BUSINESS NEXT PRESENTS
Business Standard
Smart Investor
Arena

26-28 October 2026
Jio World Convention Centre, Mumbai
Register now

प्रबंधन शिक्षा के तरीकों पर हो पुनर्विचार

अहोना मुखर्जी
नई दिल्ली, 18 सितंबर

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि प्रबंधन शिक्षा को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। नागेश्वरन ने कहा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), भू-राजनीतिक स्तर पर बढ़ती होड़ और आपूर्ति व्यवस्थाओं में व्यवधान दुनिया को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलते हालात में प्रबंधन संस्थानों को पारंपरिक तकनीक से आगे निकल कर छात्रों को इन बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए।

नागेश्वरन ने शुक्रवार को नोएडा में 16वें 'इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव' में कहा कि कारोबारी शिक्षा से जुड़े संस्थानों को केवल एआई केंद्रित विषय जोड़ने के बजाय अपने पाठ्यक्रम में समझदारी, मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता, गहरी सोच और चरित्र को केंद्र में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से प्रबंधन का ध्यान कुशलता पर था जिसमें लीन ऑपरेशन, जस्ट-इन-टाइम सिस्टम और सिंगल-सोर्स सप्लाई चेन शामिल हैं। मगर अब ये तीनों वैश्विक झटकों के कारण तेजी से कमजोर हो रहे हैं। सीईए ने कहा कि बड़ी ताकतों के बीच होड़ और आपूर्ति व्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से अब प्रबंधकों को अतिरिक्त क्षमता समझनी होगी, विकल्प बनाए रखने होंगे और संगठनों में मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता विकसित करनी होगी, भले ही इससे लागत क्यों न बढ़ जाए। नागेश्वरन ने कहा, 'बिना किसी रुकावट वाली कुशलता और एकल-स्रोत वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। यह कम से कम एक पीढ़ी तक वापस नहीं आएगी। जो लोग केवल संतुलन साधने, लागत कम से कम रखने और किसी एक सस्ती आपूर्ति पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित हुए हैं उनके लिए दिक्कत यह है कि अब वह दुनिया ही पूरी तरह बदल चुकी है।'

नागेश्वरन की टिपण्णी ऐसे समय में आई है जब हाल में भू-राजनीतिक कारणों से जहाजों की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था में आए व्यवधान से भारतीय कारोबार प्रभावित हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट में और इसके इर्द-गिर्द तनाव के कारण जहाजों को रास्ते बदलने पड़े, लंबे रास्ते अपनाने पड़े, भीड़ बढ़ी और माल ढुलाई व बीमा की लागत भी बढ़ गई। हाल की बाधाओं ने भारतीय कारोबारियों को समान मंगाने के स्रोतों, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए विवश कर दिया है।

इस संदर्भ में सीईए ने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थानों को ऐसे ढांचे बनाने की जरूरत है जो पश्चिम से लिए गए मॉडल के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने कहा, 'हमारी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है। हम युवा हैं, हम अभी भी निर्माण कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक है। हमारी कंपनियों को कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। हमारे प्रबंधकों को ऐसी आबादी के लिए वास्तविक सीमाओं के बीच बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा जो अभी भी गरीबी से बाहर निकल रही है और जिसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं।'

(शेष पृष्ठ 4)

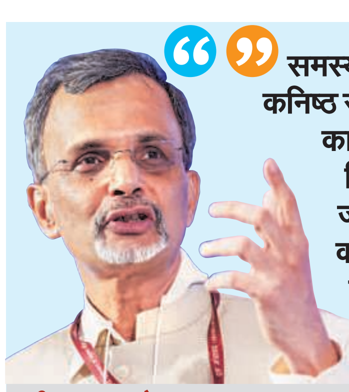

"समस्या यह है कि एआई अब कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों का काम कर रहा है। सीढ़ी के निचले पायदान ही काटे जा रहे हैं। रोजमर्रा के वे काम जिनसे युवा अपना काम सीखते थे, सबसे पहले स्वचालित हो रहे हैं।"

वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार

संक्षेप में

एअर इंडिया के नए सीईओ मंत्री से मिले

एअर इंडिया के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने शुक्रवार को नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू से मुलाकात की। नायडू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि बेहतर संपर्क सुविधा और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की भारी मांग के बीच एअर इंडिया की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। एअर इंडिया ने पांच अगस्त को इथियोपियन एयरलाइंस समूह के पूर्व प्रमुख गेब्रेमरियम को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की थी। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद उनके इस महीने पदभार संभालने की उम्मीद है। बैठक में नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गेब्रेमरियम एअर इंडिया के दूसरे विदेशी सीईओ होंगे। *भाषा*

मारुति में रेलवे टर्मिनल से ढुलाई 10 लाख पार

मारुति सुजूकी इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात और हरियाणा के दो विनिर्माण संयंत्रों में स्थिति रेलवे टर्मिनल के जरिये 10 लाख वाहनों की ढुलाई की है। यह आंकड़ा इन संयंत्रों में विशेष परिवहन लाइन शुरू करने के तीन साल से कुछ अधिक समय में हासिल किया गया। हंसलपुर (गुजरात) संयंत्र स्थित रेलवे साइडिंग से परिचालन मार्च 2023 में शुरू हुआ था, जबकि मानेसर (हरियाणा) रेलवे साइडिंग से यह परिचालन जून 2025 में शुरू हुई। वाहन कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में रेल आधारित कुल वाहन ढुलाई में से 70 प्रतिशत इन दो संयंत्र स्थित रेलवे साइडिंग के माध्यम से की गई है। उसका मध्यम अवधि का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल ढुलाई में रेल हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का है। भाषा

अशोक लीलैंड का केरल ग्रामीण बैंक से समझौता

हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने वाणिज्यिक वाहन खरीदारों को ऋण देने के लिए केरल ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है। अशोक लीलैंड ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना है। इसके तहत उनकी जरूरत और पसंद के अनुरूप आसानी से चुकाए जा सकने वाले वाहन ऋण की सुविधा दी जाएगी। अशोक लीलैंड के एलसीवी कारोबार के प्रमुख विप्लव शाह ने कहा, ''यह रणनीतिक साझेदारी हमारे आधुनिक वाणिज्यिक वाहनों की श्रृंखला तक पहुंच को और बढ़ाएगी। इससे कारोबारियों और संचालकों को अधिक वित्तीय लचीलेपन के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी।'' केरल ग्रामीण बैंक की चेयरपर्सन विमला विजयभास्कर ने कहा कि यह साझेदारी वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भाषा

सेमीकॉन इंडिया-2026

डीपटेक में 3 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धताएं

इंडिया डीप टेक अलायंस (आईडीटीए) में शामिल निवेशकों ने डीप-टेक स्टार्टअप कंपनियों में अब तक 3 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन और सेलेस्टा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अरुण कुमार ने सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान आईडीटीए सदस्यों में सहयोग, आरडीआई फंड और अन्य निवेश फंडों पर उदिशा श्रीवास्तव के साथ बातचीत की। प्रमुख अंशः

आईडीटीए का ऐलान पिछले साल सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में किया गया था। इस एक साल में क्या बदलाव आया?
पिछले साल 8 फंडों ने कुल 1 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। उसके तुरंत बाद हमने 8 फंड और जोड़े और फिर 8 फंड साथ आए। आज संगठन के 30 सदस्य हैं और इनसे अब कुल निवेश प्रतिबद्धताएं 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। पिछले एक साल में आईडीटीए के सदस्य वेंचर कैपिटल फंडों ने लगभग 25 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इस तरह देखें तो यह बहुत अच्छी प्रगति है।

सभी सदस्य, खासतौर से वीसी कैसे सहयोग कर रहे हैं?
हम कई तरीकों से मिलकर काम कर रहे हैं। मसलन, सभी डीप-टेक संस्थापकों को एक साथ लाना होगा, क्योंकि उन्हें ही असली निवेशकों को ढूंढना पड़ता है। हर कोई डीप-टेक की बात कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो धैर्यवान और डीप-टेक में निवेश के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हों। इसलिए, हमारे पास संस्थापकों को निवेशकों से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम हैं।

सेलेस्टा कैपिटल द्वारा 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना कहां तक पहुंची? क्या आपने आरडीआई फंड के तहत आवेदन किया है?
इस मामले में कंपनी अच्छी प्रगति के रास्ते पर हैं। हमने निवेश शुरू कर दिया है। पहला क्लोज कुछ समय पहले किया गया था। आईडीटीए के कई सदस्यों की तरह हमने आरडीआई फंड के तहत दूसरे स्तर के फंड मैनेजर बनने के लिए भी आवेदन किया है।

सरकार आरडीआई के तहत स्टार्टअप को धन दे रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ये स्टार्टअप 50 फीसदी निवेश निजी स्तर पर लाएं। क्या आपने सरकार के साथ कोई साझेदारी की है, ताकि प्रक्रिया सुचारू और तेज हो?
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने कई कंपनियों में सीधे शेयर खरीदे हैं और उम्मीद यह है कि अन्य निवेशक, वेंचर-कैपिटल निवेशक भी इतनी ही रकम उन कंपनियों में लगाएंगे, लेकिन कई कंपनियों को फंड प्राप्त करने में मदद की जरूरत है।

चिप निर्माता साझेदारी पर दें जोरः मिसरी

अक्षत आयुष
नई दिल्ली, 18 सितंबर

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में कहा कि चिप निर्माताओं को किसी एक स्रोत पर निर्भरता से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए साझेदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उनका इशारा दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण और आधुनिक नोड विनिर्माण में चीन की ओर था। विदेश सचिव ने कहा कि सेमीकंडक्टर दुनिया का सबसे अधिक सहयोग वाला उद्योग है। मिसरी ने कहा, 'कोई भी देश अकेले चिप नहीं बना सकता। डिजाइन करने वाले प्रतिभाशाली लोग एक देश में हैं, उपकरण दूसरे देश में, फैब्रिकेशन तीसरे में, कच्चा माल चौथे में और असेंबलिंग पांचवें देश में होती है।

दुनिया का कोई भी अकेला क्षेत्र इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को अकेले नियंत्रित नहीं करता।' विदेश सचिव ने कहा कि अगर कोई देश सीमाओं के भीतर सब कोशिश करेगा तब उसे अधिक लागत, धीमे नवाचार और एक अलग औद्योगिक आधार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए बनेगा प्रिसिजन विनिर्माण संस्थान

शुभम कुमार और अक्षत आयुष
नई दिल्ली, 18 सितंबर

अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

भारत में जल्द ही अपना खुद का प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट (सटीक विनिर्माण संस्थान) होगा। साथ ही, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नया टैलेंट मॉडल तैयार किया जाएगा। यह जानकारी सेमीकॉन इंडिया-2026 में फायरसाइड चैट के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मोबाइल, एरोस्पेस, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए प्रिसिजन तकनीकको सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है। मंत्री ने इन क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने पर बल दिया।

वैष्णव ने कहा, 'एक तरह से, हम हाई स्कूल पास करने वाले किसी युवा को ले सकते हैं... और निश्चित अवधि में उसे अलग-अलग स्तर का कौशल सिखा सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से के अच्छे बी टेक इंजीनियर के बराबर कुशल हों।' केंद्रीय मंत्री ने लगभग पांच स्तर वाले प्रशिक्षण मॉडल (कौशल विकास मॉडल) पर चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा, 'पहले स्तर का कोर्स लगभग 240 घंटे का होगा, दूसरे स्तर का कोर्स उससे बड़ा होगा।' वैष्णव ने यह भी बताया कि सेमीकॉन 2.0 के साथपाठ्यक्रम को और उन्नत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें चिप डिजाइन से हटकर सिस्टम डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'सिस्टम डिजाइन का मतलब होगा कि वह कोर्स पास करने वाले छात्रों की उद्योग में बहुत मांग होगी।'

बाजार में कुशल प्रतिभाओं की भारी मांग है। मंत्री ने कहा कि उद्योग की बढ़ती मांग के कारण आईएसएम 2.0 के तहत 1 लाख टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने विकसित देशों में बढ़ते कर्ज के स्तर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, 'विकसित कहे जाने वाले देशों में जो वैश्विक ऋण बढ़ता गया है, अगरउसे संभाला नहीं गया, तो भावी निवेशों का क्या होगा?' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र की जटिलता को देखते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए दो दशक का रोडमैप तैयार किया है। सेमीकॉन 2.0 से अपने लक्ष्यों को समय-सीमा से पहले प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। इससे पहले सेमीकॉन 1.0 ने अपने 6 साल के लक्ष्य को 4 साल में ही हासिल कर लिया था। सरकार ने हाल में 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है, जो डिजाइन, सामग्री और मशीनें, अतिरिक्त फैब, एडवांस्ड पैकेजिंग क्षमता, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिभा जैसे 6 क्षेत्रों पर आधारित है।

केंद्र सरकार करेगी सुझावों पर अमल

वैष्णव ने यह भी कहा कि माइक्रोन, सीजी सेमी, काइन्स, सुची सेमीकॉन और सीडीआईएल सेमीकंडक्टर्स द्वारा तैयार सेमीकंडक्टर चिप, लागत और गुणवत्ता के मामले में पहले से ही दूसरे देशों से मुकाबला कर रहे हैं। वैष्णव ने कहा, 'हम पहले से ही विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। सेमीकॉन 1.0 ने इसकी नींव रखी थी और इसका दूसरा संस्करण उस नींव पर मजबूत इमारत खड़ी करेगा।'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के दूसरे चरण में 'एस' वक्र का अनुसरण किया जाएगा, जहां सरकार की नीतिगत पहल और कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। सरकार को जापान, सिंगापुर और अन्य देशों की कंपनियों से रचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और वह जल्द ही इन सुझावों को लागू करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव करेगी।

आपूर्ति श्रृंखला में तेजी और मजबूती की मांग

शुभम कुमार
नई दिल्ली,18 सितंबर

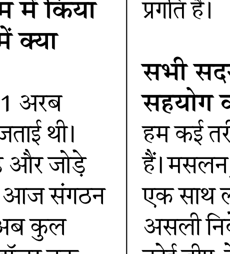

भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। ऐसे में उद्योग के अधिकारियों ने स्थानीय क्षमताओं में कमी की बात को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने सप्लाई चेन में तेज़ी और मजबूती की मांग की है। इस आपूर्ति श्रृंखला का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण हिस्सा औद्योगिक गैसों की उपलब्धता है। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 50 से अधिक अत्यधिक शुद्ध औद्योगिक गैसों की आवश्यकता होती है जो चिप निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। भारत वर्ष 2029 तक अपनी घरेलू जरूरतों के लगभग 70 से 75 प्रतिशत चिप देश में ही डिजाइन करने और उनके निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। लेकिन अभी तक देश का घरेलू उद्योग इन जरूरतों के अनुरूप रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। दिल्ली में सेमीकॉन 2026 में सप्लाई चेन पर आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान आइनॉक्स एअर प्रोडक्ट्स के रणनीति एवं व्यापार विकास प्रमुख दिगंत कुमार सरमा ने कहा, 'फैब स्तर पर बेहद शुद्ध औद्योगिक गैसों की जरूरत होती है।

चिप डिजाइन से आगे बढ़ा सेमीकॉन : विश्वनाथन

उदिशा श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 18 सितंबर

वेंचर कैपिटल फर्म सेलेस्टा कैपिटल के संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर श्रीराम विश्वनाथन ने कहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र चिप डिजाइन से आगे बढ़कर पैकेजिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बौद्धिक संपदा (आईपी) तक विस्तार ले रहा है। सेमीकॉन इंडिया के दूसरे दिन मुख्य भाषण देते हुए विश्वनाथन ने कहा, 'पहले केवल कोर डिजाइन में ही अड़चन थी, लेकिन यह अब पैकेजिंग और अन्य चीजों की ओर चली गई है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के लिए नया अवसर है, जबकि डिजाइन पहले से ही प्रमुख ताकत बनी हुई है।' विश्वनाथन के अनुसार, वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण के साथ-साथ देश के प्रतिभा पूल, बढ़ती घरेलू मांग और सरकारी समर्थन से भारत में व्यापक और मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है।

चिप लाभ देने वाला तीसरा उद्योग बनाः मनोचा

उदिशा श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 18 सितंबर

भू-राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप की बढ़ती मांग के बीच वैश्विक सेमीकंडक्टर तीसरा सबसे अधिक लाभ देने वाला उद्योग बन कर उभरा है। यह बात ग्लोबल इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट ऐंड मैटेरियल्स इंटरनैशनल (सेमी) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनोचा ने कही।

'सेमीकंडक्टर क्षेत्र का भविष्य और वैश्विक विकास एवं उत्पादकता में इसकी भूमिका' विषय पर फायरसाइड चैट के दौरान मनोचा ने कहा, 'लाभप्रदता के मामले में सभी उद्योगों में सेमीकंडक्टर उद्योग अब तीसरे स्थान पर है।

इसके उभरने का कारण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हम सभी को कोविड के दौरान अंदाजा हो गया था कि सेमीकंडक्टर हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं।'

ट्राई ने स्पैम पर कसा शिकंजा, ए2पी कॉल भी नियम दायरे में

गुलवीन औलख
नई दिल्ली,18 सितंबर

भारत के दूरसंचार नियामक ने ऐप या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए आने वाली स्पैम कॉल को रोकने के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई ऐप ऐसी कॉल की जानकारी पहले से नहीं देता है, तो दूरसंचार कंपनियां उस कंपनी से प्रति कॉल अधिकतम 5 पैसे तक शुल्क ले सकती हैं, जहां से कॉल शुरू हुई है। हालांकि, 140, 1600 और 1601 सीरीज के नंबरों से की जाने वाली एप्लिकेशन-टू-पर्सन (ए2पी) कॉल पर टर्मिनेशन शुल्क नहीं लगेगा। इन नंबरों का इस्तेमाल नियामक द्वारा तय व्यावसायिक कॉल और अधिकृत कॉल के लिए किया जाता है।

ए2पी कॉल ऐसी कॉल होती है जो किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या स्वचालित प्रणाली से की जाती है और इसमें कोई व्यक्ति सीधे नंबर डायल नहीं करता। इसमें ऑटो-डायलिंग, रोबोकॉल और पहले से रिकॉर्ड की गई या एआई से बनाई गई आवाज वाली कॉल भी शामिल हैं। ए2पी कॉल करने वाली कंपनियों या संस्थाओं को पहले से अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता को इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि वे किन नंबरों का इस्तेमाल करेंगी।

इस जानकारी में शामिल नहीं किए गए नंबरों से की जाने वाली कॉल को स्पैम माना जाएगा। ट्राई ने कहा कि पहले से जानकारी देना और टर्मिनेशन शुल्क लगाना स्पैम करने वालों और ठगी करने वालों के लिए रोक का काम करेगा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

निविदा आमंत्रण सूचना
(CO: BSD: ARCH: 2026-27: NIT: 05)

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, व्यवसाय सहायता विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, नरीमन पॉइंट, मुंबई, बैंक परिसर में नीचे दिए गए कामों के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी कॉन्ट्रैक्टरों से **टू-बिड प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय) के तहत (सिर्फ़ ऑनलाइन माध्यम से)** ऑफ़र आमंत्रित करता है: **कार्य की प्रकृति:** अधिकारी निवासी संकुल, सेंट पर्ल अपार्टमेंट्स, वसंतदादा पाटील मार्ग, सेक्टर 8बी, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400614 में प्रस्तावित सिविल मरम्मत और संबंधित कार्य **टेंडर डॉक्यूमेंट की उपलब्धता और आगे कोई अपडेट/स्पष्टीकरण आदि (यदि कोई हो):** https://centralbank.abcprocure.com. **प्री-बिड मीटिंग:** कार्य के उपर्युक्त स्थान पर 25.09.2026 को 15:00 बजे **टेंडर जमा करने की अंतिम दिनांक और समय:** 09-10-2026 को 15:00 बजे तक इस एनआईटी से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण/संशोधन/बदलाव/अतिरिक्त जानकारी, समय सीमा में विस्तार आदि, केवल उपर्युक्त पोर्टल https://centralbank.abcprocure.com पर अद्यतन किए जाएंगे। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in या ई-टेंडरिंग पोर्टल पर नियमित रूप से विजिट करें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18-09-2026

सहायक महाप्रबंधक, व्यवसाय सहायता विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

TATA POWER-DDL
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–110009
CIN No. U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट: tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित Sep 19, 2026

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200002006/26-27 Security Services and Security Assistants at Tata Power-DDL for a period of 3 years	68.86 Cr/ 12.5 Lacs	19.09.2026	12.10.2026;1600 Hrs/ 12.10.2026;1730 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website **www.tatapower-ddl.com**→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents

अगले साल तक आएगा भारत में डेंगी का टीका

जापानी कंपनी ताकेदा का 2029 तक डेंगी टीके की उत्पादन क्षमता 10 करोड़ डोज करने का लक्ष्य

सोहिनी दास
मुंबई, 18 सितंबर

जापानी दवा कंपनी ताकेदा फार्मास्युटिकल ने बायोलॉजिकल-ई के साथ अपनी डेंगी टीका क्यूडेंगा की सालाना उत्पादन क्षमता 2029 तक 10 करोड़ डोज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी 2027 की पहली छमाही में भारत की पहली स्वीकृत डेंगी टीका बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। फिलहाल क्यूडेंगा की शुरुआती खुराकों की आपूर्ति ताकेदा के सिंगन संयंत्र से की जाएगी।

ताकेदा की अंतरराष्ट्रीय कारोबार इकाई के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट प्रमुख महेंद्र नायक ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'वर्तमान में हमारे जर्मनी के सिंगन संयंत्र में सालाना लगभग 5 करोड़ टीके बनाने की क्षमता है, जबकि हैदराबाद की बायोलॉजिकल-ई के साथ हमारी साझेदारी से अतिरिक्त 5 करोड़ डोज और मिलने की उम्मीद है।' नायक ने कहा, 'हम बायो-ई के साथ साझेदारी से सालाना 10 करोड़ टीके के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। ताकेदा का लक्ष्य 2029 तक बायोलॉजिकल-ई की वार्षिक क्षमता को 5 करोड़ टीके तक बढ़ाना है।'

पहली स्वीकृत वैक्सीन
- शुरुआती खुराकों की आपूर्ति ताकेदा के जर्मनी के सिंगन संयंत्र से
- जर्मन संयंत्र की वर्तमान में वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 करोड़ खुराक
- 2029 तक भारत में बायोलॉजिकल-ई की क्षमता 5 करोड़ टीकों तक और बढ़ेगी

ताकेदा ने गुरुवार को भारत के निजी बाजार में बच्चों और वयस्कों के टीकाकरण के लिए क्यूडेंगा को बढ़ावा देने एवं वितरित करने के लिए डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ विशेष समझौते का ऐलान किया। ताकेदा के पास सार्वजनिक बाजार के अधिकार, कानूनी स्वामित्व और वैक्सीन की समग्र चिकित्सा एवं ब्रांड निगरानी का अधिकार बरकरार रहेगा।

डॉ. रेड्डीज को भारत में वैक्सीन के लिए आगे बड़ा बाजार दिख रहा है। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के सीईओ (ग्लोबल जेनेरिक्स) एमवी रामन ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि 5 से 7 साल में ही क्यूडेंगा भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

कंपनियों ने अभी तक भारत में क्यूडेंगा की कीमत का खुलासा नहीं किया है। नायक ने कहा कि मूल्य निर्धारण किसी अन्य बाजार के बेंचमार्क पर आधारित होने के बजाय देश के सामर्थ्य स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बीती जुलाई में 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए क्यूडेंगा को विपणन अधिकार प्रदान किया, जिससे यह भारत की पहली स्वीकृत डेंगी वैक्सीन बन गई।

नेस्ले के तीन उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 18 सितंबर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर नेस्ले इंडिया के तीन उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है जिनमें नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1और लैक्टोजेन प्रो 1 शामिल हैं। खाद्य नियामक ने इसकी जानकारी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी।

खाद्य नियामक ने अपने एक पोस्ट में बताया कि उसने ई-कॉमर्स मंचों पर उपलब्ध इन शिशु पोषण उत्पादों और उनकी प्रचार सामग्री की जांच की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने इन तीनों उत्पादों को लेकर कंपनी के खिलाफ तीन अलग-अलग विवाद सुलझाने के मामले दर्ज किए हैं।

एफएसएसएआई ने अपनी पोस्ट में कहा, 'नैन एक्सेल प्रो स्टेज 1 में 5 एचएमओ और व्हे प्रोटीन से जुड़े दावे देखे गए जबकि लैक्टोजेन प्रो 1 में व्हे प्रोटीन के पचने में आसान होने का दावा पाया गया। इन दावों को

लेकर मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले पर नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, 'हमारे सभी उत्पाद लागू नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। संबंधित उत्पादों (नैन एक्सेल प्रो और लैक्टोजेन प्रो) और उनके लेबलों को एफएसएसएआई की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। नोटिस के जवाब में, हमने लेबल पर लिखे बयानों को लेकर अधिकारियों को फिर से अपना विस्तृत जवाब सौंप दिया है। ये विवरण तथ्यात्मक हैं और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हैं।'

बयान में कहा गया कि कंपनी लागू कानूनों के अनुसार सभी नियमों और लेबल घोषणाओं का पालन सुनिश्चित करती है।

प्रवक्ता ने कहा, 'हम उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के एफएसएसएआई के प्रयासों में उसके साथ मिलकर काम करना और सहयोग देना जारी रखेंगे।' नियामक ने यह भी कहा कि ये दोनों उत्पाद शिशु पोषण आहार (एफएसएस) विनियम, 2020 के नियम 4(2) और आईएमएस अधिनियम, 1992 की धारा 3 का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

मुंबई संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता अश्विन ठाकुर खेओरा द्वारा मै. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 022-40275300/40275400
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

ब्रोकर की फंडिंग 1.49 लाख करोड़ रु.

खुशबू तिवारी
मुंबई, 18 सितंबर

मार्जिन बुक में बढ़ोतरी

- वॉल्यूम में गिरावट के बीच ब्रोकरों को मिली राहत
- फरवरी और मार्च में थोड़ी गिरावट के बाद, एमटीएफ में लगातार छठे महीने इजाफा
- एमटीएफ बुक के मामले में आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज सबसे आगे

मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा (एमटीएफ) बुक यानी ब्रोकरों की फंडिंग 15 सितंबर तक रिकॉर्ड 1.49 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। इसमें मासिक आधार पर लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो निवेशकों के लीवरेज बेट्स (उधार लेकर दांव लगाने) की मजबूत मांग का संकेत है। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा करीब 99,000 करोड़ रुपये था।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्जिन बुक में बढ़ोतरी ऐसे समय में ब्रोकरेज फर्मों को सहारा दे रही है जब कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम जून तिमाही के उच्चतम स्तर से नीचे बना हुआ है। एमटीएफ के तहत निवेशकों को ट्रेड वैल्यू का केवल एक हिस्सा पहले चुकाने की सुविधा दी जाती है जबकि बाकी रकम ब्रोकर ब्याज दर पर फाइनैंस करते हैं। फरवरी और मार्च में थोड़ी गिरावट के बाद एमटीएफ में लगातार छठे महीने इजाफा हुआ है। 10 महीने तक बढ़ने के बाद फरवरी में पहली बार ब्रोकर फंडिंग में गिरावट देखी गई थी। यह गिरावट मार्च में भी जारी रही और सावधानी व उतार-चढ़ाव के माहौल में एमटीएफ घटकर 1.05 लाख करोड़ रुपये पर आ गई।

ब्रोकरेज ने कहा कि ऐंजल वन और ग्रो दोनों में एमटीएफ की मजबूत वृद्धि से एक फायदेमंद समायोजन मिलता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2027 के पूरे साल के अनुमान को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार सुधार जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर तिमाही में ऐंजल वन की औसत एमटीएफ बुक में फंडिंग लगभग 6,600 करोड़ रुपये थी, जो इससे एक तिमाही पहले के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत अधिक है और वित्त वर्ष 2027 के लिए कोटक के पूरे साल के अनुमान के करीब है।

इसी तरह, ग्रो की एमटीएफ बुक भी तिमाही आधार पर लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर करीब 4,130 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पूरे साल का अनुमान 5,000 करोड़ रुपये था।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमारा अनुमान है कि साल के बाकी समय में ऑर्डर वृद्धि के लिए ग्रो की दर ऐंजल के समान ही है। यह इस साल अब तक के ऑर्डरों में लगभग 15-20 प्रतिशत वृद्धि है।' यह स्थिति तब है जब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद से खुदरा कारोबारी गतिविधियों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

कोटक ने बताया कि इंडेक्स अनुबंधों के लिए ऑप्शन प्रीमियम, जो जून तिमाही में कम थे और अगस्त में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, में सितंबर में सुधार के संकेत दिखे हैं। हालांकि कुल वॉल्यूम अभी भी साल की शुरुआत के स्तर से नीचे ही है। जीरोधा के 16 साल पूरे होने पर लिखे अपने ब्लॉग में ब्रोकरेज हाउस ने बताया था कि एमटीएफ से अब लगभग 10 प्रतिशत राजस्व आता है, क्योंकि ब्रोकरों को इस पर ब्याज से कमाई होती है। ब्रोकर ने दिसंबर 2024 में एमटीएफ बिजनेस शुरू किया था।

अदालत ने एनएसई और सेबी के बीच समझौते को मंजूरी दी

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 18 सितंबर

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को लंबे समय से चले आ रहे को-लोकेशन विवाद में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बीच हुए निपटान समझौते को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) के फैसले के खिलाफ सेबी की अपील का निपटारा हो गया है।

यह समझौता सेबी द्वारा जुलाई में एनएसई के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद हुआ है जिसमें को-लोकेशन और उससे जुड़े डार्क फाइबर मामले के निपटारे के लिए कुल लगभग 1,492 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश की गई थी।

इस कुल राशि में से एनएसई ने को-लोकेशन सुविधा से जुड़ी सेबी की लंबित अपील को सुलझाने के लिए 1,224 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। इसके अलावा लीज पर ली गई लाइन कनेक्टिविटी के रूप में जाने जाने वाले डार्क फाइबर मामले को निपटाने के लिए अलग से लगभग 268 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का संज्ञान लेते हुए डार्क फाइबर मामले में सेबी की अपील का पहले ही निपटान कर दिया था। मुख्य को-लोकेशन विवाद सेबी के 2019 के एक आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में नियामक ने एनएसई को 1 अप्रैल 2014 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 625 करोड़ रुपये वापस जमा करने का निर्देश दिया था। सेबी का आरोप था कि एनएसई ने अपनी को-लोकेशन सुविधा से काम करने वाले चुनिंदा ब्रोकरों को प्राथमिकता के आधार पर अपने पल-पल के डेटा प्रसार के सर्वरों तक पहुंच दी थी। नियामक के अनुसार इस व्यवस्था के कारण कुछ ब्रोकरों को अनुचित लाभ मिला और उन्होंने भारी मुनाफा कमाया।

एनएसई ने सेबी के इस आदेश को एसएटी में चुनौती दी जिसने सेबी के राशि लौटाने के निर्देश को रद्द कर दिया। इसके बाद सेबी ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया। अब इस समझौते के साथ ही प्रतिभूति न्यायाधिकरण और शीर्ष अदालत में वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई और विवादित आदेश से जुड़े मुकदमे का अंत हो गया है।

अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल में सेबी ने इसी महीने एनएसई के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को हरी झंडी दी है।

एनएसई का आईपीओ दूसरे दिन भरा

भाषा
नई दिल्ली, 18 सितंबर

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) का 22,569 करोड़ रुपये का आईपीओ शुक्रवार को बोली के दूसरे दिन पूरा सबस्क्राइब हो गया। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। बीएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दोपहर दो बजकर 56 मिनट तक एनएसई के आईपीओ में पेश किए गए 8,86,42,911 शेयरों के मुकाबले 8,88,23,000 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं।

पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित हिस्से को 1.32 गुना बोलियां मिलीं, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 1.37 गुना अभिदान मिला। खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा को 66 प्रतिशत बोलियां मिली। यह पेशकश 2024 में आए ह्युंडै मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है। एनएसई ने बुधवार को एंकर निवेशकों से 6,746 करोड़ रुपये जुटाए थे। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), गोल्डमैन सैक्स और फिडेलिटी शामिल हैं। इसके अलावा, सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) और नॉर्वे के नॉर्जेस बैंक के साथ ईस्टस्प्रिंग और एचएसबीसी ग्लोबल ऐसेट मैनेजमेंट ने भी बड़े निवेशकों की बोली में हिस्सा लिया।

आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 12.64 करोड़ तक शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। एनएसई ने आईपीओ के लिए 1,700-1,785 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन 4.2 लाख करोड़ रुपये से 4.42 लाख करोड़ रुपये के बीच होगा। यह निर्गम 21 सितंबर को बंद होगा। एनएसई का शेयर 24 सितंबर को बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है।

एलिवेट कैंपस आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा

एलिवेट कैंपस का 2,100 करोड़ रुपये का आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा। इसके लिए मूल्य दायरा 343-362 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार, यह आईपीओ 25 सितंबर को बंद होगा। शेयर के 30 सितंबर को बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। आईपीओ में पूरी तरह नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है। कंपनी उच्च शिक्षा संस्थानों में परिसर के भीतर छात्र आवास सुविधाओं का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती है। इसके पास के-12 शिक्षा से जुड़ी परिसंपत्तियां भी हैं। एलिवेट कैंपस अपने मंच के जरिये संस्थानों को छात्र आवास, भोजन, सुरक्षा और परिसर संचालन सहित एकीकृत गैर-शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल के-12 संस्थाओं और परिसरों के अधिग्रहण, कर्ज चुकाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। भाषा

वीगालैंड 10 प्रतिशत तेजी के साथ सूचीबद्ध

रियल एस्टेट कंपनी वीगालैंड डेवलपर्स का शेयर अपने 140 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ शुक्रवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने 151 रुपये पर कारोबार शुरू किया जो निर्गम मूल्य से 7.85 प्रतिशत अधिक है। वहीं एनएसई पर यह 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 154 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 700.78 करोड़ रुपये रहा।

एफटीएसई में बदलाव से क्लोजिंग ऑक्शन में कारोबार बढ़ा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 18 सितंबर

एफटीएसई इंडेक्स में बदलाव की वजह से गुरुवार को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कारोबार बढ़कर 16,613 करोड़ रुपये हो गया।

सीएएस शुरू होने के बाद से यह दूसरा सबसे ज्यादा कारोबार रहा। इससे पहले, 31 अगस्त को एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के दौरान रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया गया था। तब सीएएस की इस स्पेशल विंडो में कारोबार बढ़कर 39,718 करोड़ रुपये हो गया था। सीएएस अभी सिर्फ वायदा एवं विकल्प सेगमेंट के शेयरों पर लागू होता है।

वैश्विक सूचकांकों में फेरबदल उन समय-समय पर होने वाले रिव्यू में से एक है, जिनकी वजह से दुनिया भर के पैसिव फंडों को भारत में अपने आवंटन में बदलाव करना पड़ता है। इससे अक्सर दिन के आखिर में ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक और कम समय के लिए तेजी आती है।

उद्योग की नजर इस महीने के आखिर में होने वाली निफ्टी रीबैलेंसिंग पर भी है, जिससे इस गतिविधि में एक और उछाल आ सकती है।

टाटा संस को सूचीबद्ध कराने के समर्थन में बोला शापूरजी समूह

निवेदिता मुखर्जी
नई दिल्ली, 18 सितंबर

शापूरजी मिस्त्री,
चेयरमैन, शापूरजी पलोनजी समूह

टाटा संस में 18 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक शापूरजी पलोनजी समूह ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने का पुरजोर समर्थन किया है।

17 सितंबर को टाटा संस की बोर्ड बैठक में कंपनी की सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने सूचीबद्धता के प्रस्ताव का विरोध किया था लेकिन इसके एक दिन बाद शापूरजी पलोनजी समूह के चेयरमैन शापूरजी मिस्त्री ने आज विस्तृत बयान जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि कंपनी का सूचीबद्ध होना क्यों सही है।

मिस्त्री ने कहा, 'उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत नहीं है। उद्देश्य एक मजबूत टाटा संस्था, मजबूत परोपकारिता, अधिक जवाबदेही, व्यापक साझेदारी और अंततः देश की बेहतर सेवा करना है।' उनका यह बयान टाटा ट्रस्ट्स के रुख से अलग है। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66 फीसदी हिस्सेदारी है।

नोएल टाटा के शापूरजी समूह से पारिवारिक संबंध भी है। उन्होंने दिवंगत पालोनजी मिस्त्री की बेटी से विवाह किया है और वे वर्तमान चेयरमैन शापूरजी मिस्त्री और दिवंगत साइरस मिस्त्री के बहनोई हैं।

गुरुवार की बोर्ड बैठक में नोएल टाटा ने शापूरजी समूह के उस प्रस्ताव को रखा, जिसमें गैर-सूचीबद्धता के जरिये टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के आंशिक विनिवेश के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की बात कही गई थी। मिस्त्री ने कहा, 'मैं भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि यह सिर्फ टाटा संस के लिए ही नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और जिम्मेदार संस्था-निर्माण के उन सिद्धांतों के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण क्षण है, जो राष्ट्रीय महत्त्व के उद्यमों का मार्गदर्शन करता है।'

नोएल ने टाटा संस से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ और बातचीत करने तथा निजी कंपनी के रूप में बने रहने का रास्ता तलाशने के लिए कहा था। उनका कहना था कि 11 सितंबर, 2026 के आरबीआई के आदेश में सूचीबद्धता को अनिवार्य या एकमात्र विकल्प नहीं बताया गया है। गुरुवार देर शाम जारी अपने बयान में उन्होंने कहा, 'मेरी समझ में इसमें यह नहीं कहा गया है कि सूचीबद्धता ही एकमात्र विकल्प है। अभी पर्याप्त गुंजाइश है और बोर्ड को उसका इस्तेमाल करना चाहिए।'

इसके एक दिन बाद मिस्त्री ने कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरी स्पष्टता प्रदान कर दी है। आरबीआई के नियामकीय ढांचे के तहत टाटा संस को उच्च स्तर की एनबीएफसी के रूप में रखा गया है और उसे सूचीबद्ध कराना होगा। आरबीआई द्वारा टाटा संस के पंजीकरण को समाप्त करने का आवेदन खारिज किए जाने और जल्द से जल्द आवश्यक अनुपालन करने का निर्देश देने के बाद आगे की राह स्पष्ट है।'

मिस्त्री ने दोहराया कि टाटा संस की सार्वजनिक सूचीबद्धता केवल वित्तीय या नियामकीय मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह महत्त्वपूर्ण फैसला किसी एक हितधारक की दूसरे पर जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे लोगों और संस्थाओं को एक साथ लाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

टाटा समूह और शापूरजी पलोनजी समूह के बीच दशकों से करीबी कारोबारी संबंध रहे हैं। 2012 में समूह के उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2016 में टाटा ट्रस्ट्स के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा के नेतृत्व में हुए बोर्डरूम विवाद के बाद उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया था।

THIS IS A CORRIGENDUM ADVERTISEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

ANAND SEAMLESS LTD.

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

ANAND SEAMLESS LIMITED

Corporate Identity Number: U27100GJ2005PLC047144

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name "Anand Seamless Tubes Private Limited" on November 25, 2005 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli ("RoC"). Further, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on November 05, 2023 and consequently, the name of our Company was changed from 'Anand Seamless Tubes Private Limited' to 'Anand Seamless Tubes Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre on November 24, 2023. Thereafter, a Fresh Certificate of Incorporation dated December 11, 2023 was issued by the Registrar of Companies, CPC, consequent upon change in the name of the Company as "Anand Seamless Limited". The Corporate Identification Number of our Company is U27100GJ2005PLC047144.

Registered Office: Plot No. 129-A, Ankhol Patiya, Chhatral-Kadi Road, Village Indrad, Mahesana, Kadi, Gujarat, India, 382715
Tel: +91 6357364613 | **E-mail:** cs@anandseamless.com | **Website:** https://www.anandseamless.com/
Contact Person: Kinjal Jain, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: KEDAR MAYANK CHOKSI AND HETA KEDAR CHOKSI

Type	Fresh Issue Size	OFS	Total Issue Size
Fresh Issue	35,44,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each aggregating to ₹2,551.68 lakhs	N.A.	35,44,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each aggregating to ₹2,551.68 lakhs

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 35,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ANAND SEAMLESS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹ 72/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 62/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2,551.68/- LAKHS, THE ISSUE COMPRISES FRESH ISSUE OF 35,44,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹2,551.68 /- LAKHS ("FRESH ISSUE"), OUT OF WHICH 1,77,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 72/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹127.87/- LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,66,400 SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 72/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 2,423.81/- LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.61% AND 28.12%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF ISSUE" BEGINNING ON PAGE 280 OF THIS PROSPECTUS.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM

The Company has filed Prospectus dated September 16, 2026, with the Registrar of Companies, Ahmedabad, in respect of IPO of the Company which is to be opened for subscription on Tuesday, September 22, 2026 and will close on Thursday, September 24, 2026.

Attention of investors is being brought to the chapter ***"Issue Structure"*** staring from page no. 293 of the Prospectus:

1. Page 293 –

Minimum Application Size	**For Other than Individual Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares in multiples of 1,600 Equity Shares such that the Application size exceeds 2 lots. **For Individuals Investors, who applies for minimum application size:** Such number of equity shares where application size is of at least 3,200 Equity Shares
Maximum Application Size	**For Other than Individual Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares in multiples of 1,600 Equity Shares such that the Application Size does not exceed Equity Shares, subject to applicable limits to the Applicant. **For Individuals Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares in multiples of 1,600 Equity Shares so that the Application Value does not exceed ₹ 2,00,000

Shall now read as-

Particulars	Net Issue to Public
Minimum Application Size	**For Other than Individual Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares in multiples of 1,600 Equity Shares such that the Application size exceeds 2 lots and the application value exceeds ₹ 2,00,000. **For Individuals Investors, who applies for minimum application size:** Such number of equity shares where application size is of 3,200 Equity Shares so that the application value exceeds ₹ 2,00,000
Maximum Application Size	**For Other than Individual Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares in multiples of 1,600 Equity Shares such that the Application Size does not exceeds the size of the net issue, subject to applicable limits to the Applicant. **For Individuals Investors, who applies for minimum application size:** Such number of Equity Shares where the application size is of 3,200 Equity Shares so that the Application Value exceeds ₹ 2,00,000

Investors are being hereby informed that said statements stand amended.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the chapter titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus.

Investors are being hereby informed that said statements stand amended.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
AFTERTRADE **AFTERTRADE BROKING PRIVATE LIMITED** **Address:** 206, 2nd Floor, Time Square, Besides Pariseema Building, C. G. Road, Navrangpura, Ahmedabad 380009 **Tel No:** +91 9725009939 **Email:** mb@aftertrade.in **Investors Grievance e-mail:** compliance@aftertrade.in **Website:** www.aftertrade.in **Contact Person:** Mr. Vanesh Panchal **SEBI Registration Number:** INM000013110 **CIN:** U51909DN2016PTC005503	MUFG **MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** **Address:** C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Tel:** +91 8108114949 **Investor grievance e-mail:** anandseamless.smeipo@in.mpms.mufg.com **E-mail:** anandseamless.smeipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Ganesh Shinde **SEBI Registration No.:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	ANAND SEAMLESS LTD. **ANAND SEAMLESS LIMITED** **Kinjal Jain** **Address:** Plot No. 129-A, Ankhol Patiya, Chhatral-Kadi Road, Village Indrad, Mahesana, Kadi, Gujarat, India, 382715. **Tel. No.:** 91 63573 64613 **Email:** cs@anandseamless.com **Website:** www.anandseamless.com Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre- issue or post- issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

Issued by For ANAND SEAMLESS LIMITED
Sd/-
Kedar Mayank Choksi
Chairman and Managing Director

Place: Kadi, Mehsana
Date: September 19, 2026

ANAND SEAMLESS LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 22 of the Prospectus before making any investment decision. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those issues and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaz

कर वसूली में नहीं होगी गिरफ्तारी

वैल्युअर्स और अधिकृत आयकर प्रैक्टिशनर्स के पंजीकरण के लिए समय सीमा 6 महीने बढ़ाई गई

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 18 सितंबर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर बकाया की वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया है। साथ ही नए आयकर अधिनियम, 2025 में वैल्युअर्स और अधिकृत आयकर प्रैक्टिशनर्स को अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।

सीबीडीटी ने 17 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में आयकर नियम, 2026 के नियम 225 में संशोधन किया है, जो कर बकाया की वसूली से संबंधित है। इस संशोधन में गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लेख करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है और दूसरे प्रावधान से 'गिरफ्तारी और हिरासत को छोड़कर' शब्दों को हटा दिया गया है। इसमें नियम 225 के कई अन्य उप-नियमों को भी हटा दिया गया है। नियम 2 से 4, जिसमें नियम 225 भी शामिल है, में संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं।

ग्रांट थॉर्नटन भारत की पार्टनर ऋचा साहनी ने कहा, 'कर वसूली नियमों से गिरफ्तारी और हिरासत के प्रावधानों को हटाना एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। व्यावहारिक रूप से इन नियमों के तहत व्यक्तिगत गिरफ्तारी निर्धारित वसूली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगी, जबकि संपत्तियों की कुर्की और बिक्री और अन्य वसूली तंत्र के माध्यम से कर वसूली जारी रहेगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा पेश किए गए बदलावों के मुताबिक है। इससे संपत्ति पर आधारित वसूली के तरीकों में बदलाव का पता चलता है।'

इसके अलावा सीबीडीटी ने वैल्युअर्स और अधिकृत आयकर प्रैक्टिशनर्स के पंजीकरण के लिए नियम 246 और 256 के तहत समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 30 सितंबर, 2026 की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 कर दिया गया है।

अधिसूचना में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के तहत एक वैल्युअर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र में बदलाव किया गया है। संशोधित फॉर्म में आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जिस संपत्ति वर्ग के लिए पंजीकरण मांगा जा रहा है, शैक्षणिक योग्यता, पूर्व रोजगार और पेशेवर अनुभव का विवरण देना आवश्यक है। वैल्युअर्स को पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकित संपत्तियों या किए गए कार्यों का विवरण भी देना होगा।

इस फॉर्म में संपत्ति के 11 वर्ग हैं, जिसमें अचल संपत्ति, कृषि भूमि, बागान, वन, खदानें और क्वैरी, सिक्योरिटीज, मशीनरी और संयंत्र, आभूषण और कलाकृतियां शामिल हैं। प्रत्येक संपत्ति वर्ग के लिए एक अलग आवेदन आवश्यक है। आवेदन के लिए 10,000 रुपये का शुल्क है, हालांकि धन-कर अधिनियम, 1957 के तहत पहले से पंजीकृत वैल्युअर्स को शुल्क से छूट दी गई है।

सीबीडीटी ने एक अधिकृत आयकर प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र का फॉर्म 171 भी बदला है। संशोधित फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मौजूदा पंजीकरण जैसे विवरण मांगे गए हैं। आवेदकों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे कम से कम एक वर्ष से आयकर अधिकारियों के समक्ष प्रैक्टिस कर रहे हैं।

अधिसूचना में नियम 176 में भी संशोधन किया गया है ताकि कुछ संचारों को 'डिजिटल हस्ताक्षर के साथ' तामील करने की आवश्यकता को 'इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से' तामील करने की आवश्यकता से बदला जा सके। ये बदलाव आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2026 के हिस्से के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

आयकर नियम में किया संशोधन

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 17 सितंबर को जारी अधिसूचना में आयकर नियम, 2026 के नियम 225 में संशोधन किया है
- बकाया कर वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रावधानों को हटा गया

प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ा

खुशबू तिवारी
मुंबई, 18 सितंबर

वित्त वर्ष 2026-27 में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 17 सितंबर, 2026 तक बढ़कर 40,214.36 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 53 प्रतिशत अधिक है।

पिछले साल की समान अवधि में एसटीटी संग्रह 26,305.72 करोड़ रुपये था। यह तेज उछाल केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद अप्रैल से प्रभावी एसटीटी में वृद्धि के कारण आया है।

फ्यूचर्स पर एसटीटी 1 अप्रैल से पहले के 0.02 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर कारोबार मूल्य का 0.05 प्रतिशत हो गया है। ऑप्शंस में प्रीमियम टर्नओवर पर कर को 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस पर शुल्क को आंतरिक मूल्य के 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार ने 2024 के बाद एसटीटी में यह दूसरी वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2026 में कुल एसटीटी संग्रह 57,522 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में 53,296 करोड़ रुपये था।

केंद्रीय बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में एसटीटी से 73,700 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान लगाया था।

डीआर चौकसे फिनसर्व के प्रबंध निदेशक देवेन चौकसे ने कहा, 'इस राजस्व वृद्धि की प्राथमिक वजह डेरिवेटिव लेनदेन पर सरकार की दर वृद्धि है। इस दर परिवर्तन का मतलब है कि सरकार द्वारा ट्रेड किए गए प्रत्येक अनुबंध पर काफी अधिक राजस्व निकाला जाता है। भले ही सेबी (जैसे बड़े अनुबंध आकार और कड़ी पोजिशन सीमा) द्वारा खुदरा सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के इरादे से हाल में नियामक सख्ती की गई है, समग्र बाजार लेनदेन मूल्य अविश्वसनीय रूप से उच्च बना हुआ है।'

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह अब तक 13 प्रतिशत बढ़ा

सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक 13 प्रतिशत बढ़कर 12.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। कॉरपोरेट क्षेत्र से बेहतर अग्रिम कर संग्रह से इसमें वृद्धि हुई।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अग्रिम कर संग्रह 16.18 प्रतिशत बढ़कर करीब 5.22 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र से अग्रिम कर भुगतान 18 प्रतिशत बढ़कर 4.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक और गैर-कॉरपोरेट क्षेत्र (व्यक्तिगत तथा हिंदू अविभाजित परिवार) से अग्रिम कर संग्रह 9.24 प्रतिशत बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार, 17 सितंबर तक कर 'रिफंड' 29.19 प्रतिशत बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 प्रतिशत बढ़कर 14.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 19.48 प्रतिशत बढ़कर करीब 5.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। *भाषा*

बिजली संयंत्रों में कोयला बेहद कम

नंदिनी केसरी
नई दिल्ली, 18 सितंबर

देश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक एक साल पहले के 17 दिनों से घटकर लगभग आधा यानी 9 दिन का रह गया है। यह नवंबर 2023 के बाद का सबसे कम स्तर है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आज यह जानकारी दी। बिजली की मांग में बढ़ोतरी के बीच कोयले से बिजली उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2026 में स्टॉक की मात्रा पिछले साल इसी महीने के 5 करोड़ टन की तुलना में 42 प्रतिशत घटकर 2.9 करोड़ टन रह गई।

क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा कि घरेलू कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्रों में स्टॉक कम होने की समस्या ज्यादा देखी गई। इससे बिजली की ज्यादा मांग और कोयले की खपत के बीच 'समय पर स्टॉक फिर से भरने' की चुनौतियों का पता चलता है।

अप्रैल से अगस्त के बीच ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 39.5 करोड़ टन हो गई। असामान्य रूप से गर्म सीजन और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से कम रहने से बिजली की मांग में 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ। जून और अगस्त के बीच कुल बारिश दीर्घावधि के औसत से 13 प्रतिशत कम रही।

इन पांच महीने के दौरान बिजली उत्पादन सालाना आधार पर लगभग 10.5 प्रतिशत बढ़ा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भी 20.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन चौबीसों घंटे की मांग को पूरा करने के लिए, पर्याप्त ऊर्जा भंडारण की कमी के कारण कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों ने बेस लोड में मदद जारी रखी। देश के 190 ताप विद्युत संयंत्रों में से 51 संयंत्रों में अगस्त में कोयले का स्टॉक बहुत कम था, जबकि एक साल पहले ऐसे संयंत्रों की संख्या 20 थी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'इनमें से ज्यादातर संयंत्र घरेलू कोयले पर निर्भर रहते हैं, जिससे समय पर स्टॉक को फिर से भरने की अहमियत पता चलती है। क्रिसिल ने बताया कि कोयले पर चलने वाले संयंत्रों में स्टॉक का दबाव राजस्थान में 72 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 69 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 60 प्रतिशत था।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक को तब गंभीर स्थिति मानता है, जब यह तय मानक स्तर से 25 प्रतिशत कम हो जाता है। अध्ययन में बताया गया है कि बिहार और झारखंड को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे बड़े राज्यों में कोयले से चलने वाली क्षमता का 20 से 31 प्रतिशत हिस्सा भी इसी तरह प्रभावित हुआ।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक सेहुल भट्ट ने कहा, 'भारत में खदानों पर जमा कोयले का स्टॉक मार्च 2026 की शुरुआत के 15.7 करोड़ के शीर्ष स्तर से घटकर अगस्त 2026 में 7.6 करोड़ टन रह गया, जो ज्यादा स्टॉक स्तर का सामान्य होने को दिखाता है।'

बिजली की मांग बढ़ने और ढुलाई की क्षमता घटने के कारण स्टॉक में आई गिरावट

मूडीज ने देश की वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाया

कृति अंबे
नई दिल्ली, 18 सितंबर

मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अपना अनुमान पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर आज 7 प्रतिशत कर दिया। इसके लिए उम्मीद से बेहतर आर्थिक गतिविधियों और पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए वैश्विक झटकों का सामना करने की क्षमता का हवाला दिया गया। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने आगाह किया है कि लंबे समय तक चलने वाले टकराव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें महंगाई को वित्त वर्ष 27 के लिए 4.8 प्रतिशत के अनुमान से ऊपर ले जा सकती हैं।

मूडीज रेटिंग्स ने समय-समय पर होने वाली अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा, 'पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक झटके के बावजूद अर्थव्यवस्था ने जो मजबूती दिखाई है, उसके कारण हमने वित्त वर्ष 2026-27 (मार्च 2027 में खत्म होने वाले साल) के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।'

रेटिंग एजेंसी का भारत के लिए वृद्धि का यह अनुमान अन्य अधिकांश एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से भी ज्यादा है जिसने 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीने (जनवरी से जून) में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि सालाना आधार पर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई, जबकि 2025 में पूरे साल के लिए यह 7.3 प्रतिशत थी। इस बेहतर प्रदर्शन की वजह निजी खपत, जोरदार निर्धारित पूंजी निर्माण और सेवा क्षेत्र में लगातार बनी हुई मजबूती थी।

रेटिंग एजेंसी ने वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वित्त वर्ष के लिए तिमाही आधार पर जीडीपी वृद्धि के आंकड़े जारी करता है। इसके अनुसार साल 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही (वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही) और अप्रैल-जून तिमाही (वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही) दोनों के लिए जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

मूडीज ने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार खर्च और निजी क्षेत्र के निवेश में संभावित तेजी जोरदार खपत के साथ मिलकर वृद्धि को सहारा दे रहे हैं। इसने भारत की बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ने की क्षमता, मजबूत बाहरी स्थिति और स्थिर घरेलू वित्तीय आधार को भी उन ताकतों के तौर पर बताया जो इसके सॉवरिन क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत बनाती हैं।

प्रबंधन शिक्षा के तौर-तरीकों पर ...

पृष्ठ 1 का शेष

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय बिजनेस स्कूल को केवल अमेरिकी बिजनेस स्कूलों की नकल नहीं करनी चाहिए। उसे अपने सवाल स्वयं पूछने चाहिए। नागेश्वरन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रबंधन की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सोशल मीडिया युवाओं का ध्यान भटका रहा है जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'यह प्रबंधन के छात्रों के लिए एक चेतावनी है। प्रबंधक का सबसे जरूरी औजार स्वच्छ और शांत दिमाग होता है। छात्रों के परिसर पहुंचने से पहले ही उस औजार पर हमला हो रहा है।'

सीईए ने प्रबंधन के छात्रों से यह भी कहा कि वे केवल कंपनी को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी समझें। सीईए ने कहा कि इसके लिए उन्हें भू-राजनीति, ऊर्जा, तकनीकी और राजनीतिक-अर्थव्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। नागेश्वरन ने कहा कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से काम सीखते हुए अनुभव लेने के पारंपरिक तरीकों को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर पर रोजमर्रा के और विश्लेषण से जुड़े कार्यों के दौरान ही कर्मचारी अक्सर यह सीखते थे कि संगठन कैसे फैसले लेते हैं, मॉडल की सीमाएं क्या हैं और पेशेवर समझ कैसे विकसित की जाती है। उन्होंने कहा कि मगर अब समस्या यह है कि एआई कनिष्ठ स्तरों के काम कर रही है।

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आज रोक लगा दी, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147ए को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह मामला कर पुनर्मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए नोटिस जारी करने के अधिकार से जुड़ा था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के पीठ ने भारत सरकार एवं अन्य बनाम भारत इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। *बीएस*

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.9 अरब डॉलर घटा

अनुप्रेक्षा जैन
मुंबई, 18 सितंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.9 अरब डॉलर घटकर 780.8 अरब डॉलर रह गया है। यह 10 हफ्तों की लगातार वृद्धि के बाद पहली बार भंडार में आई गिरावट है।

एक सप्ताह पहले भंडार में 44.9 अरब डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह गिरावट आई है। रिजर्व बैंक की रियायती स्वैप विंडो के तहत विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ने के बाद मुद्रा भंडार एक सप्ताह पहले रिकॉर्ड 785.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।

भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में सप्ताह के दौरान 2.4 अरब डॉलर की कमी आई और यह 645.8 अरब डॉलर रह गया। सोना का भंडार 2.6 अरब डॉलर घटकर 111.2 अरब डॉलर पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 3.9 करोड़ डॉलर की मामूली वृद्धि हुई और यह 18.8 अरब डॉलर हो गया, जबकि आईएमएफ के साथ भारत का रिजर्व 6 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.9 अरब डॉलर हो गया।

भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा

आतिरा वारियर
मुंबई, 18 सितंबर

अगस्त 2026 में भारत का विदेश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले साल के इसी महीने के 3.11 अरब डॉलर की तुलना में 23.3 प्रतिशत बढ़कर 3.8 अरब डॉलर हो गया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 के 5.77 अरब डॉलर की तुलना में इसमें गिरावट आई है।

वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में विदेश में किया जाने वाला यह निवेश इक्विटी, ऋण और गारंटी के रूप में होता है। अगस्त में आउटबाउंड इक्विटी एफडीआई एक साल पहले के 1.06 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 1.14 अरब डॉलर हो गया। यह जुलाई 2026 के 2.06 अरब डॉलर से कम है।

इस दौरान ऋण जुलाई 2026 में गिरकर 46.4 करोड़ डॉलर रह गया, जो 2025 के इसी महीने के 84.5 करोड़ डॉलर से कम है। यह मार्च 2026 के 87.89 करोड़ डॉलर से भी कम है। विदेशी इकाइयों के लिए गारंटी अगस्त में बढ़कर 2.23 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 1.2 अरब डॉलर थी। हालांकि यह जुलाई 2026 के 2.8 अरब डॉलर से कम है।

आंकड़ों के अनुसार सोलर इंडस्ट्रीज ने मॉरीशस स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 79.5 करोड़ डॉलर की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। जिंदल पावर ने अपनी मॉरीशस स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 51.4 करोड़ डॉलर की गारंटी और 74 लाख डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। टाटा कम्युनिकेशंस ने नीदरलैंड्स स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 28.875 करोड़ डॉलर की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। केईसी इंटरनैशनल ने सऊदी अरब स्थित अपने संयुक्त उद्यम के लिए 8.17 करोड़ डॉलर की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत पेट्रोलियम ने नीदरलैंड्स में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 25 करोड़ डॉलर की इक्विटी और 15.45 करोड़ डॉलर की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। सिंधु ट्रेड लिंक्स ने सिंगापुर स्थित अपनी एडवांटेक कोल रिसोर्सेज के लिए 7.239 करोड़ डॉलर की इक्विटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। नजारा टेक्नोलॉजिज ने ब्रिटेन स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 3.38 करोड़ डॉलर की इक्विटी और 5.74 करोड़ डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। इनमोबी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म ने सिंगापुर स्थित अपनी सहायक कंपनी के लिए 1.601 करोड़ डॉलर की इक्विटी देने की प्रतिबद्धता जताई है।

हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजिज ने सिंगापुर स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 2.18 करोड़ डॉलर की इक्विटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। केमकॉ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने भी बहरीन स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 4.349 करोड़ डॉलर की इक्विटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। ओएनजीसी विदेश ने वर्जिन स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए 2.013 करोड़ डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है।

बीएस सूडोकू 5697

2			6		1	4	8	5
7	1			5				
			2			3	7	
4		1	5	6	2			9
6		9		3				2
	3		9					
	4				5		9	
		5	8	4		6		
3	8					2		

परिणाम संख्या 5696

9	1	4	8	3	2	7	6	5
7	5	6	1	9	4	3	8	2
8	2	3	7	5	6	9	4	1
5	6	2	9	8	7	4	1	3
1	7	9	5	4	3	6	2	8
4	3	8	2	6	1	5	9	7
3	4	1	6	2	5	8	7	9
2	8	5	4	7	9	1	3	6
6	9	7	3	1	8	2	5	4

कैसे खेलें ?
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल
★★★★★

एमएसएमई मंत्रालय की ब्लिंकइट संग साझेदारी

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 18 सितंबर

सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट के साथ साझेदारी की है। इसका मकसद सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बाजार की पहुंच बढ़ाना है। इस पहल को अभी बेंगलूरु में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है।

इस साझेदारी के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को ब्लिंकइट ऐप पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे कारीगरों को पारंपरिक बाजारों से हटकर और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जोमैटो और ब्लिंकइट को चलाने वाली कंपनी ईटर्नल लिमिटेड ने विज्ञप्ति में कहा कि इस प्रायोगिक परियोजना का विस्तार दूसरे शहरों में भी किए जाने की उम्मीद है।

इस सूची में पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद शामिल होंगे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, गुड़िया, खिलौने, सजावटी सामान तथा इस योजना का लाभ उठाने वाले कारीगरों द्वारा निर्मित सीधे हासिल की गई वस्तुएं।

पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी

इस पहल का मकसद कारीगरों को डिजिटल कॉमर्स की परिचालनगत जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करना भी है। ईटर्नल के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनबोर्डिंग और ऑर्डर पूरा करने के साथ-साथ पैकेजिंग और खेप भेजने से जुड़े तरीकों के बारे में भी लाभार्थियों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक की मदद उपलब्ध कराती है। इसमें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन में मदद भी शामिल है।

सरकार ई-कॉमर्स और अन्य संस्थागत मार्गों के जरिये इस योजना के बाजार-लिंकेज वाले हिस्से का विस्तार कर रही है। एमएसएमई मंत्रालय ने इससे पहले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), फैबइंडिया और मीशो जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिये ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता की सुविधा प्रदान की है। साथ ही लाभार्थियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर भी लाया गया है।

मंत्रालय के अनुसार पीएम विश्वकर्मा के तहत 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से लगभग 24.5 लाख को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। 18.15 लाख से अधिक आधुनिक टूलकिट का भी वितरण किया जा चुका।

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 183

सुनियोजित आवास जरूरी

दिल्ली के सत्य निकेतन में हाल ही में एक इमारत गिरने से छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई, जिससे विद्यार्थियों के लिए आवास का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। भारत में विद्यार्थियों के लिए सुनियोजित आवास व्यवस्था अभी भी सीमित है। एक उद्योग आकलन के अनुसार, पेशेवर रूप से प्रबंधित आवास नामांकित विद्यार्थियों में से 0.5 फीसदी से भी कम को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा अमेरिका में 13-15 फीसदी और ब्रिटेन में 17-19 फीसदी था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे-जैसे अधिक विद्यार्थी अपने घर से दूर दिल्ली जैसे शिक्षा केंद्रों में जा रहे हैं, उपयुक्त आवास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। एक उद्योग अध्ययन के अनुसार, 2018-19 में राष्ट्रीय स्तर पर 90.8 लाख प्रवासी विद्यार्थी थे। इसमें यह भी पाया गया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के 7,45,000 विद्यार्थियों में से 50 फीसदी इस क्षेत्र के बाहर से थे, जिससे पेशेवर रूप से प्रबंधित अतिरिक्त 2,50,000 बिस्तरों की मांग का संकेत मिलता है। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, फिर भी ये छात्रावास की मांग के अधिक व्यवस्थित आकलन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

समस्या केवल छात्रावासों की कमी नहीं है। यह संस्थानों की अपर्याप्त क्षमता को दर्शाती है, जिसके कारण विद्यार्थी महंगे, भीड़भाड़ वाले और अनियमित निजी आवासों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। स्पष्ट रूप से, विश्वविद्यालयों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें आवास की मांग का वार्षिक ऑडिट करने के अलावा बाहरी विद्यार्थियों की संख्या, छात्रावास के आवेदनों एवं अस्वीकृतियों की संख्या, और किराये के आवास पर निर्भर विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करनी चाहिए। इस तरह के आंकड़े उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां कमी सबसे अधिक है और संस्थानों को वास्तविक मांग के आधार पर क्षमता की योजना बनाने में सक्षम बनाएंगे।

इसलिए, आपूर्ति संबंधी प्रतिक्रिया की शुरुआत विश्वविद्यालयों से होनी चाहिए। यह समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में विशेष रूप से दिखाई देती है, जहां हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 2,50,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में केवल 7,000 बिस्तर उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार की 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने की योजना एक उपयोगी कदम होगा, लेकिन स्वीकृत परियोजनाओं में लंबे समय तक देरी होने पर इसका कोई खास महत्त्व नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, डीयू में एक छात्रावास परियोजना निर्माण शुरू होने से पहले ही 31 महीने विलंबित हो चुकी थी। इसलिए, विश्वविद्यालयों को स्वीकृत छात्रावास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और कम उपयोग वाली संस्थागत भूमि का अधिक कुशल उपयोग करना चाहिए। जहां छात्रावास बनाना आर्थिक या भौतिक रूप से कठिन है, वहां संस्थान मान्यता प्राप्त निजी छात्रावास संचालकों के साथ साझेदारी कर सकते हैं और परिसर के बाहर सुरक्षित आवासों की सत्यापित सूचियां बनाकर रख सकते हैं। अन्य देशों के उदाहरण उपयोगी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्रदाताओं की यह औपचारिक ज़िम्मेदारी है कि वे उन रहने की जगहों का ध्यान रखें जिनकी वे मालिक हैं, जिन्हें वे चलाती हैं, जिनका वे प्रबंधन करती हैं या जिनसे वे जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन में 2025 आवास संहिता में सुरक्षा, संरक्षा, स्थिरता और छात्र कल्याण को शामिल किया गया है।

इस बीच, सरकार को निजी बाजार को भी विनियमित करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार का पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा, जो पीजी प्रतिष्ठानों को एक नियामक ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है, सही दिशा में एक कदम है। रिपोर्टों के अनुसार, मसौदा विधेयक पीजी के लिए सामान्य मानक स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें अग्नि और संरचनात्मक सुरक्षा, स्वच्छता, अधिकतम अधिभोग और किराये पर सीमा, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण को आवधिक निरीक्षणों से भी जोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली का प्रस्तावित जीओवीपीजी पोर्टल, जिसमें पंजीकरण, उपलब्ध कमरे और किराये की जानकारी, सुरक्षा दस्तावेज और शिकायत निवारण तंत्र की परिकल्पना की गई है, एक उपयोगी मॉडल प्रदान कर सकता है। अंततः,विद्यार्थियों के आवास को शैक्षिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बनना चाहिए। बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा, संस्थागत जवाबदेही और विश्वसनीय विनियमन उच्च शिक्षा के विस्तार को सुरक्षित और समावेशी बना सकते हैं।

बिनय सिन्हा

निर्यात पर केंद्रित हो पीएलआई का ध्यान

पीएलआई सब्सिडी को एक निश्चित समय के बाद समाप्त करना जरूरी है। विजेता चुनने के बजाय व्यापक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बता रहे हैं अजय छिब्बर

औद्योगिक नीति फिर से चर्चा में है। दुनिया भर के देश विशेष उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के नीतिगत उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास की व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों में औद्योगिक नीति दुनिया भर में लगातार प्रभावी रही है। खासकर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अपेक्षाकृत समृद्ध देशों में।

औद्योगिक नीति (आईपी) के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले सरकारी हस्तक्षेप भी 2010 के दशक के करीब 5 फीसदी से बढ़कर औसतन 40 फीसदी हो गए हैं। आईपी में अब केवल उद्योग ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र भी आते हैं। पहले यह नीति आमतौर पर बड़े उपक्रमों पर केंद्रित रहती थी लेकिन आज इसमें छोटे और मझोले उपक्रम भी आते हैं। इन दिनों इसी की चर्चा है।

औद्योगिक नीति पर हालिया अध्ययनों में कहा गया है कि राज्य की क्षमता और निजी क्षेत्र के साथ इसका रिश्ता दोनों औद्योगिक नीति की कामयाबी के लिए जरूरी हैं। अगर कोई देश बिना पर्याप्त क्षमता के बहुत कुछ करने का प्रयास करता है तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। सरकार की किसी भी स्तर की क्षमता के लिए गतिविधियों का भी एक स्तर होता है। कर राजस्व के लिए वह लाफर कर्व की तरह होता है जहां कर बढ़ने के साथ राजस्व बढ़ता है लेकिन एक सीमा तक। अगर कर दर बहुत अधिक हो तो राजस्व में कमी आती है। इसी प्रकार अगर राज्य किसी भी स्तर की क्षमता के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की कोशिश करता है तो इसका प्रभाव शुरू में तो बढ़ता है लेकिन बाद में उसमें गिरावट आती है। राज्य की हर क्षमता में हस्तक्षेप की एक सीमा होती है। चूंकि इसका कोई नाम नहीं है इसलिए मैं इसे राज्य के हस्तक्षेप का 'छिब्बर कर्व' कह रहा हूं। जब राज्य की भूमिका अत्यधिक विस्तृत हो जाती है, तो काम को कम करना यानी ए से बी की ओर जाना सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करेगा। समय के साथ जैसे-जैसे राज्य की क्षमता बढ़ती है, राज्य की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है और बी से सी की ओर जा सकता है।

सरकारी कार्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेणी 1 में हमारे पास रक्षा, कानून और व्यवस्था, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे न्यूनतम कार्य आते हैं। कई विकासशील देश इन न्यूनतम कार्यों को भी कुशलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ होते हैं। अगला स्तर श्रेणी 2, मध्यवर्ती कार्यों का है, जैसे शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शोध और विकास को प्रोत्साहन देना, वित्तीय और उपयोगिता विनियमन, और सामाजिक सुरक्षा या बीमा की व्यवस्था। इनमें से कुछ गतिविधियां जैसे शोध और विकास को प्रोत्साहित करना, कभी-कभी औद्योगिक नीति का हल्का संस्करण भी कहा जाता है। अंत में, श्रेणी 3 में निजी गतिविधियों के समन्वय में सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका आती है। जैसे बाजारों को बढ़ावा देना और क्लस्टर पहलों का समर्थन करना। ये अधिक सक्रिय कार्य पारंपरिक रूप से औद्योगिक नीति माने जाते रहे हैं।

यदि कोई देश श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं जैसे बुनियादी स्वास्थ्य आदि प्रदान करने में असमर्थ है, शिक्षा में अपर्याप्त निवेश कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण के उपायों को लागू करने में विफल है, या नागरिकों को उचित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो वह औद्योगिक नीति के तहत अधिक सक्रिय नीतियों के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं माना जा सकता।

कमजोर क्षमताओं वाले राज्यों को अधिक सक्रिय औद्योगिक नीतियों की ओर बढ़ने से पहले श्रेणी 1 और 2 के तहत आने वाले बुनियादी और मध्यवर्ती कार्यों को पूरा करना चाहिए। वे उद्योगों को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपेक्षाकृत सरल उपाय अपनाने चाहिए। जैसे बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था, कर प्रोत्साहनों के जरिये शोध एवं विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक पार्कों के लिए सहायता उपलब्ध कराना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। हालांकि उन्हें समर्थन के लिए अपनी पसंद के उद्योगों या कंपनियों को चुनने जैसी अधिक सक्रिय औद्योगिक नीति में नहीं पड़ना चाहिए।

सफल औद्योगिक नीति की कुंजी यह तय करना है कि औद्योगिक नीति के लाभ पाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को किस पैमाने से मापा जाएगा। पूर्वी एशिया के सफल देशों खासकर दक्षिण कोरिया और ताइवान ने औद्योगिक नीति के तहत काफी अलग-अलग उपाय अपनाये और विभिन्न प्रकार की कंपनियों को लक्षित किया। दक्षिण कोरिया में मुख्यतः बड़े उद्योगों को सहारा दिया गया जबकि ताइवान ने उन उद्योगों को सहारा दिया जहां लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम प्रमुख थे।

लेकिन दोनों ही मामलों में औद्योगिक नीति इसलिए सफल रही क्योंकि प्रदर्शन का पैमाना निर्यात था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि औद्योगिक नीति का सहारा पाने वाली कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों। इसके अलावा औद्योगिक नीति के लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं थे बल्कि पूरे उद्योग को व्यापक रूप से उपलब्ध कराए गए थे।

भारत औद्योगिक नीति के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं है क्योंकि वह अभी राज्य के बुनियादी कार्यों, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, को भी पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है और राज्य की क्षमता से जुड़े सूचकांकों में उसका प्रदर्शन कमजोर है। खासकर दूरसंचार क्षेत्र में नियामकीय कब्जे के भी प्रमाण मिले हैं।

भारत ने 1950 से 1990 के दौर में भी औद्योगिक नीति अपनाने की कोशिश की थी। उस समय आयात प्रतिस्थापन और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जरिए इसे लागू किया गया। लेकिन औद्योगिक नीति का वह दौर बुरी तरह विफल रहा।

इसके बावजूद भारत ने अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए फिर औद्योगिक नीति का रास्ता अपनाया है। इसके तहत 14 उद्योगों को सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि पीएलआई के तहत मिलने वाली सब्सिडी निर्यात प्रदर्शन के बजाय उत्पादन और बिक्री में हुई अतिरिक्त वृद्धि से जुड़ी है। अब तक पीएलआई योजना ने आईफोन असेंबली और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में सफलता दिखाई है जहां लाभ निर्यात के जरिए हासिल हुए हैं। बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और फार्मास्युटिकल्स ने वित्त वर्ष 2026 तक वितरित की गई कुल पीएलआई प्रोत्साहन राशि का 73 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जबकि इनको सब्सिडी की जरूरत तक नहीं है।

आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, एसीसी बैटरी और सोलर पीवी मॉड्यूल जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन का वितरण सीमित रहा है। इनमें से कुछ उद्योगों में लक्ष्य निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि आयात का प्रतिस्थापन है। ऐसे में यह आकलन करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कि यह नीति सफल होगी या नहीं और इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी।

ये उद्योग केवल सब्सिडी की मांग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि और अधिक आयात संरक्षण की मांग भी करेंगे। उम्मीद है कि भारत जिन मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, उनकी वजह से ऐसी मांगों को सीमित रखने में मदद मिलेगी।

नुकसान को सीमित करने के लिए पीएलआई सब्सिडी को निर्यात से जोड़ना और एक निश्चित समय के बाद उन्हें पूरी तरह समाप्त करना जरूरी है। इसके बजाय व्यापक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उद्योग समग्र रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बने और औद्योगिक नीति की सब्सिडी पर निर्भर न रहे।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान में अतिथि विद्वान हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

डॉलर की बाढ़ के बाद महंगे विकल्प

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) या एफसीएनआर(बी) योजना को रुपये के सफल बचाव के रूप में सराहा गया है। इसने डॉलर को आकर्षित किया और रुपये के अनियंत्रित अवमूल्यन को रोका। लेकिन रुपये को स्थिर करना तो बस शुरुआत थी। बड़े पैमाने के इन डॉलर जमा से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तत्काल घरेलू तरलता की समस्या खड़ी कर दी है। भविष्य में विनिमय दर में गिरावट या पुनर्भुगतान के दबाव के उत्पन्न होने से पहले ही इस योजना के कारण लागतें बढ़ गई हैं।

इस विशेष सुविधा के तहत 136.4 अरब डॉलर जुटाए गए, जिसमें एफसीएनआर (बी) जमा के माध्यम से 127.2 अरब डॉलर शामिल हैं। चूंकि आरबीआई ने अधिकांश विदेशी मुद्रा को अवशोषित कर लिया और बदले में रुपये जारी किए, इसलिए बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। अब आरबीआई को इस धन का क्या करना चाहिए? हर विकल्प महंगा है।

पहला विकल्प यह है कि डॉलर को बाजार में आने दिया जाए और रुपये को मजबूत होने दिया जाए। वर्ष 2013 में यह उपयुक्त था, जब भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.7 फीसदी था, मुद्रास्फीति चरम पर थी और अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी। रुपये को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। एफसीएनआर (बी) और संबंधित विंडो के माध्यम से लगभग 34 अरब डॉलर आकर्षित हुए और इससे रुपये में गिरावट को रोकने में मदद मिली।

वर्तमान घटनाक्रम अलग है। व्यापारिक साझेदारों के एक व्यापक समूह के मुकाबले रुपये का वास्तविक अवमूल्यन लगभग 10 फीसदी था, जो 2013 में हुई इसी तरह की गिरावट के आधे से भी कम है। भारत के पास पर्याप्त भंडार, स्वस्थ वृद्धि दर, विदेश से मजबूत धन प्रेषण और लगभग शून्य चालू खाता घाटा है।

बाजार में पूरी तरह से पैसा आने देने से रुपया 90 रुपये से नीचे जा सकता था। इससे निर्यात को नुकसान होता, आयात सस्ता हो जाता और घरेलू विनिर्माण कमजोर हो जाता। साथ ही, इससे उतने ही रुपये के बदले अधिक डॉलर मिलने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को निकलने में आसानी होती। इसलिए, बाजार में आए अधिकांश पैसे को अवशोषित करना उचित था, लेकिन इससे विनिमय दर की समस्या तरलता की समस्या में बदल गई।

प्रसन्ना तंत्री

दूसरा विकल्प यह है कि बैंकों के पास भंडार छोड़ दिया जाए ताकि वे ज्यादा ऋण दे सकें। लेकिन मुद्रा भंडार उच्च ताकत वाला धन होता है। जब बैंक उधार देते हैं, तो वे जमा राशि सृजित करते हैं। इसलिए, ऋण और व्यापक मुद्रा मूल निवेश से कई गुना बढ़ सकती है, जिससे कुछ समय बाद मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। इससे भी गहरा खतरा है। नीति निर्माताओं को विरल आचार्य, राहुल चौहान, रघुराम राजन और साशा स्टीफन के शोध पत्र, 'तरलता निर्भरताः केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट को कम करना एक कठिन कार्य क्यों है' को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। लेखकों ने दिखाया है कि जमा, क्रेडिट लाइन और अन्य तरलता प्रतिबद्धताओं का निर्माण करके प्रचुर भंडार के आधार पर बैंक अपनी बैलेंस शीट को पुनर्गठित करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा भंडार निकालने पर भी ये दायित्व बने रहते हैं। तब बैंक तरलता का संचय कर सकते हैं, ऋण देना कम कर सकते हैं, प्रतिभूतियां बेच सकते हैं या अल्पकालिक वित्तपोषण के लिए हाथ-पैर मार सकते हैं। केंद्रीय बैंक को फिर से भंडार डालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह 'रिजर्व रैचेट' प्रभाव है। यानी रिजर्व बनाना आसान है। बैंकों के उन पर निर्भर हो जाने के बाद उन्हें हटाना विघटनकारी हो सकता है। भारत को पहले मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है और फिर पता चलता है कि इसे नियंत्रित करना वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है।

तीसरा विकल्प नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को बढ़ाना है। इससे बैंकों को आरबीआई के पास बिना ब्याज के अतिरिक्त धनराशि रखने के लिए बाध्य करके भंडार को स्थिर किया जा सकेगा। इसका बोझ बड़ा और असमान होगा। एफसीएनआर(बी) जमा राशि बढ़ाने वाले बैंकों को जमाकर्ताओं को 6 से 7 फीसदी तक ब्याज देना होगा। यदि संबंधित राशि सीआरआर में फंसी रहती है, तो उन्हें कोई लाभ नहीं होता। पूरे सिस्टम में ब्याज दर बढ़ाने से उन बैंकों को भी नुकसान होगा जिन्होंने इन जमाओं को जुटाया नहीं है।

चौथा विकल्प यह है कि आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों को बेच दे। इससे कोई नया ऋण सृजित नहीं होगा। मौजूदा ऋण आरबीआई से बैंकों को हस्तांतरित हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बिक्री से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, आरबीआई की आय घट सकती है और सामान्य मौद्रिक संचालन के लिए आवश्यक प्रतिभूतियां समाप्त हो सकती हैं।

अगर नए सामान्य सरकारी बॉन्ड से मिली रकम खर्च कर दी जाए, तो वे लिक्विडिटी को स्थायी रूप से अवशोषित नहीं करेंगे, क्योंकि वह पैसा बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जाएगा। बैंक प्रभावी रूप से विदेश से उधार लेंगे, डॉलर को रुपये में बदलेंगे और सरकार को वित्त पोषित करेंगे, जबकि आरबीआई भविष्य की विनिमय दर की गारंटी देगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से सॉवरिन विदेशी मुद्रा उधार लेने जैसा प्रतीत होता है।

अंतिम विकल्प बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) है। इसके तहत, सरकार विशेष बॉन्ड जारी करती है और उससे प्राप्त धनराशि को रख लेती है। इस धनराशि को खर्च नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह बॉन्ड की अवधि तक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहती है। तीन वर्षों के लिए 6 फीसदी की दर से 7 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को अवशोषित करने के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ से 1.45 लाख करोड़ रुपये के सकल ब्याज भुगतान की आवश्यकता होगी। अंततः करदाताओं को उच्च ब्याज या कम राजकोषीय संसाधनों के माध्यम से यह लागत वहन करनी पड़ेगी।

लेकिन मेरे विचार में, एमएसएस सबसे कम नुकसानदायक विकल्प है। यह लागत को स्पष्ट करती है, बड़े पैमाने पर मौद्रिक विस्तार को रोकती है और बैंकों पर पूरा बोझ नहीं डालती। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह बैंकिंग प्रणाली को ऐसे भंडार पर निर्भर होने से बचाती है जिन्हें आरबीआई को बाद में निकालने में कठिनाई हो सकती है। एफसीएनआर(बी) योजना से रुपये में स्थिरता तो आई होगी, लेकिन इससे लागत की समस्या खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ स्थानांतरित हुई। भारत को अब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रास्फीति, बैंकों के घाटे, जनता के लिए अप्रत्यक्ष जोखिम और एक महंगे अवशोषण कार्यक्रम में से किसी एक को चुनना होगा। इस स्थिति में पहुंचने के बाद, मुद्रास्फीति और आरक्षित भंडार में कटौती के जोखिम से बचने के लिए एमएसएस का प्रत्यक्ष लागत वहन करना बेहतर है।

(लेखक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते हैं)

आपका पक्ष

एमडीआर शुल्क का बोझ किस पर पड़ेगा?

यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उसने डिजिटल भुगतान को सरल, त्वरित और लगभग बिना किसी प्रत्यक्ष शुल्क के आम आदमी की आदत बना दिया। ऐसे में 15 अक्टूबर, 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी लेनदेन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू होने के बाद सवाल यह है कि इसका बोझ अंततः किस पर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक से यह शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और बैंकों को इसे रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसी उद्देश्य से सरकार का भुगतान एग्रीगेटरों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है, जिसमें कारोबारी एमडीआर को ग्राहक के बिल में जोड़ न सकें। सरकार इसकी निगरानी भी करेगी और भुगतान एग्रीगेटरों के साथ बातचीत के जरिये अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी भी की जा रही है। यहां एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नया एमडीआर सभी यूपीआई भुगतानों पर नहीं है। 2,000 रुपये तक के पर्सन टु मर्चेंट लेनदेन और पात्र छोटे कारोबारियों के भुगतान इससे बाहर हैं तथा लगभग 96 फीसदी पर्सन टु मर्चेंट लेनदेन अप्रभावित रहने की बात सरकार ने कही है। पर्सन टु पर्सन भुगतान भी पूरी तरह मुक्त रहेंगे। एमडीआर पर जीएसटी का प्रश्न थोड़ा अलग है। एमडीआर पर जीएसटी लागू होगा और कारोबारी उपलब्ध नियमों के तहत उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे। साथ ही इस विषय से जुड़े किसी बदलाव पर जीएसटी परिषद विचार कर सकती है। दरअसल असली चुनौती शुल्क लगाने से अधिक उसकी पारदर्शी व निष्पक्ष वसूली की है। यूपीआई की विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब कारोबारी अपनी लागत का हिसाब स्वयं करें और ग्राहक से छिपे हुए शुल्क के रूप में उसकी भरपाई न करें।

इशरत अली कादरी

यूपीआई से कारोबारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क 15 अक्टूबर से लगाने की घोषणा की गई है

सरकारी अस्पतालों की दशा में हो सुधार

देश में आज भी कई सरकारी अस्पताल बदहाल हैं। कुछ शहरों की आबादी लाखों में है, लेकिन वहां सिविल अस्पताल एक ही है। गांवों में दिल की बीमारी या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को कई किलोमीटर दूर शहर के निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। कई बार तो रोगी अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसी के साथ सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं। सरकार की तरफ से कई योजनाएं हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए बनाई जाती है, परंतु वे सुविधाएं मात्र सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाती है। कारखानों या कंपनियों में काम करने वालो के लिए सरकार की तरफ से कर्मचारियों का कुछ अंशदान तनख्वाह से काट कर हर बीमारी का इलाज ईएसआईसी के अस्पतालों में मुफ्त कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन ईएसआईसी की बहुत सी डिस्पेंसरियों में न तो पूरा स्टाफ पूरा होता है और न पूरी दवाइयां। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारत समेत छह देशों का ध्वजारोहण समारोह शुक्रवार को एक घंटे विलंब से शुरू हुआ। एशियाई ओलिंपिक परिषद और स्थानीय आयोजन समिति के बीच गलतफहमी इस विलंब का कारण रही। भारत के अभियान प्रमुख सहदेव यादव और चार अभियान उप प्रमुख अचंत शरत कमल, लिजो डेविड टी, अलकनंदा अशोक और अंजलि भागवत गार्डन पियर पर समारोह के लिए मौजूद थे। खेलमंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा भी समारोह स्थल पर थे।

खबरों में

■ एवलॉन टेक्नॉलजीज

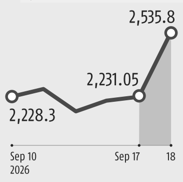

Top gainer amongst A-group of companies

₹ 2,231.1 PREVIOUS CLOSE
₹ 2,535.8 CLOSE
▲ 13.7% UP

■ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस

Trading volume surged 39 times over 2-week average on BSE

₹ 255.4 PREVIOUS CLOSE
₹ 239.1 CLOSE
▼ 6.4% DOWN

■ एमक्योर फार्मास्युटिकल्स

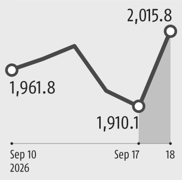

Hits new high since listing, Up 48 per cent year to date

₹ 1,910.1 PREVIOUS CLOSE
₹ 2,015.8 CLOSE
▲ 5.5% UP

* OVER PREVIOUS CLOSE

आज का अहम शेयर

■ अपार इंडस्ट्रीज

Hit new all-time high of ₹19,054, price rallies 96 per cent in last 6 months

निफ्टी 50

Company	Close (₹) 18 Sep '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std	Company	Close (₹) 18 Sep '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std
Adani Enter	3020.0	3.3	0.9	158.8	122.9	JSW Steel	1275.6	1.8	1.5	31.9	41.4
Adani Ports	1824.0	4.9	1.3	31.6	152.1	Kotak Mah Bank	412.5	-1.0	2.7	20.5	27.6
Apollo Hosp	8944.5	2.0	0.8	61.1	81.4	L & T	3885.0	1.3	4.8	30.0	39.8
Asian Paints	2451.3	-0.1	1.0	48.2	49.6	Mah & Mah	3052.0	-0.8	2.8	19.7	23.2
Axis Bank	1257.0	1.4	3.2	14.1	15.2	Maruti Suzuki	12103.0	-1.9	1.4	26.5	27.1
Bajaj Auto	11414.0	-0.7	1.3	26.6	29.2	Max Health	1049.3	1.2	0.7	68.2	139.7
Bajaj Fin	1040.3	2.5	2.6	31.6	35.6	Nestle India	1372.4	0.1	0.9	71.4	70.5
Bajaj Finsrv	1852.5	-0.4	1.1	28.5	133.8	NTPC	323.7	-1.8	1.4	11.3	13.2
Bharat Elctn	393.3	-0.5	1.3	46.8	46.9	ONGC	232.8	0.2	1.1	6.7	7.0
Bharti Airtel	1893.3	3.1	5.3	37.1	68.6	Power Grid	270.3	2.5	1.1	15.8	16.0
Cipla	1394.5	1.3	0.7	31.5	34.4	Reliance Ind	1226.4	-1.4	7.5	22.2	42.3
Coal India	409.9	-1.9	0.9	8.1	13.4	SBI	996.2	0.8	3.7	11.0	11.7
Dr Reddys	1185.0	0.9	0.6	30.7	149.1	SBI Life Ins	1731.0	-2.0	0.7	-	66.8
Eicher Motor	7516.0	0.3	0.9	35.5	39.1	Shriram Finance	1010.0	1.5	1.7	21.0	21.1
Eternal	326.9	1.4	2.8	726.3	119.7	Sun Pharma	1837.3	-1.6	1.8	34.9	138.5
Grasim Ind	3209.2	1.1	1.1	37.3	259.2	Tata Consumer P	996.0	-1.7	0.6	59.7	59.8
HCL Techno	1249.3	-0.7	1.2	18.7	18.6	Tata Motors PV	303.8	-3.4	0.6	122.5	177.7
HDFC Bank	731.0	2.5	10.0	14.3	14.9	Tata Steel	185.5	-0.9	1.4	19.6	12.9
HDFC Std Life	551.0	-1.1	0.5	60.6	60.6	TCS	2105.0	-3.9	1.9	14.2	14.1
Hindalco	986.5	0.6	1.3	10.6	17.1	Tech Mahindra	1537.1	-1.5	0.9	28.3	37.7
HUL	1932.0	-0.5	1.5	41.2	42.0	Titan Company	4798.5	-0.9	1.8	73.0	79.4
ICICI Bank	1338.9	-0.6	8.6	17.1	18.4	Trent	2824.0	1.3	0.8	82.4	71.8
Infosys	1051.4	-0.7	3.3	13.7	13.7	UltraTech	11014.0	2.3	1.2	37.6	42.4
InterGlobe Avia	4920.0	1.5	1.0	-	-	Wipro	166.8	0.3	0.4	12.5	14.6
ITC	262.3	-1.5	2.9	16.6	17.2	Nifty 50	23346.4	↑0.3	100.0	21.2	25.4
Jio Financial	229.9	0.3	0.7	73.4	212.9						

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स स्टॉक

Adani Ports	1801.0	3.7	1.5	31.2	150.2	L & T	3860.0	0.8	5.8	29.8	39.5
Asian Paints	2405.0	-2.0	1.2	47.3	48.6	Mah & Mah	3053.1	-0.9	3.4	19.7	23.2
Axis Bank	1240.9	0.2	3.9	13.9	15.0	Maruti Suzuki	12145.0	-2.0	1.7	26.6	27.2
Bajaj Fin	1027.0	1.1	3.2	31.2	35.2	NTPC	324.0	-1.6	1.7	11.3	13.2
Bajaj Finsrv	1849.9	-0.7	1.3	28.5	133.6	Power Grid	270.0	2.5	1.3	15.8	16.0
Bharat Elctn	393.7	-0.5	1.5	46.8	47.0	Reliance Ind	1234.0	-0.6	9.2	22.3	42.6
Bharti Airtel	1866.0	2.1	6.3	36.6	67.6	SBI	989.8	0.5	4.5	10.9	11.6
Eternal	326.6	0.8	3.4	725.7	119.6	Sun Pharma	1835.5	-1.6	2.2	34.9	138.3
HCL Techno	1238.0	-1.4	1.4	18.5	18.5	Tata Steel	184.8	-1.7	1.7	19.5	12.8
HDFC Bank	729.1	2.3	12.3	14.2	14.9	TCS	2101.0	-4.3	2.3	14.2	14.1
HUL	1935.0	-1.1	1.9	41.2	42.1	Tech Mahindra	1530.7	-1.8	1.1	28.2	37.6
ICICI Bank	1337.1	-0.6	10.5	17.1	18.4	Titan Company	4756.5	-2.1	2.2	72.4	78.7
Infosys	1050.2	-0.6	4.1	13.7	13.7	Trent	2778.1	-0.6	1.0	81.0	70.6
InterGlobe Avia	4899.1	0.9	1.2	-	-	UltraTech	10670.0	-1.5	1.4	36.5	41.1
ITC	262.2	-1.4	3.6	16.6	17.2	BSE SENSEX	74295.0	↓0.0	100.0	20.9	24.6
Kotak Mah Bank	412.8	-1.0	3.3	20.5	27.6						

C = Consolidated; S = Standalone

वैश्विक सूचकांक

Indices	Close	% Chg*	Indices	Close	% Chg*
Americas (Sep 17,26)			**Asia/Pacific (Sep 18,26)**		
Nasdaq Composite	26418.3	1.7	Kospi (Sep 17)	6894.2	2.7
S&P/ TSX Composite	35874.3	1.1	Taiwan Taiex	47180.8	1.9
Dow Jones	51778.0	0.6	Shanghai Se Comp	3911.9	0.9
Europe/Africa (Sep 17,26)			Stock Exchange of Thai	1584.2	0.1
FTSE 100	10745.4	-0.7	Straits Times	5656.1	-0.1
CAC 40	8131.4	-0.7	Jakarta Composite	6441.2	-0.3
DAX	25537.1	-0.7	Kuala Lumpur Comp	1665.6	-0.6
IBEX 35	19664.7	-0.8	**Volatility (Sep 17,26)**		
Asia/Pacific (Sep 18,26)			CBOE S&P 500	15.4	-0.6
Nikkei 225	65019.0	1.4	CBOE Dow Jones	14.7	-12.5
Hang Seng	24750.8	0.6			

* Change over previous close

प्रमुख सूचकांक

	Previous Close	Open	High	Low	Close	Change	% chng
BSE Sensex	74,314.6	74,575.2	74,728.4	74,295.0	74,295.0	-19.6	0.0
BSE Sensex 50	24,413.7	24,494.3	24,549.2	24,404.7	24,404.9	-8.8	0.0
BSE-100	24,957.4	25,030.5	25,121.7	24,984.4	24,985.9	28.5	0.1
BSE-200	10,951.6	10,982.7	11,040.3	10,974.8	10,991.1	39.5	0.4
BSE-500	35,439.3	35,532.2	35,764.6	35,512.1	35,625.2	185.9	0.5
BSE IPO	18,277.5	18,330.0	18,834.6	18,319.7	18,717.7	440.2	2.4
Dollex-30	6,360.7	6,383.0	6,396.1	6,361.1	6,361.1	0.4	0.0
Nifty 50	23,270.6	23,334.7	23,389.2	23,286.6	23,346.4	75.8	0.3
Nifty next50	71,144.0	71,290.9	72,199.1	71,287.9	72,025.4	881.4	1.2
Nifty 500	22,654.7	22,709.7	22,860.3	22,707.4	22,840.6	185.9	0.8
India VIX	12.3	12.3	12.3	11.3	11.4	-0.9	-7.4
Nifty CPSE	6,333.4	6,346.1	6,359.3	6,317.6	6,327.6	-5.8	-0.1

बढ़े/घटे

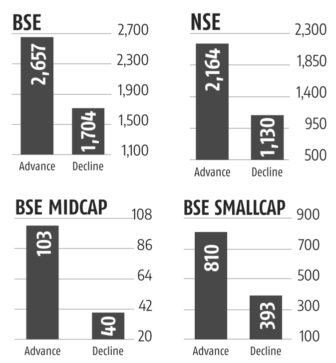

मार्केट ओवरव्यू

INDEX AGGREGATES	PE C/S	SHRS MN	TRDS '000	ADV	DEC	1 YR RETURN
SENSEX	20.9/24.6	25.8	218	10	20	-10.5
NIFTY 50	21.2/25.4	375.3	3953	26	24	-8.2

C = CONSOLIDATED; S = STANDALONE

TURNOVER	CASH BSE	CASH NSE	DERIVATIVES BSE	DERIVATIVES NSE
VALUE(IN ₹ CRORE)	10221	144659	2172813	13795042
SHARES(IN MN)	646.1	5341.0	75	15819.4
TRADES(000)	3585	42212	-	37239

MARKET-CAP (₹ CR)	TRADED	TOTAL
BSE	47,906,344	48,265,844
NSE	47,897,462	48,141,010
DERIVATIVES	33,339,036	33,339,036

कारोबारी गतिविधि

(₹ crore)	FIIs Equity Net	FIIs Debt Net	MF Equity Net	MF Debt Net
On 17 Sep	-3164	1150	-	-
On 16 Sep	-588	-1704	-	-
On 15 Sep	-3106	522	-	-
On 11 Sep	-978	-82	-	-
On 10 Sep	-226	-281	-	-
Sep till date	-15541	-1086	15467	5845
2026 till date	-240919	60790	389424	-583649

डेरिवेटिव में एफआईआई

(₹crore)	Index NET	Stock Net	Index Fut OI	Index Opt OI	Stock OI
On 17 Sep	5232	-41	0.4	3.3	7.7
On 16 Sep	-11012	1708	0.4	3.2	7.6
On 15 Sep	-20808	-2944	0.4	2.8	7.6
On 11 Sep	3985	-1055	0.4	3.6	7.5
On 10 Sep	3275	-1625	0.4	3.2	7.4
Sep till date	-48480	-3047	-	-	-
2026 till date	-790695	-83195	-	-	-

OI in number of contracts(million)

एसऐंडपी बीएसई सेक्टर सूचकांक

	Prev cls	Close	% Chng
Auto	60,105	60,198	0.2
Bankex	63,330	63,517	0.3
Cons. Durables	61,020	60,246	-1.3
Cap. Goods	75,681	76,862	1.6
FMCG	17,289	17,200	-0.5
Healthcare	51,118	51,438	0.6
Infra	556	563	1.3
IT	27,986	27,613	-1.3
Metal	41,014	41,215	0.5
Oil & Gas	25,419	25,651	0.9
Power	7,349	7,446	1.3
PSU	19,960	20,083	0.6
Realty	6,524	6,556	0.5

एफऐंडओ स्नैपशॉट

	Futures price	Cash price	Premium (%)		Futures price	Cash price	Discount (%)
MOST BULLISH				**MOST BEARISH**			
NBCC	84.0	82.4	2.0	Uno Minda	1244.6	1284.0	-3.1
Voltas	1131.2	1110.9	1.8	PI Inds	2297.0	2366.8	-2.9
Bosch	47850.0	47000.0	1.8	IREDA	111.1	114.3	-2.9
YES Bank	23.1	22.7	1.8	APL Apolo Tb	2206.0	2270.1	-2.8
Dixon Tech	13238.0	13005.0	1.8	Supreme Ind	3483.4	3580.3	-2.7

	BSE Index	BSE Stock	NSE Index	NSE Stock
FUTURE				
Contracts	535	7	50032	918980
Open Int.(000)	5	0	27880	18109423
Shares(In Mn)	0	0	2.9	1358.3
Value(₹ crore)	81	0	7896	60451
OPTIONS				
Contracts	14531551	5	86461175	8025250
Open Int.(000)	1089	0	683840	11546527
Shares(In Mn)	7	0	5538.4	8919.7
Value(₹ crore)	2172732	0	13182815	543880

पुट कॉल रेशियो

(Open Interest in Mn)	Put	Call	PC Ratio
Market	4410.6	7819.7	0.6

Top 5	PC Ratio	Bottom 5	PC Ratio
Aditya Birla	1.0	ONGC	0.3
Hyundai Motor	1.0	Suzlon Energy	0.3
Mankind Pharma	1.0	NTPC	0.3
Jindal Steel	1.0	Containr Crp	0.4
Cummins (I)	1.0	Motilal Oswl	0.4

एक्टिव कॉल

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	22/09/26	23300	365.8	7.4	12.5
Nifty	22/09/26	23350	344.4	5.0	42.5
Nifty	22/09/26	23400	317.5	8.8	34.6
Nifty	22/09/26	23500	229.2	9.2	2.0
Nifty	22/09/26	23450	174.0	3.9	12.2
Stock					
Vodafone Idea	29/09/26	15	504.2	707.1	-4.4
Vodafone Idea	29/09/26	16	421.5	485.3	-3.6
Vodafone Idea	29/09/26	17	164.8	260.1	-0.1
Vodafone Idea	29/09/26	14	148.8	252.2	8.2
YES Bank	29/09/26	24	78.3	129.4	3.5

एक्टिव पुट

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	22/09/26	23300	460.8	12.7	86.8
Nifty	22/09/26	23350	262.2	5.1	224.3
Nifty	22/09/26	23200	221.0	9.6	9.7
Nifty	22/09/26	23250	184.7	6.5	38.7
Nifty	22/09/26	23400	171.3	4.8	60.7
Stock					
Vodafone Idea	29/09/26	13	180.5	187.5	-5.1
Vodafone Idea	29/09/26	14	118.4	262.2	0.1
YES Bank	29/09/26	23	42.8	82.4	-3.7
HDFC Bank	29/09/26	720	41.6	10.5	19.6
Vodafone Idea	27/10/26	14	39.9	84.1	39.5

वॉल्यूम में तेजी

Company	Days Volume	2-week Avg Volume	Change %	Close price	*Price %chg
Bombay Burm	4422313.0	46124.2	9487.8	1510.3	8.0
Utiamc-Niftybet	2607269.0	35029.3	7343.1	259.8	0.3
A B Cotspin Ind	427714.0	7533.9	5577.2	210.9	0.0
Top15letf	150107.0	2832.9	5198.7	9.5	0.0
Adani Total Gas	41337560.0	814149.8	4977.4	660.7	12.6
Manugraph I	728534.0	15641.9	4557.6	18.2	19.3
Sri Adhikari Br	38267346.0	1120100.0	3316.4	18.0	-4.8
SKF Industrial	1431248.0	45416.7	3051.4	2962.9	0.8
Shivam Auto	1118591.0	39325.2	2744.5	20.1	20.0
Grauer Weil	15325745.0	546661.3	2703.5	86.4	8.9

52 सप्ताहों का उच्चतम और निम्नतम

Company	Price	Company	Price	Company	Price	Company	Price
HIGH		*Yashhv	1099.8	**LOW**		POCL Ent	135.8
BS 200		*Liquidbetf	1099.5	BS 200		*Tirupati Str	115.0
*Aurob Pharma	1735.0	Jyoti CNC Autom	1066.0	*Tata Elxsi	3325.3	Camlin Fine Sci	96.0
Others		*Shilpa Medi	1033.4	Reliance Ind	1234.0	*Suyog Gurbaxani	82.0
*Apar Ind	19054.0	*Absliquid	1000.0	*KPIT Techno	539.2	*AB Life Brand	80.8
*SAR Auto Pr	6534.2	*Mirae -ET	1000.0	*Syngene Intl	366.8	*City Puls Mult	75.9
*Sansera Enginee	4295.0	*Sigma Advanc	887.4	Bank of Baroda	232.1	*Dhruva Capital	74.0
*SKF Industrial	3210.5	*Welspun Ent	838.0	*Wipro	163.4	*Rajesh Exp	70.9
*Cospower Engg	2814.0	Asian Star	827.2	Others		*Perfectpac	65.0
*Avalon Technol	2620.0	*West Coast Pape	771.1	*MRF	123800.0	*Himatsing S	63.0
*Neogen Chem	2498.5	*Timex Group	729.0	*Proct & Gamb	7435.0	*DSM Fresh Foods	54.0
*Venus Pipes	2306.1	*Lenskart	725.0	*Gillette I	7032.0	*Continental Che	51.1
*Anand Rathi Wea	2267.0	DIC India	641.6	Astrazen Ph	6610.0	*Reliance Infra	49.9
*Emcure Pharma	2101.0	Gretex Corpor	620.9	*ICRA	4531.0	*Athena Global T	49.5
*Ipca Labs	2039.2	*Beezaasan	607.0	*Bayer CropSn	3763.3	*Cindrella Ht	42.5
*Veljan Denis	2000.0	*Tribhovandas Bh	602.9	*Kama Hold	2250.0	*Tanvi Foods (I)	39.9
*Syrma SGS Techn	1765.0	Max Estates	595.1	*IndiaMART Int	1623.5	*Austere Systems	36.5
GMM Pfaudler	1475.0	Somany Cera	578.0	*Transport Co	820.2	*Abram Food	35.5
*Rosstech	1464.0	*Adv Petroch	569.4	Sharda Crop	736.9	*Chatterbox	35.0
*Valiant Comm	1400.0	*Shri Venkatesh	560.0	*Whirlpool	706.3	*Indo Thai Secur	33.7
*Kalyani Cast-Te	1394.0	Quadrant Future	554.7	EID Parry	683.0	*Vedanta Power	30.4
PVR Inox	1340.0	*NRB Bearings	535.0	*Brady & Morr	645.0	*Neptune logtex	30.2
Action Const	1241.5	*SKM	507.0	*The Hi-Tech Gea	516.0	Centuple Global	29.9
*Yatharth Hospit	1183.2	Softtech	496.2	Lerthai Financ	348.3	*UHM Vacation	29.1
*Liquidadd	1145.5	*Talbros Auto	480.0	Ind.Link Chain	245.6	Meera Inds	27.2
*CFF Fluid C	1144.8	SNL Bearings	475.9	*Go Digit Genera	236.5	*Ambassador	26.9
*Liquid1	1123.4	*Bhagya Inter	469.8	Autorid.Inte	225.6	Gautam Exim	22.7

* Indicates that the market price of these companies reached two-year highs/lows.

दिन में सबसे ज्यादा चढ़े

Company	Day's high	Close	% chg*	3mth high	52 wk high
APL Apolo Tb	2270.7	2270.7	5.9	2277.0	2300.9
Rail Vikas Niga	210.5	210.3	4.5	250.8	400.9
Dalmia Bharat	1800.0	1765.7	4.5	1924.1	2459.1
Exide Ind	444.5	436.2	4.3	496.0	496.0
IRCTC	479.5	476.5	4.2	526.9	739.0
Sona BLW Precis	812.0	810.0	3.9	843.9	843.9
Ather Energy	1614.9	1610.0	3.9	1741.9	1741.9
Supreme Ind	3485.0	3460.0	3.8	3711.1	4483.1
Shree Cement	22967.2	22749.6	3.8	27530.5	30274.0
Adani Green En	1338.1	1313.7	3.7	1631.4	1631.4
Adani Ports	1801.0	1801.0	3.7	1891.8	1891.8
PAYTM	1825.0	1825.0	3.6	1856.5	1856.5
Jubilant Fd	502.0	498.0	3.4	528.1	635.0
LIC India	411.7	411.7	3.3	450.0	468.3
HUDCO	176.6	175.2	3.2	217.8	246.9

दिन में सबसे ज्यादा गिरे

Company	Day's low	Close	% chg*	3mth low	52 wk low
Cupid Ltd	251.1	265.1	-5.1	170.4	41.3
Tata Techno	716.3	723.3	-4.7	662.0	507.5
TCS	2101.0	2101.0	-4.3	1976.0	1976.0
Tata Motors PV	301.6	303.8	-3.4	296.7	294.2
KPIT Techno	539.2	543.0	-2.9	539.2	539.2
Syngene Intl	366.8	369.3	-2.8	366.8	366.8
Titan Company	4756.5	4756.5	-2.1	4224.3	3307.4
Asian Paints	2405.0	2405.0	-2.0	2396.7	2116.0
Maruti Suzuki	12145.0	12145.0	-2.0	12135.0	12135.0
Marico	801.0	801.0	-1.9	767.3	690.4
Tech Mahindra	1522.6	1530.7	-1.8	1345.0	1304.3
Torrent Phar	4804.3	4804.3	-1.8	4376.0	3480.0
Tata Steel	184.8	184.8	-1.7	180.1	160.0
DLF	631.1	631.1	-1.7	609.0	489.3
Sun Pharma	1835.5	1835.5	-1.6	1820.8	1547.3

* Ranked on the basis of percentage gain/loss on previous close

सबसे ज्यादा कारोबार

	Value BSE+NSE (₹ crore)	Volume BSE+NSE (Mn shrs)
HDFC Bank	3235.6	44.5
Bharti Airtel	2726.9	14.6
Adani Total Gas	2697.6	41.3
Infosys	2356.5	22.5
Glass Wall Sys	2246.7	79.9
Rentomojo	2056.2	38.6
Reliance Ind	1927.0	15.6
Syrma SGS Techn	1902.2	11.0
Meesho	1887.0	88.2
Lenskart	1833.6	26.0
TCS	1528.4	7.2
Billionbrains	1464.7	76.8
Pine Labs	1340.1	70.3
Welspun Corp	1270.6	4.9
Skyways Air	1258.2	97.2
Karamtara Eng	1119.8	31.7
Avalon Technol	1101.7	4.5
ICICI Bank	1073.0	8.0
Tata Chem	1072.2	15.1
Bajaj Fin	970.5	9.4
Mah & Mah	966.0	3.1
JSW Infra	910.4	26.2
MCX	872.9	2.7
PAYTM	865.6	4.8
Maruti Suzuki	856.6	0.7

प्रमुख एम-कैप

Rank	Company	Mcap (₹ cr)
1	Reliance Ind	1669847.8
2	Bharti Airtel	1164686.3
3	HDFC Bank	1124031.6
4	ICICI Bank	959777.1
5	SBI	913664.6
6	TCS	760162.8
7	Bajaj Fin	639410.2
8	L & T	531097.4
9	LIC India	520737.3
10	HUL	454635.9
11	Sun Pharma	440391.5
12↑	Infosys	426176.1
13↓	Titan Company	422282.1
14↑	Adani Ports	414941.4
15↓	Kotak Mah Bank	410641.1
16	Adani Enter	405898.2
17	Adani Power	403050.2
18↑	Axis Bank	386354.2
19↓	Maruti Suzuki	381838.8
20	Mah & Mah	379652.9
21	HCL Techno	335949.9
22	ITC	328531.4
23	HAL	321081.3
24↑	Bajaj Auto	316015.9
25↑	Eternal	315133.8
26↓	UltraTech	314423.6
27↓	NTPC	314172.1
28	JSW Steel	310089.4
29	Bajaj Finsrv	296364.5
30	ONGC	292491.5

रुझान

Company	% change	Company	% change
BS200		**DOWN 7 DAYS**	
UP 3 DAYS		Mopshop Distrib	-40.5
Max Fin Sre	10.4	ANS Inds	-30.1
ICICI Prud Life	8.2	City Puls Mult	-30.1
APL Apolo Tb	7.3	Fly Hi Maritime	-30.0
Jubilant Fd	7.2	Tirupati Foam	-29.7
SBI Life Ins	7.0	Lerthai Financ	-26.6
Uno Minda	6.8	Hypersoft Tech	-21.4
Alkem Labs	6.7	**UP 3 DAYS**	
DOWN		Monq50	72.4
Cupid Ltd	-6.8	Quint Digital	45.2
Torrent Pwer	-3.3	Asian Star	44.5
Federal Bank	-3.0	Dhanwel Hybrid	33.1
Mphasis	-2.9	Masptop50	30.4
Infosys	-2.4	Patels Airt	27.0
Wipro	-2.3	TCM	26.5
Solar Ind	-2.2	**DOWN 3 DAYS**	
Others		Betala Global	-19.9
UP 7 DAYS		Graviss Hosp	-16.9
Dindigul Farm P	55.3	Retina Paints	-16.3
Classic Filam	54.4	Mukka Proties	-14.4
Grand Found	54.3	RR Metalmakers	-14.3
Afltd	49.2	Esds Software	-14.3
Anlon Health	47.6	Onix Solar	-14.3
Std.Surfact.	40.7		
Mcnally Bh	40.7		

बोर्ड बैठक

Group
Company
Purpose

SEPTEMBER 19

Anupam Rasayan: To consider and approve the fund raising by way of issuance of Secured Rated Unlisted Redeemable Non-Convertible Debentures on Private Placement basis

Choksi Labs: To consider and approve the proposal for raising funds through issue of equity shares and/ or any other equity-linked or convertible securities

Equinox Dev: To consider and approve the raising of funds by way of issuance of non-convertible debentures (NCDs), through such permissible mode(s)

Gconnect: To consider the proposal for raising funds through the issuance of equity shares on a rights basis to the Company

Goenka Business: To consider and approve Final Dividend for the financial year 2025 26

P N Gadgil: To consider and approve the Employee Stock Option Plan

Seshachal: To consider and approve Fund raising

SEPTEMBER 20

Prime Inds: To consider and approve the issue of Equity shares/convertible warrants/other instruments through prefrential issue.

Spectrum: To consider other business matters

SEPTEMBER 21

Augmont Ente: To consider and approve Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter Ended 30th June 2026

Elitecon: To consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31 2026.

Kapil Raj Fin: to consider and approve the proposal for raising of funds

Lumino Industri: To consider and approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Statement of the Company along with the Limited Review Report for the quarter ended 30th June 2026.

Reliable Data: To consider and approve raising funds through preferential allotment/right issue or any other mode.

Share India Sec: To consider and approve the proposal for raising of funds through issue of such securities

Supra Pacific F: Meeting of the Board of Directors of the Company

Suryoday SFB: to consider and approve raising of funds by issue of Non-Convertible Debentures on Private Placement basis

Symbiotec Pharm: To consider and approve To consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2026 along with Limited Review Report.

Tahmar Enterpri: Meeting of the Board of Directors of the Company

इंट्रा-डे

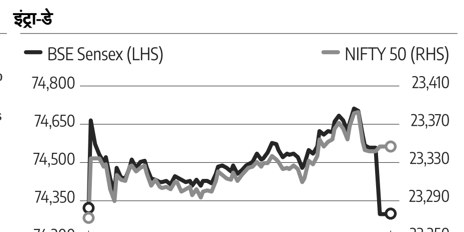

ANNUAL GENERAL MEETING

SEPTEMBER 19
Group A
Godawari Pwr
Kalyan Jeweller
Banco Prod
Netweb Technolo
Group B
Shankar Lal Ram
Vishal Bearings
Arfin India
Veer Global
RMC Switch
Arcl
SG Mart
Anant Raj Globa
Guj Ind Power
Bharat Paranter
Indo Thai Secur
Group M
KCS
STEELMAN TEL
DAPS Advertisin
Chemkart
Group MS
Nirmitee Roboti
Group P
SICL
Group T
Ashika Global
Group X
Tulsyan Nec
Tulsyan Nec
Classic Leasing
Adarsh Pt Pr
Ruparel Food
Nikki Glob
Milestone Gl
Pasari Spg
Prism Medico
Ultracab (I)
Group XT
Sinnar Bidi
Axisol
Asia Capital
Sinnar Bidi
Easun Cap Mar
Valson Inds
Gallopent
Group ZP
Mahasagar T

SEPTEMBER 21
Group A
Inventurus Know
Chalet Hotels
Paisalo Digital
Apar Ind
Blue Jet HC
Taril
Premier Energie
Awfis Space
Manorama Inds
Emcure Pharma
Sammaan Capita
Dr Agarwals Hea
Group B
Pace Digitek
Trejhara Sol

बीएस-200

स्टॉक पेज कैसे पढ़ें

बिजनेस स्टैंडर्ड के शेयर बाजार के पन्ने पर बीएस-200 में बंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के स्पॉट और फ्यूचर्स के आंकड़े एक ही जगह पर दिए गए हैं। दोनों प्रमुख शेयर बाजारों में इन शेयरों के वॉल्यूम, भाव और कारोबार की हिस्सेदारी 85 फीसदी है। बीएसई-200 सूची दिन के कारोबार की बुनियादी जानकारी देता है। पिछले दिन बाजार किस भाव पर बंद हुआ था, शुरुआती कारोबार के आंकड़े, न्यूनतम और अधिकतम भाव, शेयर के वॉल्यूम और पीई (प्राइस टू अर्निंग) की जानकारी यहां दी जाती है।

पिछले 52 हफ्तों के उच्चतम और निम्नतम आंकड़ों का रिकार्ड भी यहां उपलब्ध होता है। बाजार बंद के बाद एनएसई में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। साथ ही पिछले सत्र की समाप्ति के आंकड़े और अंतिम सत्र के आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। शेयर से संबंधित अन्य पन्नों में उन शेयरों के बारे में जानकारी दी जाती है जिन्हें बीएसई-200 में शामिल नहीं किया गया है। अन्य शेयरों की जानकारी उपलब्ध कराने वाले इस पन्ने में हमने बीएसई और एनएसई के प्रतिदिन के कारोबार के दौरान उच्चतम और निम्नतम कारोबारी आंकड़ो को प्रस्तुत किया है। उन शेयरों की भी जानकारी यहां दी गई है जिनकी मांग बाजार में सबसे अधिक है।

परिभाषा: किसी शेयर के बंद भाव को प्रति शेयर आय (ईपीएस) से भाग देने पर पीई निकाला जाता है। ईपीएस से आशय कुल मुनाफे से है जिसे पिछले 12 महीनों के कारोबारी आंकड़ों को इक्विटी कैपिटल से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। पीई का मूल्यांकन समग्र आय के आधार पर किया जाता है। उच्चतम और निम्नतम आंकड़े से तात्पर्य उस आंकड़े से है जिसे किसी शेयर के पिछले 52 हफ्तों के प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया है।

ओपन इंट्रेस्ट: फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफऐंडओ) सेगमेंट के तहत प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में जितने कॉन्ट्रेक्ट खुले होते हैं, उस संख्या को ही ओपन इंट्रेस्ट कहा जाता है।

मार्केट लॉट्स: एक एफऐंडओ कॉन्ट्रेक्ट का मूल्य। क्षेत्रगत सूचकांकों में इसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी 25 जूनियर में इसके भाव में अंतर हो सकता है।

स्ट्राइक प्राइस: जिस भाव पर किसी ऑप्शन के लिए बोली लगाई जा सकती है। अगर मार्केट प्राइस एसपी से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कोई ऑप्शन इन द मनी है। वहीं अगर मार्केट प्राइस एसपी से कम होती है तो ऐसी स्थिति में उस ऑप्शन को आउट ऑफ मनी कहा जाता है।

एक्सपाइरी डेट: इसे सेटलमेंट तिथि के तौर पर भी जानते हैं। इसी तारीख पर कोई डेरीवेटिव का निबटान होता है। एनएसई के लिए यह तारीख हर महीने की आखिरी गुरुवार होती है।

SYMBOLS FOR FACE VALUE OF SCRIPS

● ₹100 ❍ ₹50 ■ ₹20 ◆ ₹6 ✤ ₹5 ✱ ₹4 ❑ ₹3 ★ ₹2 ♠ ₹1

Face value of scrips is ₹10 in all cases if not specified.

	360 ONE WAM♠ BSE	NSE	ABB India★ BSE	NSE
PClose	(1060.8)	(1061.3)	(7129.0)	(7130.5)
Open	1064.9	1060.5	7175.0	7185.5
High	1086.8	1086.1	7308.9	7307.0
Low	1061.0	1060.5	7162.9	7151.0
Close	1082.8	1073.1	7235.2	7270.5
Shares	162K	519K	18369	383K
PE	35.0	34.6	99.5	100.0
52 Wk H/L	1236/906	1236/906	7923/4641	7925/4638
Mcap	44135	43740	153314	154062

	Adani Energy So BSE	NSE	Adani Enter♠ BSE	NSE	Adani Green En BSE	NSE	Adani Ports★ BSE	NSE	Aditya Birla BSE	NSE	Alkem Labs★ BSE	NSE
PClose	(1382.0)	(1386.8)	(2926.6)	(2923.2)	(1266.3)	(1274.2)	(1736.4)	(1738.3)	(389.5)	(390.0)	(5340.0)	(5348.5)
Open	1381.0	1380.9	2935.0	2933.0	1275.0	1274.2	1749.8	1748.0	390.9	390.5	5340.9	5378.5
High	1437.0	1436.5	3005.8	3020.0	1338.1	1337.9	1801.0	1824.0	404.3	410.1	5501.6	5466.5
Low	1381.0	1380.9	2924.6	2924.6	1273.6	1274.2	1744.3	1744.0	390.9	390.5	5310.4	5310.5
Close	1415.0	1436.1	2999.1	3020.0	1313.7	1334.5	1801.0	1824.0	400.1	410.1	5501.6	5466.5
Shares	73961	2146K	58067	1628K	142K	2597K	105K	4149K	2315K	4889K	25104	321K
PE	59.3	60.2	157.7	158.8	109.9	111.7	31.2	31.6	27.2	27.9	28.9	28.7
52 Wk H/L	1789/805	1789/803	3245/1753	3245/1753	1631/767	1632/765	1892/1293	1891/1292	431/278	431/278	5933/5052	5934/5051
Mcap	173047	175628	405898	408727	216390	219816	414941	420240	109529	112253	65772	65352

	Axis Bank★		Bajaj Auto		Bajaj Fin♠		Bajaj Finsrv♠		Bandhan Bank		Bank of Baroda★	
PClose	(1238.1)	(1240.0)	(11524.0)	(11500.0)	(1016.0)	(1015.0)	(1862.4)	(1859.2)	(171.4)	(171.5)	(232.4)	(232.3)
Open	1241.5	1244.0	11512.6	11501.0	1024.0	1025.9	1859.1	1857.2	172.8	173.0	232.5	233.6
High	1249.9	1257.0	11530.3	11540.0	1036.1	1040.3	1870.0	1872.6	178.3	178.3	234.8	234.9
Low	1240.6	1240.5	11400.1	11406.0	1019.2	1019.1	1843.3	1852.5	172.8	172.5	232.1	231.9
Close	1240.9	1257.0	11499.9	11414.0	1027.0	1040.3	1849.9	1852.5	175.0	175.0	234.8	234.9
Shares	79791	5693K	12262	297K	1222K	8202K	362K	720K	949K	20361K	263K	7111K
PE	13.9	14.1	26.8	26.6	31.2	31.6	28.5	28.5	20.8	20.8	5.5	5.5
52 Wk H/L	1418/1123	1418/1125	12470/8490	12470/8492	1178/788	1176/788	2195/1598	2195/1597	221/134	221/134	326/232	326/232
Mcap	386354	391367	316016	313657	639410	647691	296364	296789	28195	28195	121423	121496

	CAMS★		Canara Bank★		CDSL		CG Power★		Chola Inv★		Cipla★	
PClose	(713.4)	(715.0)	(123.9)	(123.9)	(-)	(1349.4)	(880.0)	(880.0)	(1761.5)	(1764.5)	(1372.3)	(1376.3)
Open	714.1	712.7	123.9	123.8	-	1348.0	881.1	883.7	1773.2	1769.3	1372.3	1371.7
High	723.5	723.6	123.9	123.9	-	1390.0	911.0	911.0	1804.0	1804.4	1391.7	1394.5
Low	708.1	708.1	123.0	123.0	-	1346.5	881.1	881.3	1760.1	1766.0	1371.5	1371.7
Close	708.1	708.1	123.5	123.8	-	1390.0	900.0	892.0	1778.6	1800.0	1371.5	1394.5
Shares	50501	1128K	491K	11490K	-	1694K	205K	3115K	7867	1510K	11566	1387K
PE	35.5	35.5	5.6	5.7	-	61.6	111.4	110.4	26.4	26.7	31.0	31.5
52 Wk H/L	845/612	845/611	163/116	163/116	-/-	1674/1116	981/526	981/526	1952/1300	1953/1299	1672/1166	1673/1166
Mcap	17588	17588	112023	112277	-	29051	141791	140530	151946	153774	110793	112655

	Exide Ind♠		Federal Bank★		Force Motors		Fortis Health		GAIL		Glenmark♠	
PClose	(418.1)	(418.6)	(334.0)	(332.8)	(17673.0)	(17650.0)	(887.3)	(886.1)	(172.0)	(172.0)	(2414.5)	(2416.0)
Open	419.9	419.4	332.4	332.8	17622.0	17622.0	882.8	884.7	171.9	172.0	2417.3	2409.8
High	444.5	444.7	335.4	335.4	17877.0	17882.0	899.8	899.7	174.6	174.7	2436.0	2447.4
Low	419.8	419.4	325.5	325.4	17601.8	17488.0	875.0	884.7	171.9	172.0	2380.0	2396.8
Close	436.2	435.9	332.8	332.8	17669.4	17488.0	875.0	886.0	172.0	173.9	2380.0	2447.4
Shares	231K	5571K	398K	14568K	3709	63130	59189	1928K	195K	8527K	57061	546K
PE	39.5	39.5	17.6	17.6	21.2	20.9	61.9	62.7	11.5	11.6	21.5	22.1
52 Wk H/L	496/287	496/287	365/189	372/189	26486/14911	26450/14911	1105/767	1104/767	187/134	187/134	2537/1794	2538/1793
Mcap	37077	37047	82286	82274	23288	23049	66059	66689	113092	114341	67164	69066

	Hind Zinc★		Hindalco♠		Hitachi Energy★		HPCL		HUL♠		Hyundai Motor	
PClose	(573.5)	(572.3)	(983.8)	(980.5)	(31201.0)	(31230.0)	(350.5)	(350.6)	(1955.9)	(1942.2)	(2163.4)	(2160.0)
Open	578.0	578.3	981.7	982.9	31580.0	31490.0	352.9	352.4	1948.0	1950.0	2171.1	2176.0
High	591.8	596.0	999.4	999.3	32349.1	32700.0	356.2	359.0	1959.3	1959.6	2190.0	2208.8
Low	578.0	578.3	972.0	979.4	31533.8	31450.0	350.7	350.5	1935.0	1932.0	2155.3	2155.5
Close	585.2	596.0	972.0	986.5	32100.0	32700.0	354.5	359.0	1935.0	1932.0	2169.0	2208.8
Shares	362K	7197K	294K	8310K	7824	126K	134K	6540K	38109	1995K	23021	764K
PE	14.5	14.8	10.5	10.6	120.1	122.4	45.2	45.7	41.2	41.2	35.6	36.3
52 Wk H/L	733/446	733/446	1179/732	1176/732	38800/16104	38785/16111	508/316	508/316	2668/1927	2667/1926	2890/1658	2890/1658
Mcap	247265	251828	218428	221686	143006	145679	75431	76389	454636	453943	176240	179474

	InterGlobe Avia		IOC		IRFC		ITC♠		Jindal Steel &♠		Jio Financial	
PClose	(4854.0)	(4845.0)	(134.1)	(134.3)	(79.3)	(79.3)	(266.0)	(266.2)	(1125.6)	(1128.4)	(229.5)	(229.3)
Open	4912.2	4925.0	134.8	135.0	79.3	79.3	266.9	266.6	1130.2	1128.9	230.0	230.0
High	4965.9	4970.0	136.8	137.0	81.5	81.5	267.0	266.6	1139.6	1140.2	232.0	232.0
Low	4883.8	4881.0	134.7	134.6	79.3	79.3	262.2	262.3	1124.6	1119.5	230.0	229.9
Close	4899.1	4920.0	136.8	137.0	81.5	81.5	262.2	262.3	1124.9	1119.5	231.4	229.9
Shares	39577	732K	281K	11506K	424K	14378K	13005K	14399K	11424	1057K	993K	11847K
PE	-	-	5.7	5.7	14.8	14.8	16.6	16.6	37.2	37.0	73.9	73.4
52 Wk H/L	5959/3895	5970/3895	189/130	189/130	137/78	137/78	427/256	426/256	1306/978	1306/977	322/223	322/223
Mcap	189434	190242	193179	193461	106508	106508	328531	328657	114746	114200	152797	151800

	LIC Hsg Fin★		LIC India		LTM♠		Lupin★		Macrotech Devlp		Mah & Mah✤	
PClose	(546.5)	(545.9)	(398.6)	(400.0)	(4258.5)	(4265.3)	(2092.0)	(2098.1)	(1102.1)	(1103.1)	(3080.0)	(3076.5)
Open	548.5	548.6	400.0	400.0	4240.6	4245.0	2090.6	2088.1	1110.7	1110.2	3080.0	3082.0
High	551.7	552.0	411.7	407.7	4279.0	4300.0	2144.7	2114.7	1148.5	1148.8	3097.0	3098.2
Low	543.9	543.6	398.8	398.8	4157.2	4155.0	2079.0	2075.0	1110.0	1108.6	3053.1	3052.0
Close	548.9	548.2	411.7	407.7	4257.9	4275.1	2144.7	2083.0	1115.1	1144.7	3053.1	3052.0
Shares	50602	2235K	774K	6937K	19896	501K	134K	1194K	90599	4727K	175K	2973K
PE	5.3	5.3	8.7	8.6	22.5	22.6	16.5	16.0	27.0	27.7	19.7	19.7
52 Wk H/L	598/459	598/459	468/361	468/361	6430/3530	6430/3528	2530/1900	2530/1900	1344/651	1345/651	3840/2896	3840/2896
Mcap	30192	30151	520737	515741	126289	126799	98066	95245	111436	114394	379653	379522

	NBCC♠		Nestle India♠		NHPC		NMDC♠		NTPC		Nykaa♠	
PClose	(82.4)	(82.1)	(1372.0)	(1370.6)	(75.1)	(75.2)	(80.9)	(80.8)	(329.4)	(329.6)	(323.6)	(323.8)
Open	82.3	82.4	1370.2	1372.1	75.1	75.2	81.1	81.4	330.1	329.8	327.3	324.2
High	84.2	84.3	1389.2	1390.0	76.5	77.0	81.7	81.7	330.7	330.9	329.8	332.2
Low	82.3	82.4	1332.8	1332.8	75.1	75.1	79.7	79.2	324.0	323.7	322.8	322.7
Close	83.9	82.4	1353.1	1372.4	76.5	77.0	79.7	79.2	324.0	323.7	326.0	332.2
Shares	410K	5215K	157K	3265K	1037K	18275K	740K	18920K	124K	9449K	57470	4424K
PE	33.1	32.6	70.4	71.4	20.2	20.4	9.4	9.3	11.3	11.3	350.5	357.2
52 Wk H/L	126/77	126/77	1553/1145	1553/1145	89/69	89/72	98/72	97/72	414/316	414/316	351/219	350/228
Mcap	22642	22248	260918	264640	76845	77297	70071	69587	314172	313833	93376	95138

	PNB★		PNB Hou Fin		Policy Bazar★		Polycab India		Power Fin		Power Grid	
PClose	(116.8)	(116.5)	(1107.9)	(1103.5)	(1762.3)	(1765.0)	(8225.0)	(8208.5)	(345.5)	(345.0)	(263.5)	(263.8)
Open	116.9	117.0	1103.0	1105.2	1787.7	1770.0	8250.0	8256.0	344.6	345.0	264.8	264.6
High	118.0	117.5	1138.0	1138.3	1796.8	1798.0	8375.0	8400.0	347.1	347.1	270.0	270.3
Low	116.5	116.5	1083.0	1103.0	1740.0	1743.0	8237.0	8235.0	344.4	342.6	263.4	263.4
Close	117.2	117.3	1128.0	1133.1	1740.0	1743.0	8360.0	8400.0	346.0	342.6	270.0	270.3
Shares	486K	16061K	28711	1329K	104K	1368K	75691	417K	395K	11370K	162K	17897K
PE	6.1	6.1	12.7	12.8	107.6	107.8	44.0	44.2	4.4	4.3	15.8	15.8
52 Wk H/L	135/99	135/99	1211/730	1212/730	1963/1334	1964/1364	10129/6661	10126/6663	486/330	487/330	325/250	325/250
Mcap	134697	134778	29418	29551	80510	80649	125977	126580	114183	113045	251116	251395

	SBI Life Ins		Shriram Finance★		Siemens★		Solar Ind★		Sona BLW Precis		SRF	
PClose	(1762.3)	(1766.9)	(997.0)	(995.0)	(3770.0)	(3763.5)	(18890.0)	(18815.0)	(779.7)	(777.9)	(2536.0)	(2536.0)
Open	1755.0	1751.3	1003.1	1004.9	3773.4	3781.4	18849.8	18850.0	779.4	780.2	2530.0	2536.6
High	1769.4	1770.0	1019.0	1019.0	3845.4	3913.9	19088.8	19080.0	812.0	812.0	2567.4	2569.9
Low	1741.0	1731.0	1001.0	1000.5	3752.9	3770.0	18726.9	18555.0	779.4	780.2	2530.0	2512.0
Close	1769.4	1731.0	1005.0	1010.0	3822.8	3913.9	18830.0	18555.0	810.0	808.0	2561.0	2512.0
Shares	12815	929K	129K	4871K	43196	667K	18696	203K	173K	4202K	9016	401K
PE	68.3	66.8	20.9	21.0	90.6	92.7	85.6	84.3	69.5	69.4	33.9	33.2
52 Wk H/L	2133/1653	2132/1653	1154/603	1154/603	4149/2827	4149/2826	22630/11641	22700/11646	844/403	844/402	3239/2314	3210/2355
Mcap	177533	173680	236482	237658	136130	139374	170412	167923	50555	50430	75913	74461

	Torrent Phar✤		Trent♠		Tube Inv of Ind♠		TVS Motor♠		UltraTech		Union Bank	
PClose	(4891.0)	(4875.0)	(2796.0)	(2789.0)	(2612.5)	(2598.8)	(4110.3)	(4101.7)	(10830.3)	(10764.0)	(177.4)	(178.1)
Open	4871.1	4874.5	2786.4	2789.3	2573.0	2598.9	4113.7	4125.0	10873.4	10890.0	177.8	178.5
High	4927.5	4928.0	2820.0	2824.0	2674.9	2637.8	4195.0	4195.0	11056.0	11060.0	179.0	178.9
Low	4804.3	4827.0	2776.1	2776.1	2573.0	2571.5	4113.7	4122.1	10670.0	10819.0	177.0	176.6
Close	4804.3	4840.0	2778.1	2824.0	2605.0	2600.0	4161.0	4171.3	10670.0	11014.0	177.0	176.6
Shares	5888	487K	43357	925K	16241	293K	25619	1305K	138K	459K	99160	6401K
PE	81.9	82.5	81.0	82.2	78.6	78.3	57.1	57.3	36.5	37.6	6.5	6.5
52 Wk H/L	5250/3480	5250/3481	3434/2184	3439/2184	3395/2165	3400/2165	4485/3228	4485/3228	13104/10329	13110/10325	205/134	205/134
Mcap	182734	184094	148126	150576	50433	50336	197689	198178	314424	324561	135115	134779

	Amber Enter Ind BSE	NSE	Ambuja Cem★ BSE	NSE	Angel One♠ BSE	NSE	APL Apolo Tb★ BSE	NSE	Apollo Hosp✤ BSE	NSE	Ashok Leyland♠ BSE	NSE
PClose	(7065.3)	(7046.0)	(384.0)	(383.3)	(295.6)	(295.0)	(2144.7)	(2148.5)	(8750.0)	(8768.5)	(158.9)	(158.6)
Open	7071.6	7080.5	384.2	384.6	294.8	295.0	2155.4	2154.9	8790.8	8800.0	158.9	159.1
High	7165.8	7164.5	395.8	396.0	301.7	301.8	2270.7	2270.1	8866.7	8944.5	163.1	163.1
Low	7071.6	7075.0	384.0	383.9	294.8	295.0	2100.1	2146.3	8770.3	8798.0	158.5	158.5
Close	7129.0	7125.0	392.6	388.3	300.0	299.1	2270.7	2270.1	8770.3	8944.5	162.8	163.0
Shares	3877	75972	161K	2583K	357K	3531K	26123	1116K	25549	344K	654K	17546K
PE	127.1	127.0	20.5	20.2	26.6	26.5	51.3	51.3	59.9	61.1	25.6	25.6
52 Wk H/L	8970/5404	8974/5401	601/380	601/380	360/209	360/209	2301/1653	2301/1653	9327/6680	9050/6697	215/134	215/134
Mcap	25144	25130	97541	96485	27420	27338	63045	63029	126099	128604	95627	95745

	Bank of India		Bank of Maha		Bharat Dyn✤		Bharat Elctn♠		Bharat Forge★		Bharti Airtel✤	
PClose	(138.1)	(138.2)	(80.8)	(80.8)	(1150.0)	(1151.9)	(395.6)	(395.5)	(1919.0)	(1918.7)	(1827.5)	(1836.0)
Open	139.0	138.8	81.3	81.6	1153.0	1151.9	399.0	397.4	1934.3	1940.1	1844.0	1843.0
High	140.1	140.0	83.3	83.5	1176.9	1196.6	399.3	399.2	1994.0	1994.9	1866.0	1893.3
Low	138.1	138.0	81.2	81.1	1150.0	1151.0	393.7	393.3	1934.3	1940.1	1835.1	1835.3
Close	140.1	140.0	82.0	83.5	1173.0	1196.6	393.7	393.3	1976.0	1962.1	1866.0	1893.3
Shares	123K	4270K	651K	18030K	38719	742K	645K	11863K	219K	1602K	364K	14190K
PE	5.4	5.4	8.4	8.5	82.5	84.2	46.8	46.8	93.4	92.7	36.6	37.1
52 Wk H/L	178/116	178/116	95/54	95/54	1655/1090	1654/1086	473/380	473/380	2293/1179	2295/1179	2175/1745	2175/1741
Mcap	63783	63737	63071	64255	42997	43863	287750	287494	94473	93808	1164686	1181726

	Coal India		Cochin Ship✤		Coforge★		Containr Crp✤		Cummins (I)★		Delhivery♠	
PClose	(417.9)	(418.0)	(1333.7)	(1334.3)	(1789.2)	(1793.0)	(488.3)	(488.1)	(5020.0)	(5020.0)	(430.0)	(426.0)
Open	419.0	418.0	1336.0	1335.0	1791.3	1793.0	488.5	489.0	5020.0	5000.0	427.1	426.1
High	420.0	420.0	1379.0	1398.0	1793.1	1841.0	498.0	504.6	5119.8	5119.0	433.2	433.6
Low	409.9	409.7	1333.7	1333.0	1755.2	1754.2	485.5	485.1	5020.0	5000.0	422.1	425.9
Close	411.9	409.9	1363.0	1398.0	1760.0	1841.0	490.0	504.6	5100.0	5099.5	426.0	428.0
Shares	1293K	7701K	63364	1456K	75351	2489K	55755	2242K	23563	502K	123K	1686K
PE	8.1	8.1	52.7	54.1	40.2	42.1	30.0	30.9	57.9	57.9	267.9	269.2
52 Wk H/L	491/370	491/370	1980/1187	1980/1187	2022/1009	2021/1008	562/422	563/421	6143/3803	6100/3833	524/374	524/374
Mcap	253812	252610	35858	36779	77968	81556	37319	38428	141372	141358	31920	32070

	GMR Airports♠		Godrej Cons♠		Godrej Prpty✤		Grasim Ind★		HAL✤		Havells I♠	
PClose	(95.2)	(95.0)	(873.9)	(873.0)	(1680.0)	(1678.2)	(3175.2)	(3173.1)	(4776.5)	(4788.0)	(1092.6)	(1092.0)
Open	95.4	95.5	875.0	875.3	1689.4	1686.9	3192.6	3175.0	4809.7	4804.9	1086.1	1086.0
High	97.8	99.3	885.7	886.0	1720.0	1721.3	3202.0	3209.2	4887.3	4890.0	1102.0	1132.4
Low	95.4	95.4	870.5	870.5	1680.1	1686.6	3171.0	3174.5	4781.5	4780.0	1086.1	1086.0
Close	96.1	99.3	884.0	880.0	1701.0	1691.1	3171.0	3209.2	4801.0	4800.3	1096.0	1132.4
Shares	572K	21945K	320K	1411K	16936	660K	17620	683K	76346	973K	21381	745K
PE	168.6	174.2	43.6	43.4	31.7	31.5	36.9	37.3	34.4	34.4	41.3	42.7
52 Wk H/L	116/84	116/84	1275/854	1274/855	2352/1434	2352/1434	3412/2504	3411/2503	5150/3479	5150/3479	1610/1081	1610/1081
Mcap	101483	104851	90460	90050	51238	50939	215802	218402	321081	321034	68785	71069

	ICICI Bank★		ICICI Lombard		ICICI Prud Life		IDFC First Bank		IIFL Finance★		Indian Bank	
PClose	(1345.0)	(1347.6)	(1482.0)	(1486.7)	(492.0)	(490.5)	(86.2)	(86.3)	(596.5)	(596.5)	(840.0)	(840.5)
Open	1353.0	1351.9	1486.5	1485.7	495.0	494.0	86.2	86.0	599.2	602.0	845.0	845.0
High	1359.1	1359.8	1488.0	1486.8	501.4	501.5	87.2	87.2	614.0	614.3	847.8	848.9
Low	1337.1	1338.9	1466.3	1458.1	491.4	491.1	86.0	85.9	599.0	598.5	835.0	835.0
Close	1337.1	1338.9	1488.0	1458.1	493.8	492.0	86.4	85.9	600.1	600.2	844.8	839.8
Shares	480K	7509K	10939	926K	62835	2241K	471K	27340K	97279	2244K	26288	1400K
PE	17.1	17.1	30.6	30.0	44.6	44.4	32.3	32.2	12.2	12.2	8.9	8.8
52 Wk H/L	1480/1188	1480/1188	2064/1424	2065/1423	707/456	707/455	89/58	89/58	705/409	705/409	1000/694	1001/694
Mcap	959777	961069	74342	72848	71661	71400	74453	74082	25612	25617	113791	113118

	JSW Energy		JSW Steel♠		Jubilant Fd★		Kalyan Jeweller		Kaynes T		KEI Ind★	
PClose	(511.0)	(512.0)	(1256.8)	(1253.4)	(481.8)	(480.2)	(582.0)	(581.5)	(3519.0)	(3520.0)	(4550.0)	(4560.0)
Open	511.1	512.0	1282.8	1270.1	482.1	484.0	585.0	585.0	3531.6	3528.0	4564.5	4560.0
High	517.8	526.0	1299.9	1278.7	502.0	502.0	588.5	588.5	3604.1	3605.9	4648.0	4650.0
Low	509.1	509.0	1262.9	1262.7	481.0	480.3	580.1	580.0	3475.1	3475.0	4535.0	4532.0
Close	517.8	526.0	1268.0	1275.6	498.0	500.0	584.0	581.9	3510.9	3515.0	4648.0	4650.0
Shares	36202	3398K	34929	2378K	87607	2901K	304K	5379K	65264	1267K	11264	573K
PE	47.1	47.8	31.7	31.9	86.9	87.3	41.2	41.1	68.0	68.0	44.6	44.6
52 Wk H/L	617/428	617/428	1350/1025	1351/1073	635/409	635/409	649/327	649/327	7705/2996	7705/2995	5931/3730	5899/3729
Mcap	94938	96441	310089	311948	32861	32993	60313	60091	23600	23628	44435	44454

	Manapp Finance★		Mankind Pharma♠		Marico♠		Maruti Suzuki✤		Max Fin Sre★		Max Health	
PClose	(316.0)	(316.0)	(2295.0)	(2300.0)	(816.8)	(817.0)	(12390.0)	(12338.0)	(1553.1)	(1554.0)	(1033.8)	(1037.0)
Open	319.1	319.0	2297.7	2300.0	822.4	820.1	12365.7	12350.0	1540.4	1538.6	1035.4	1037.0
High	319.9	319.9	2349.0	2329.5	822.4	822.5	12456.2	12458.0	1575.0	1573.6	1058.0	1059.9
Low	315.3	310.0	2289.3	2287.7	801.0	803.9	12145.0	12103.0	1529.4	1538.0	1035.2	1034.9
Close	316.8	319.2	2318.0	2300.7	801.0	803.9	12145.0	12103.0	1575.0	1559.0	1055.0	1049.3
Shares	92883	3823K	80938	485K	82043	2849K	41946	660K	50219	899K	128K	2098K
PE	20.5	20.7	44.9	44.5	55.2	55.4	26.6	26.5	501.6	496.5	68.6	68.2
52 Wk H/L	381/245	382/245	2670/1910	2674/1910	890/690	889/690	17372/12135	17370/12103	1891/1408	1893/1424	1221/904	1222/903
Mcap	29754	29979	95733	95019	104146	104523	381839	380518	54353	53801	102684	102129

	Oberoi Relty		Oil India		ONGC✤		Oracle Fin✤		Page Inds		Patanjali Foods★	
PClose	(1738.8)	(1740.7)	(477.0)	(477.4)	(232.8)	(232.4)	(11619.5)	(11620.0)	(35102.4)	(35020.0)	(354.5)	(354.5)
Open	1737.7	1730.1	479.6	479.0	232.5	232.4	11634.1	11648.0	34975.0	34990.0	353.0	353.1
High	1778.0	1785.0	492.2	482.8	234.3	234.3	11700.0	11896.0	35942.4	36400.0	363.7	367.0
Low	1565.0	1721.0	472.0	472.0	231.8	231.8	11522.0	11515.0	34950.0	34900.0	353.0	353.1
Close	1778.0	1785.0	492.2	475.7	232.5	232.8	11675.0	11896.0	35900.0	36400.0	363.1	367.0
Shares	9959	767K	66174	3704K	509K	11146K	2596	163K	744	32020	170K	2000K
PE	24.4	24.5	9.6	9.3	6.7	6.7	29.8	30.4	51.2	51.9	18.2	18.4
52 Wk H/L	1985/1390	1986/1391	531/396	531/396	308/228	308/228	12413/6232	12540/6235			615/328	615/328
Mcap	64648	64903	80062	77378	292492	292869	101666	103590	40029	40586	39509	39933

	Premier Energie♠		Prestige Est		Radico Khatn★		Rail Vikas Niga		RBL Bank		REC	
PClose	(883.0)	(880.0)	(1444.9)	(1440.1)	(4394.0)	(4380.0)	(201.1)	(201.7)	(404.0)	(404.1)	(311.5)	(310.5)
Open	878.1	880.0	1450.4	1447.0	4380.5	4381.0	201.9	201.8	406.7	406.2	310.5	311.0
High	905.0	905.8	1471.5	1471.6	4459.0	4535.4	210.5	214.3	409.7	415.9	313.7	313.4
Low	878.1	878.3	1440.1	1435.1	4380.5	4381.0	200.8	200.8	405.1	405.0	309.3	309.1
Close	903.0	902.0	1458.0	1435.1	4438.0	4535.4	210.3	214.3	408.0	415.9	311.4	312.0
Shares	101K	3107K	9371	563K	8907	372K	383K	9469K	33764	3793K	162K	4686K
PE	24.6	24.6	55.1	54.3	83.7	85.5	48.8	49.7	70.5	71.8	5.1	5.1
52 Wk H/L	1134/661	1134/660	1805/1090	1805/1090	4748/2505	4747/2500	401/195	401/195	420/262	420/262	390/304	390/304
Mcap	40996	40951	62800	61814	59469	60774	43848	44680	63307	64533	81998	82156

	Sun Pharma♠		Suzlon Energy★		Swiggy♠		Tata Consumer P♠		Tata Elxsi		Tata Motors PV★	
PClose	(1866.0)	(1867.3)	(42.5)	(42.5)	(276.5)	(276.5)	(1015.0)	(1013.7)	(3385.0)	(3381.8)	(314.6)	(314.5)
Open	1868.0	1866.1	42.7	42.9	276.5	277.0	1018.4	1016.2	3401.3	3399.0	310.0	309.6
High	1875.0	1877.2	43.8	43.8	280.0	280.0	1018.4	1018.7	3401.3	3399.0	311.5	310.0
Low	1835.5	1837.3	42.7	42.7	276.0	273.1	1000.5	996.0	3325.3	3266.7	301.6	301.5
Close	1835.5	1837.3	43.3	43.1	277.0	273.1	1002.8	996.0	3340.0	3266.7	303.8	303.8
Shares	22192	2897K	4293K	63471K	1159K	20140K	46258	2077K	19842	297K	773K	18037K
PE	34.9	34.9	18.7	18.7	-	-	60.2	59.7	29.5	28.9	122.5	122.5
52 Wk H/L	2048/1547	2047/1548	61/38	62/38	473/236	474/236	1283/981	1283/986	5950/3325	5950/3267	740/294	740/294
Mcap	440392	440823	59041	58823	76460	75370	99247	98574	20812	20355	111887	111887

	United Spirt✤		Uno Minda★		UPL★		Varun Bever★		Vedanta♠		Vishal Mega	
PClose	(1387.9)	(1390.0)	(1207.0)	(1205.0)	(554.3)	(554.8)	(416.0)	(415.5)	(256.6)	(257.5)	(101.1)	(101.2)
Open	1383.8	1382.0	1208.3	1213.2	554.6	554.0	416.5	416.9	258.0	258.0	101.3	101.2
High	1405.0	1405.0	1249.0	1284.0	566.6	580.0	425.4	425.4	261.9	267.6	102.1	102.7
Low	1380.2	1371.0	1207.3	1206.8	553.9	553.4	416.5	416.3	258.0	258.0	100.4	100.2
Close	1390.0	1371.0	1240.0	1284.0	559.9	580.0	421.8	422.0	261.3	267.6	101.0	102.7
Shares	5470	842K	149K	1278K	271K	3779K	330K	7582K	180K	8484K	236K	10786K
PE	54.6	53.8	58.5	60.6	23.9	24.7	42.1	42.2	13.9	14.4	53.2	54.0
52 Wk H/L	1576/1210	1563/1211	1382/994	1382/994	812/550	812/550	556/381	556/381	795/250	795/250	153/99	153/99
Mcap	101102	99720	71604	74145	47250	48946	142674	142725	102159	104642	47317	48090

	Asian Paints♠ BSE	NSE	Astral♠ BSE	NSE	Ather Energy♠ BSE	NSE	Au Small Fin BSE	NSE	Aurob Pharma♠ BSE	NSE	Avenue Supermar BSE	NSE
PClose	(2454.0)	(2454.0)	(1395.8)	(1398.9)	(1550.0)	(1550.0)	(1036.6)	(1039.3)	(1683.9)	(1690.0)	(3715.0)	(3711.2)
Open	2454.0	2455.7	1403.3	1400.0	1550.0	1550.0	1043.2	1040.5	1687.9	1683.2	3708.1	3711.1
High	2475.2	2474.0	1425.0	1427.7	1614.9	1640.0	1046.3	1058.6	1735.0	1734.0	3755.0	3755.8
Low	2405.0	2438.0	1396.1	1397.5	1550.0	1548.1	1034.2	1033.3	1676.4	1676.1	3680.0	3680.0
Close	2405.0	2451.3	1425.0	1427.7	1610.0	1640.0	1041.0	1058.6	1735.0	1734.0	3738.0	3749.9
Shares	21753	1001K	12451	1389K	334K	5010K	10161	1252K	35962	1209K	34805	881K
PE	47.3	48.2	64.6	64.7	-	-	27.4	27.8	26.4	26.4	79.7	80.0
52 Wk H/L	2986/2116	2986/2115	1768/1312	1769/1312	1742/535	1744/535	1145/704	1144/704	1735/1066	1734/1067	4809/3529	4798/3529
Mcap	230688	235129	38290	38362	63853	65042	78135	79456	99832	99774	243811	244587

	BHEL★		Biocon✤		Bosch		BPCL		Britannia♠		BSE★	
PClose	(428.0)	(429.2)	(380.0)	(380.0)	(47840.1)	(47735.0)	(306.8)	(307.0)	(4990.0)	(4982.0)	(-)	(3259.0)
Open	428.9	428.4	380.0	380.1	47850.0	47850.0	308.9	308.6	4986.0	4982.0	-	3259.0
High	435.5	439.9	388.8	388.0	48650.0	48650.0	314.1	314.2	5025.0	5026.5	-	3296.0
Low	428.0	427.3	379.5	379.3	47700.0	47000.0	307.5	308.3	4967.3	4968.0	-	3241.0
Close	434.0	439.9	385.0	385.0	47800.0	47000.0	307.5	314.0	5016.0	4998.0	-	3266.4
Shares	460K	7669K	91962	7901K	572	27389	93902	9440K	8472	347K	-	2075K
PE	62.1	62.9	85.9	85.9	59.7	58.7	8.6	8.8	46.4	46.2	-	47.1
52 Wk H/L	447/220	447/230	447/337	447/337	49630/28650	50000/28610	392/267	392/267	6270/4940	6271/4933	-/-	4447/2022
Mcap	151121	153175	62743	62743	141010	138650	133409	136229	120835	120402	-	133236

	Divis Lab★		Dixon Tech★		DLF★		Dr Reddys♠		Eicher Motor♠		Eternal♠	
PClose	(9346.5)	(9323.0)	(13271.0)	(13290.0)	(641.7)	(640.0)	(1172.1)	(1175.0)	(7510.3)	(7493.5)	(323.9)	(322.4)
Open	9331.0	9346.5	13306.7	13290.0	639.6	640.0	1184.8	1182.6	7516.0	7523.5	327.6	328.5
High	9445.7	9445.0	13381.7	13383.0	653.5	653.7	1207.5	1207.5	7570.0	7569.0	329.6	329.8
Low	9330.0	9328.5	13070.0	13005.0	631.1	640.0	1171.1	1182.1	7480.0	7477.0	325.7	325.7
Close	9367.0	9375.0	13100.0	13005.0	631.1	644.4	1171.1	1185.0	7500.0	7516.0	326.6	326.9
Shares	23386	692K	23599	371K	572K	2890K	128K	3003K	6650	420K	890K	17697K
PE	83.5	83.5	42.7	42.4	36.3	37.1	30.3	30.7	35.4	35.5	725.7	726.3
52 Wk H/L	10000/5638	9615/5637	18472/9605	18471/9600	790/489	790/489	1414/1080	1415/1101	8233/6439	8230/6442	368/213	368/213
Mcap	248647	248859	80107	79526	156204	159496	97752	98912	205875	206314	315134	315423

	HCL Techno★		HDFC AMC✤		HDFC Bank♠		HDFC Std Life		Hero MotoCorp★		HFCL♠	
PClose	(1256.0)	(1258.3)	(2384.5)	(2387.7)	(713.0)	(713.0)	(556.8)	(557.0)	(5325.0)	(5325.0)	(209.6)	(209.4)
Open	1257.9	1258.3	2395.2	2405.6	716.0	715.3	558.0	557.1	5325.0	5325.0	213.0	213.9
High	1260.0	1260.8	2437.7	2439.0	733.5	733.8	564.3	565.0	5360.0	5362.5	219.9	219.4
Low	1235.8	1235.6	2395.2	2401.2	715.1	715.3	552.2	551.0	5289.7	5285.5	208.8	208.5
Close	1238.0	1249.3	2425.0	2425.0	729.1	731.0	552.2	551.0	5300.0	5285.5	214.7	215.7
Shares	43337	2886K	62216	1041K	5055K	39401K	182K	5599K	15765	689K	436K	6280K
PE	18.5	18.7	35.3	35.3	14.2	14.3	60.7	60.6	19.2	19.1	57.4	57.7
52 Wk H/L	1770/1030	1780/1030	2965/2206	2967/2206	1020/682	1021/682	797/509	797/509	6390/4672	6389/4672	257/60	257/60
Mcap	335950	339016	103989	103989	1124032	1126961	119960	119699	106080	105789	32862	33017

	Indian Hotel♠		Indus Towers		IndusInd Bank		Info Edge★		Infosys✤		Inox Wind	
PClose	(726.3)	(726.7)	(380.3)	(381.4)	(960.0)	(958.2)	(1268.2)	(1265.0)	(1056.1)	(1058.6)	(74.3)	(74.1)
Open	726.0	725.9	381.2	380.9	960.2	963.8	1265.0	1265.0	1060.1	1061.9	74.3	74.3
High	742.8	743.0	384.0	382.5	970.0	969.3	1283.2	1284.0	1062.6	1061.9	75.9	76.8
Low	720.6	722.6	376.4	375.9	957.1	955.3	1255.0	1251.2	1038.1	1038.0	74.3	74.3
Close	732.3	732.8	384.0	375.9	957.1	966.3	1255.0	1251.2	1050.2	1051.4	75.0	76.8
Shares	100K	3256K	52053	4696K	38143	6251K	142K	1486K	363K	22125K	552K	10977K
PE	54.0	54.0	14.2	13.9	56.4	56.9	56.0	55.8	13.7	13.7	37.7	38.6
52 Wk H/L	781/565	781/565	482/338	482/338	1078/711	1078/711	1440/909	1434/908	1728/984	1728/982	159/68	159/68
Mcap	104228	104300	101305	99168	74571	75288	81374	81128	426176	426683	12953	13273

	KFin Technologi		Kotak Mah Bank♠		KPIT Techno		L & T★		L&T Finan		Laurus Labs★	
PClose	(896.0)	(897.0)	(417.0)	(416.5)	(559.3)	(559.3)	(3830.1)	(3836.2)	(302.0)	(302.3)	(1956.4)	(1948.1)
Open	902.6	900.0	415.3	415.5	560.0	559.3	3848.9	3846.0	302.5	303.0	1960.0	1962.0
High	915.6	930.0	419.3	419.2	560.0	559.5	3896.0	3898.0	314.0	314.3	1981.3	1982.0
Low	895.2	895.0	411.2	412.5	539.2	532.0	3848.9	3846.0	302.1	302.5	1955.3	1954.0
Close	900.0	930.0	412.8	412.5	543.0	532.0	3860.0	3885.0	311.0	312.8	1955.3	1954.0
Shares	26968	539K	138K	15461K	229K	3944K	50930	1548K	143K	4648K	54069	2656K
PE	44.4	45.9	20.5	20.5	23.8	23.4	29.8	30.0	24.3	24.5	96.6	96.5
52 Wk H/L	1217/785	1215/785	453/345	453/346	1309/539	1310/532	4440/3289	4440/3288	339/232	339/235	1981/823	1982/823
Mcap	15558	16077	410641	410343	14886	14584	531097	534537	77947	78399	105642	105575

	Mazagon Dock✤		MCX★		Motilal Oswl♠		Mphasis		Muthoot Finance		Nat Alum✤	
PClose	(2216.9)	(2210.0)	(3265.0)	(3265.2)	(986.7)	(988.7)	(2310.0)	(2320.0)	(2772.0)	(2770.2)	(355.5)	(355.7)
Open	2210.0	2209.0	3263.1	3257.5	990.1	988.7	2310.8	2322.9	2774.9	2796.6	361.4	359.8
High	2270.1	2280.0	3313.6	3314.9	1008.1	1010.0	2340.8	2327.9	2851.4	2852.0	363.0	363.2
Low	2204.1	2205.1	3232.0	3230.1	961.5	988.7	2275.0	2275.0	2774.9	2784.3	356.3	350.5
Close	2252.0	2280.0	3249.0	3260.0	1005.5	1010.0	2309.9	2300.4	2840.0	2841.1	357.0	350.5
Shares	88510	851K	478K	2197K	7665	740K	119K	650K	38943	655K	130K	5809K
PE	31.8	32.2	53.7	53.9	30.6	30.8	22.8	22.7	10.0	10.0	9.7	9.5
52 Wk H/L	3061/2057	3061/2057	3480/1546	3480/1545	1097/616	1097/615	3010/2034	3013/2013	4149/2722	4150/2671	445/199	445/199
Mcap	90841	91971	82850	83130	60632	60903	44108	43926	114017	114062	65568	64374

	PAYTM♠		Persistent S✤		PG Elect♠		Phoenix Mill★		Pidilite Ind♠		Piramal Pharma	
PClose	(1762.0)	(1763.0)	(5480.0)	(5473.0)	(530.7)	(529.3)	(1872.7)	(1872.2)	(1553.1)	(1551.5)	(204.5)	(204.7)
Open	1795.4	1795.4	5480.0	5476.0	529.3	529.4	1876.4	1880.0	1557.2	1559.9	204.8	204.5
High	1825.0	1849.9	5488.2	5500.0	541.5	541.5	1922.4	1923.2	1598.0	1598.9	210.0	210.1
Low	1765.5	1765.0	5388.7	5389.0	529.3	529.2	1876.4	1877.9	1557.2	1559.9	204.6	204.5
Close	1825.0	1849.9	5433.0	5416.0	538.0	529.2	1877.0	1877.9	1566.1	1572.1	208.0	208.2
Shares	171K	4640K	35569	495K	45362	570K	6130	422K	18096	1142K	110K	2927K
PE	144.3	146.2	43.1	42.9	74.9	73.7	51.6	51.6	60.2	60.4	35.7	35.8
52 Wk H/L	1857/947	1856/931	6597/4243	6599/4245	645/437	644/437	2169/1465	2170/1466	1708/1259	1708/1259	232/133	232/132
Mcap	117092	118690	85711	85443	15430	15176	67140	67172	159413	160024	27692	27713

	Reliance Ind		Sagility		SAIL		Samvardhana Mot♠		SBI♠		SBI Card & Pay	
PClose	(1240.8)	(1243.9)	(44.8)	(44.6)	(175.1)	(175.0)	(162.0)	(161.9)	(984.5)	(988.7)	(637.8)	(637.0)
Open	1245.5	1245.0	44.5	44.6	176.2	176.5	161.8	161.9	992.8	992.0	635.2	636.0
High	1247.4	1247.3	46.2	46.2	180.0	179.8	165.2	165.4	994.5	996.2	640.3	651.2
Low	1234.0	1226.4	44.5	44.6	176.1	176.0	161.8	161.8	985.1	985.1	631.1	630.7
Close	1234.0	1226.4	45.6	45.7	180.0	177.3	164.4	162.6	989.8	996.2	637.0	651.2
Shares	482K	15123K	2097K	17451K	372K	11882K	1260K	19068K	212K	5699K	48668	3242K
PE	22.3	22.2	20.7	20.8	15.4	15.2	37.9	37.5	10.9	11.0	26.6	27.2
52 Wk H/L	1611/1234	1612/1226	58/36	58/36	210/124	210/124	173/101	173/101	1235/849	1235/849	965/567	965/565
Mcap	1669848	1659631	21361	21375	74350	73247	173514	171583	913665	919572	60619	61966

	Tata Power♠		Tata Steel♠		Tata Techno★		TCS♠		Tech Mahindra✤		Titan Company♠	
PClose	(368.3)	(369.0)	(188.0)	(187.3)	(758.6)	(758.8)	(2196.0)	(2190.0)	(1559.0)	(1561.0)	(4859.0)	(4841.0)
Open	365.4	364.8	186.2	186.4	762.0	761.4	2179.5	2177.2	1559.0	1558.3	4846.0	4851.0
High	374.8	374.8	188.0	188.0	762.0	761.4	2179.5	2177.3	1559.0	1561.2	4895.0	4864.5
Low	360.9	360.9	184.8	185.5	716.3	716.1	2101.0	2101.2	1522.6	1523.1	4756.5	4772.0
Close	374.8	374.8	184.8	185.5	723.3	722.5	2101.0	2105.0	1530.7	1537.1	4756.5	4798.5
Shares	555K	5103K	1086K	29014K	83381	2216K	340K	6875K	35279	3114K	34914	1066K
PE	30.4	30.4	19.5	19.6	45.1	45.1	14.2	14.2	28.2	28.3	72.4	73.0
52 Wk H/L	465/342	465/343	224/160	224/160	890/508	891/507	3337/1976	3350/1977	1850/1304	1854/1304	5187/3307	5187/3303
Mcap	119760	119760	230633	231619	29370	29335	760163	761610	150030	150657	422282	426011

	Vodafone Idea		Voltas♠		Waaree Energies		Wipro★		YES Bank★		Zydus Lifescien♠	
PClose	(14.2)	(14.2)	(1136.7)	(1135.0)	(2471.4)	(2473.0)	(166.4)	(166.4)	(23.1)	(23.1)	(1137.3)	(1135.1)
Open	14.3	14.3	1136.7	1136.0	2493.3	2490.1	167.2	166.9	23.2	23.2	1150.7	1150.7
High	14.4	14.4	1145.2	1145.3	2545.3	2560.7	167.2	166.9	23.4	23.4	1167.2	1167.3
Low	14.1	13.9	1128.8	1110.9	2483.8	2486.1	163.4	163.3	23.1	22.7	1148.5	1147.7
Close	14.1	13.9	1131.0	1110.9	2535.1	2560.7	166.0	166.8	23.1	22.7	1153.0	1160.0
Shares	13923K	350367K	20980	597K	30371	1224K	669K	23606K	3514K	73564K	122K	2789K
PE	-	-	80.2	78.7	18.1	18.3	12.4	12.5	19.3	18.9	23.6	23.7
52 Wk H/L	16/8	16/8	1582/1126	1583/1111	3720/2402	3719/2403	273/163	273/163	26/17	26/17	1206/836	1205/836
Mcap	152764	150814	37425	36760	72922	73659	164422	165244	72570	71314	115012	115710

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, sell securities for any publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement of the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated Monday, September 07, 2026 ("Letter of Offer" or "LOF") for the purpose of the offering of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

PARTY CRUISERS LIMITED

Please scan the QR Code to view the Letter of Offer

PARTY CRUISERS LIMITED

(Corporate Identification Number: L63040MH1994PLC083438)

Registered Office: 303/304/305 Simran Plaza, Khar 4th Road Next to Regal Enclave Hotel, Khar West, MumbaiCity, Mumbai, Maharashtra, India, 400052

Contact Number: +91-9967160222 **E-mail:** compliance.partycruisersindia@gmail.com; **Website:** www.partycruisersindia.com; **Company Secretary and Compliance Officer:** Ms. Riddhima Gupta

Party Cruisers Limited, our Company was originally incorporated as Party Cruisers Private Limited on December 02, 1994, a private limited company under the provisions of Companies Act, 1956 pursuant to Certificate of Incorporation issued by RoC, Mumbai, Maharashtra. Further, the name of the Company was changed to Party Cruisers Limited" pursuant to shareholders resolution passed at the General Meeting of our Company held on September 03, 2013, and the name of our Company was changed to "Party Cruisers Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated November 13, 2013, issued by RoC, Mumbai, Maharashtra. For further details of change of name of our Company, please see "General Information" beginning on page 45 of the Letter of Offer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. ZUZER HATIM LUCKNOWALA AND MS. RACHANA LUCKNOWALA

ISSUE OF UPTO 20,00,000 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10.00/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹120.00/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹110.00/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹2,400 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 6 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, BEING MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 237 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares.

INVESTORS ARE REQUESTED TO NOTE THAT THE RATIO IN WHICH THE RIGHTS EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE ISSUED MAY RESULT IN THE CREATION OF ODD LOTS. INVESTORS HOLDING SUCH ODD LOTS MAY BE REQUIRED TO PURCHASE OR SELL ADDITIONAL EQUITY SHARES TO CONSOLIDATE THEIR HOLDINGS INTO MARKETABLE LOT OF 1,000 EQUITY SHARES. GIVEN THE LIMITED LIQUIDITY AND LOWER TRADING VOLUMES GENERALLY OBSERVED ON THE SME PLATFORM OF THE STOCK EXCHANGE, INVESTORS HOLDING SUCH ODD LOTS MAY FACE DIFFICULTIES IN SELLING THEIR EQUITY SHARES. THIS MAY ADVERSELY AFFECT THE LIQUIDITY OF THE EQUITY SHARES AND THE ABILITY OF INVESTORS TO EXIT THEIR INVESTMENT.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATIONS*	ISSUE CLOSES ON#
MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026	THURSDAY, OCTOBER 01, 2026	MONDAY, OCTOBER 05, 2026

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through on-market renunciation is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.*

***Our Board will have the right to extend the Issue Period as it may deem fit, provided that the Issue shall not be kept open in excess of 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ASBA*

ASBA* – Simple, Safe, Smart way of application. Make use of it!
***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking bank account. For further details, check section on ASBA below.**

Facilities for application in this Issue:

ASBA Facility:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Eligible Equity Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Eligible Equity Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through the ASBA Process" beginning on page No. 247 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated 25th September, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated 2nd January, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such ASBA Application.

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders

Pursuant to provision of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account only and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN No. INE06ZX20015subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements see "Terms of Issue – Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 238 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the Credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of so subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company, not later than two clear working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts, at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in stipulated time then their Rights Entitlements shall lapse and shall not be eligible to apply in this Issue. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited. Even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an Application to apply for Rights Equity Shares offered under the Issue for subscribing to the Rights Equity Shares offered under the Issue.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., https://rights.kfintech.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company.

In this regard, our Company has made necessary arrangements with NSDL and CDSL for crediting of the Rights Entitlements to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders in a dematerialized form. A separate ISIN for the Rights Entitlements has also been generated which is ISIN: INE06ZX20015. The said ISIN shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date. The said ISIN shall be suspended for transfer by the Depositories post the Issue Closing Date.

If Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date, have not provided the details of their demat accounts to our Company or to the Registrar, they are required to provide their demat account details to our Company or the Registrar not later than two clear working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their respective demat accounts, at least one day before the Issue Closing Date. Such Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form can update the details of their respective demat accounts on the website of the Registrar (i.e., https://rights.kfintech.com). Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after the Rights Entitlements is credited to their respective demat accounts.

Procedure for Application: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible Shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 252 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: An Investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, refer https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.

Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date, please see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 252 of the Letter of Offer.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of Rights Equity Shares in dematerialised form: Please note that the Rights Equity Shares applied for in this Issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such Investor on the Record Date.

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "Party Cruisers Suspense Escrow Demat Account") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or suspended for debit/credit or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process: An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India. Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1) Name of our Company, being "Party Cruisers Limited";
2) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
3) Registered Folio No./DP and Client ID No.;
4) Number of Equity Shares held as on Record Date;
5) Allotment option – only dematerialised form;
6) Number of Rights Equity Shares entitled to;
7) Total number of Rights Equity Shares applied for;
8) Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any;
9) Total number of Rights Equity Shares applied for;
10) Total amount paid at the rate of Rs. 120/- for Rights Equity Shares issued. However, Rs. 30/- is to be paid on Application;
11) Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
12) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address, branch of the SCSB with which the account is maintained and a copy of the RBI approval obtained pursuant to Rule 7 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019;
13) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue;
14) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
15) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
16) In addition, all such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/We understand that neither the Rights Entitlement nor the Equity Shares have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the "United States") except in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/we understand that this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/we understand that none of the Company, the Registrar or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar, or any other person acting on behalf of the Company has reason to believe is in the United States, or if such person is outside India and the United States, such person is not a corporate shareholder, or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/We will not offer, sell, or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/We understand and agree that the Rights Entitlement and Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S"), or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States, and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S.

I/We acknowledge that the Company, and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements. In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company, the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at https://rights.kfintech.com.

I/We acknowledge that Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date."

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Monday, 5th October, 2026 i.e., Issue Closing Date. The Board may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Basis of Allotment" on page No. 260 of the Letter of Offer.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as prescribed by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Eligible Equity Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlements or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

Procedure for Renunciation of Rights Entitlements: The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges; or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. Such renunciation shall result in renouncement of the Rights Equity Shares. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism. Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements. Our Company accepts no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges, and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

a. On Market Renunciation:

The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under the ISIN INE06ZX20015 that shall be allotted for the Rights Entitlement subject to requisite approvals. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time. The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlement.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Monday, 21st September, 2026 to Thursday, 01st October, 2026 (both days inclusive).

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock brokers by quoting the ISIN – INE06ZX20015 (for Rights Entitlement) that shall be allotted for the Rights Entitlement and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to sell. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2' rolling settlement basis, where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

b. Off Market Renunciation:

The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date. The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN (for Rights Entitlement) that shall be allotted for the Rights Entitlement, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

Listing and trading of the Rights Equity Shares to be issued pursuant to the Issue:

Subject to receipt of the listing and trading approvals, the Rights Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for trading on the Stock Exchanges. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Rights Equity Shares Allotted pursuant to this Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary procedures for listing and commencement of trading in the Rights Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has received in-principle approval from the BSE through letter bearing reference number NSE/LIST/C/2026/0698 dated 27th August, 2026. Our Company will apply to the Stock Exchanges for final approvals for the listing and trading of the Rights Equity Shares subsequent to their Allotment. No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Rights Equity Shares or the price at which the Rights Equity Shares offered under this Issue will trade after the listing thereof.

For an applicable period, from the Call Record Date, the trading of the Rights Equity Shares would be suspended under the applicable law. The process of corporate action for crediting the fully paid-up Rights Equity Shares to the Investors' demat accounts, may take such time as is customary or as prescribed under applicable law from the last date of payment of the amount under the Call notice for the final Call.

The existing Equity Shares are listed on NSE (NSE Symbol: PARTYCRUS) under the ISIN: INE06ZX20015. The Rights Equity shall be credited to temporary ISINs which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from such temporary ISINs and credited to the existing ISIN as fully paid-up Equity of our Company and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

The listing and trading of the Rights Equity Shares issued pursuant to this Issue shall be based on the current regulatory framework then applicable. Accordingly, any change in the regulatory regime would affect the listing and trading schedule. In case our Company fails to obtain listing or trading permission from the Stock Exchanges, we shall refund through verifiable means/unblock the respective ASBA Accounts, the entire monies received/blocked within four days of receipt of intimation from the Stock Exchange, rejecting the application for listing of the Rights Equity Shares, and if any such money is not refunded/unblocked within four days after our Company becomes liable to repay it, our Company and every director of our Company who is an officer-in-default shall, on and from the expiry of the fourth day, be jointly and severally liable to repay that money with interest at rates prescribed under applicable law.

Listing: Our Company will apply to NSE-SME platform for final approval for the listing and trading of the Rights Equity Shares subsequent to their Allotment. No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Rights Equity Shares or the price at which the Rights Equity Shares offered under the Issue will trade after the listing thereof.

Disclaimer clause of NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to page 231 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the NSE.

Dispatch and Availability of issue materials: In accordance with the SEBI (ICDR) Regulations and relevant SEBI circulars on Rights Issue and ASBA Circular, our Company will send/dispatch at least 3 (Three) days before the Issue Opening Date, the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, Application Form and other issue material (i) only to e-mail addresses of the resident Eligible Equity Shareholders who have provided their e-mail addresses; (ii) physical delivery only to the Indian address of resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, whose e-mail addresses are not available with our Company or the Eligible Equity Shareholders have not provided the valid email address to our Company; (iii) physical delivery only to the Indian addresses of the non-resident Eligible Equity Shareholders, on a reasonable effort basis, who have provided an Indian address to our Company; and (iv) to the e-mail addresses of the foreign corporate or institutional shareholders, and in each case who make a request in this regard. The Letter of Offer will also be provided by our Company to any existing Shareholder who makes a request in this regard.

Further, the Letter of Offer will be sent/dispatched, by the Registrar to the Issue on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses and have made a request in this regard. In case the Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case the Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Eligible Equity Shareholders can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of:

- our Company at https://partycruisersindia.com
- the Registrar at https://rights.kfintech.com
- the Stock Exchanges at www.bseindia.com

Eligible Equity Shareholders, in order to update the respective Indian addresses, a separate request to be sent to the Registrar and to update the email addresses/mobile numbers in the records maintained by the Registrar or our Company, should visit https://rights.kfintech.com

Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form may apply, along with the requisite application money, by using the application forms available on the websites above, or on plain paper, with the same details as per the application form available online.

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar to the Issue's website at https://rights.kfintech.com, by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (https://partycruisersindia.com).

Please note that neither our Company nor the Registrar shall be responsible for not sending the physical copies of issue materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form attributable to non-availability of the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit. Resident Eligible Equity Shareholders, who are holding Equity Shares in physical form as on the Record Date, can obtain details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar by entering their Folio Number.

Allotment Banker Account – Kotak Mahindra Bank

Bankers to the Issue and Refund Banker – Kotak Mahindra Bank

For Risk Factors and other details, kindly refer page No. 25 of the Letter of Offer

REGISTRAR TO THE ISSUE

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
Selenium, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddi, Hyderabad, Telangana, India, 500032
Telephone: +91 40 67162222/1800309001, **Fax No:** +91-40-67161563
Investor Grievance ID: einward.ris@kfintech.com
Website: https://www.kfintech.com
Contact Person: Mr. Murali Krishna
SEBI Registration No.: INR000000221
CIN: L72400MH2017PLC444072

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

PARTY CRUISERS LIMITED

Party Cruisers Limited
Ms. Riddhima Gupta, Company Secretary & Compliance Officer
Corporate office: 301, 3rd Floor, Raheja Point 1, Vakola East, Santacruz, Mumbai 400055
Contact No: +91 9967160222
E-mail-id: compliance.partycruisersindia.com
Website: https://partycruisersindia.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company and Compliance Officer for any Pre Issue and post-Issue related matters. All grievances related to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue with a copy to SCSB, giving complete details such as name, address, contact number, email address of the sole first holder, folio number or demat account of the applicant, number of equity shares applied for, amount blocked, ASBA account number, and the Designated branch of SCSB where the Application Form or the Plain Application as the case may be submitted by the ASBA Investors.

Date: September 18, 2026

Place: Mumbai

emami LIMITED

CIN: L63993WB1983PLC036030

Registered Office: Emami Tower, 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata - 700107, West Bengal, India

Tel. No.: +91- 33-66136264

Website: www.emamiltd.in; **Email:**investors@emamigroup.com

Contact Person: Mr. Arpit Shah, ACS, Compliance Officer to the Buyback

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF EMAMI LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This public announcement (the "Public Announcement") is being made in relation to the Buyback (as defined hereinafter) of Equity Shares (as defined hereinafter) of Emami Limited (the "Company") from the open market through BSE and NSE, collectively referred to as "Stock Exchange" mechanism, pursuant to the provisions of Regulation 16(iv)(b) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (including any statutory modification(s) or amendment(s) from time to time) (the "Buyback Regulations") and contains the disclosures as specified in Schedule IV to the Buyback Regulations read with Schedule I of the Buyback Regulations.

Certain figures contained in this Public Announcement, including financial information, have been subjected to rounding-off adjustments and presented in whole numbers. In certain instances, (i) the sum or percentage, change of such numbers may not conform exactly to the total figure given; (ii) the sum of the numbers in a column or row in certain tables may not conform exactly to the total figure given for that column or row. Further, certain numerical information in this Public Announcement has been presented in "lakhs". One lakhs represents 1,00,000.

'Working Days' means any working days of the Securities and Exchange Board of India.

OFFER FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES OF EMAMI LIMITED FROM OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGE(S)

PART A - Disclosures in accordance with Schedule I of the Buyback Regulations

1. DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 Pursuant to the provision 52A of Article of Association of the Company and the provisions of Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and other relevant Rules made thereunder, as applicable, each as amended from time to time ("**Companies Act**") (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactments from time to time), the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("**Buyback Regulations**"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**Listing Regulations**") (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactments from time to time) and Article 52A of the Articles of Association of the Company, and subject to such other approvals, permissions, consents, exemptions, and sanctions of the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), the Registrar of Companies, Kolkata -I at Kolkata (the "**ROC**") and / or other authorities, institutions or bodies, as may be applicable (together with SEBI and ROC, the "**Appropriate Authorities**"), as may be necessary, and subject to such conditions, alterations, amendments and modifications as may be prescribed or imposed by the Appropriate Authorities while granting such approvals, permissions, consents, exemptions and sanctions which may be agreed to by the Board of Directors of the Company (the "**Board**" which expression shall be deemed to include any committee constituted by the Board and / or officials, which the Board may constitute / authorise to exercise its powers, including the powers conferred by the board resolution), the Board at its meeting held on September 17, 2026 ("**Board Meeting**"), approved the buyback of fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 1 (Rupee One Only) ("**Equity Shares**") of the Company, each from its shareholders / beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group, persons in control (and their associates)), from the open market through Stock Exchange mechanism which is not more than 10% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company, which is based on the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2026, whichever sets out a lower amount, for an aggregate amount not exceeding ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only) ("**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding ₹ 475.00 (Rupees Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash from the open market through Stock Exchanges ((the process being referred hereinafter as "**Buyback**"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include any other expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees, advisory fees, intermediaries fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses if any, brokerage, costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and any other applicable taxes if any, stamp duty and other incidental and related expenses (collectively referred to as "**Transaction Costs**").

1.2 The Maximum Buyback Size represents 9.28% and 9.98% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2026, respectively (being the latest available audited standalone and consolidated financial statements of the Company) which is not more than 10% of the total paid-up capital and free reserves of the Company in accordance with the proviso to the Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and Section 68(2)(b) of the Companies Act.

1.3 Subject to the market price of the Equity Shares being equal to the Maximum Buyback Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 59,36,842 (Fifty Nine Lakhs Thirty Six Thousand Eight Hundred and Forty Two Only) Equity Shares (**"Maximum Buyback Shares"**), representing approximately 1.36% which is less than 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as of March 31, 2026 and approximately 1.36% of the total paid-up equity share capital of the Company as on the date of the Board Meeting and Public Announcement. The actual number of equity shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the equity shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the number of Equity Shares bought back could exceed the Maximum Buyback Shares, but will always be subject to the Maximum Buyback Size i.e., ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only). The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the Listing Regulations, during the Buyback period and upon completion thereof.

1.4 Unless otherwise permitted under applicable law, the Company shall utilize atleast 75% of the Maximum Buyback Size i.e. ₹ 21,150.00 Lakhs (Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Fifty Lakhs Only) ("**Minimum Buyback Size**") towards the Buyback and accordingly, based on the Maximum Buyback Price and Minimum Buyback Size, the Company will purchase an indicative minimum number of 44,52,632 (Forty Four Lakhs Fifty Two Thousand Six Hundred and Thirty Two) Equity Shares ("**Minimum Buyback Shares**"). Further, atleast 40% of the Maximum Buyback Size i.e. ₹ 11,280.00 Lakhs (Rupees Eleven Thousand Two Hundred and Eighty Lakhs Only) shall be utilized within the initial half from the date of the opening of the Buyback i.e. Tuesday, September 22, 2026.

1.5 Buy-back period shall in any case close within sixty-six working days from the date of opening of the Buyback i.e. Tuesday, December 29, 2026. The Board (or the buyback committee constituted by the Board and empowered to exercise its powers in relation to the Buyback), shall determine, at its discretion, the time frame for completion of the Buyback and may close the Buyback (which shall not be longer than sixty-six Working Days from the date of commencement of the Buyback or such other period as may be permitted under the Act and/or Buyback Regulations or as may be directed by the appropriate authorities) ("**Maximum Buyback Period**") after the Minimum Buyback Size has been reached, after giving appropriate notice for such closure and on completing all formalities in this regard, in accordance with the Act and/or Buyback Regulations.

1.6 The company shall, within one working day from the date of public announcement, send an intimation through electronic mode regarding the open market buy-back offer to those persons who were its shareholders as on the date of making the public announcement. Buyback Offer shall open not later than four Working Days from the date of the public announcement.

1.7 The Buyback will be implemented by the Company out of its free reserves or such other sources as may be permitted by law and in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations, and in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii), 5(i)(b), and 16 of the Buyback Regulations, by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except 'all or none' order matching system (as defined below), as provided under the Buyback Regulations and subject to the restrictions on placement of bids, price and volume as specified by the Board. Further, as required under the Companies Act and Buyback Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are locked-in or non-transferable, in the Buyback, until the pendency of the lock-in or until the Equity Shares become transferable, as applicable. There are no partly paid-up Equity Shares with calls in arrears of the Company.

1.8 The Buyback is subject to receipt of such sanctions and approvals from statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, including the SEBI, RoC and the Stock Exchanges.

1.9 The Company has obtained the prior consent from its lenders for the Buyback and it is confirmed that there is no breach of any covenant with such lenders. The Buyback from erstwhile overseas corporate bodies and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time.

1.10 A copy of this Public Announcement is available on the Company's website (www.emamiltd.in) and is available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), website of NSE (www.nseindia.com), website of BSE (www.bseindia.com) and the website of manager to the Offer (www.iiflcapital.com) during the period of the Buyback.

2. NECESSITY FOR THE BUYBACK AND DETAILS THEREOF

2.1 The Buyback is being undertaken by the Company after taking into account the strategic and operational cash requirements of the Company in medium term and for returning surplus funds to the members in an effective and efficient manner. The Buyback will help the Company achieve the following objectives: (i) optimize returns to shareholders; and (ii) enhance overall shareholders' value.

The Buyback is being proposed, inter-alia, for the following reasons:

a) The Buyback gives the Company an opportunity to distribute surplus cash to its shareholders in proportion to their shareholding;

b) The Buyback may help in improving return on equity and other financial ratios, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value; and

c) The Buyback gives an option to the shareholders to either participate in the Buyback and receive cash in lieu of equity shares accepted under the Buyback or they may choose not to participate in the Buyback and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding in the Company, post the Buyback, without any additional investment.

2.2 The Buyback may lead to reduction in outstanding Equity Shares, improvement in earnings per equity share, and enhanced return on invested capital. The Buyback will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

2.3 The Board at its meeting held on September 17, 2026, considered the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the last audited financial statements as on March 31, 2026, and considering these, the Board decided to approve the Buyback of Equity Shares at a Maximum price of ₹ 475.00 per Equity Share for an aggregate sum not exceeding ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only) excluding the Transaction Costs for distributing to the shareholders holding Equity Shares of the Company through the Buyback.

3. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUYBACK AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES

3.1 The maximum amount of funds required for the Buyback will aggregate up to ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only), 9.28% and 9.98% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company, which is not more than 10% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company based on the lower of the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2026 in accordance with the proviso to the Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and Section 68(2)(b) of the Companies Act.

3.2 The Maximum Buyback Size does not include any Transaction Cost.

3.3 The funds for the implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves of the Company or such other sources as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act. Borrowed funds from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

4. MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

4.1 The indicative maximum number of Equity Shares at the Maximum Buyback Price and the Maximum Buyback Size bought back would be 59,36,842 (Fifty Nine Lakhs Thirty Six Thousand Eight Hundred and Forty Two Only) Equity Shares, representing approximately 1.36% which is less than 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as of March 31, 2026 and approximately 1.36% of the total paid-up equity share capital of the Company as on the date of the Board Meeting and Public Announcement

4.2 The actual number of equity shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the equity shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Maximum Buyback Shares, but will always be subject to the Maximum Buyback Size i.e., ₹ 28,200 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only).

4.3 The Company shall utilise at least 75% of amount earmarked as the Maximum Buyback Size for the Buyback i.e., ₹ 21,150.00 Lakhs (Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Fifty Lakhs Only) (excluding Transaction Costs) ("**Minimum Buyback Size**"). Based on the Minimum Buyback Size and Maximum Buyback Price, the Company would purchase a minimum of 44,52,632 (Forty Four Lakhs Fifty Two Thousand Six Hundred and Thirty Two) Equity Shares ("**Minimum Buyback Shares**").

4.4 The Company shall utilize a minimum of 40% of the amount earmarked for the Buyback i.e. ₹ 11,280.00 Lakhs (Rupees Eleven Thousand Two Hundred and Eighty Lakhs Only) within the initial half from the opening of the offer.

5. BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUYBACK PRICE AND OTHER DETAILS

5.1 The Maximum Buyback Price of ₹ 475.00 per Equity Share, has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices and closing price of the Equity Shares on Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed, price earnings ratio, impact on other financial parameters and possible impact of Buyback on the earnings per share.

5.2 The Maximum Buyback Price per Equity Share represents:

i. a premium of 20.80% over the average of the daily volume weighted average market price on NSE (the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 3 (three) months preceding the date of Prior Intimation;

ii. a premium of 22.14% over the average of the daily volume weighted average market price on NSE (the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 2 (two) months preceding the date of Prior Intimation; and

iii. a premium of 28.18% over the average of the daily volume weighted average market price on NSE (the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 2 (two) weeks preceding the date of Prior Intimation;

5.3 Subject to the Maximum Buyback Price of ₹ 475.00 (Rupees Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share and achievement of the Minimum Buyback Size, the price for the Buyback will be determined by the Board of Directors or the Buyback Committee or their duly authorized representatives, in accordance with the Buyback Regulations.

5.4 In accordance with Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) of the Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company to the paid-up equity share capital and free reserves after the Buyback shall be (i) less than or equal to 2:1, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever is lower or (ii) be less than or equal to 2:1, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever is lower, after excluding financial statements of all subsidiaries that are non-banking financial companies and housing finance companies regulated by Reserve Bank of India or National Housing Bank, as the case may be as on March 31, 2026;

5.5 The quantum of daily purchases by the Company, during the Buyback Period, may vary from day to day. The actual number of Equity Shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buyback, subject to the Maximum Buyback Size. The actual reduction in existing number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buyback period.

5.6 Shareholders are advised that the Buyback of the Equity Shares will be carried out through the Stock Exchanges by the Company, in its sole discretion, based on, amongst other things, the prevailing market prices of the Equity Shares, which may be below the Maximum Buyback Price of ₹ 475.00 (Rupees Four Hundred and Seventy Five only) per Equity Share.

6. COMPLIANCE WITH REGULATION 4 OF THE BUYBACK REGULATIONS

In terms of the provisions of Regulation 4(iv) and Regulation 5(i) (b) of the Buyback Regulations, the aggregate amount proposed under Buyback shall be not more than 10% of the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the company, which is based on the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2026, whichever sets out a lower amount

As per the latest audited balance sheet of the Company as at March 31, 2026 , the total paid-up equity capital and free reserves are as follows:

(₹ In Lakhs)

Particulars	Standalone	Consolidated
Total paid-up equity capital **(A)**	4,365.00	4,365.00
Total Free Reserves **(B)**	2,99,608.93	2,78,240.83
Total paid up Equity capital and free reserves (C=A+B)	**3,03,973.93**	**2,82,605.83**
Maximum amount permissible for Buyback with the approval of Board of Directors of the Company under the section 68(2)(b) of the Companies Act and proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buy-back Regulations, (which is not more than 10% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company, which is based on the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2026, whichever sets out a lower amount	28,260.58	

Based on the above, the Maximum Buyback Size i.e. ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only), which is not more than 10% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company, which is based on the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2026, whichever sets out a lower amount.

7. METHOD TO BE ADOPTED FOR BUYBACK AS REFERRED TO IN SUB-REGULATION (IV) OF REGULATION 4 OF THE BUYBACK REGULATIONS

7.1 In terms of Regulation 40(1) Listing Regulations, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Accordingly, the Buyback is open to beneficial owners holding Equity Shares in dematerialized form ("**Demat Shares**"). The promoters, promoter group, and the persons in control of the Company and their associates, shall not participate in the Buyback. Further, as required under the Buyback Regulations, the Company will not Buyback Equity Shares which are locked-in or non-transferable, until the pendency of such lock-in or until the time such Equity Shares become transferable, as applicable.

7.2 Shareholders holding Equity Shares in physical form can participate in the Buyback, only after such Equity Shares are dematerialized.

7.3 The Company shall not, directly and indirectly purchase its own Equity Shares through any subsidiary company, including its own subsidiary company, investment company or group of investment companies or through spot transactions, or through any private arrangement, in the implementation of Buyback.

7.4 The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Indian Stock Exchanges, by the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

7.5 The Company shall not, directly or indirectly, purchase its own Equity Shares through any subsidiary company, including its own subsidiary companies, or through any investment company or group of investment companies.

7.6 The Company shall not buy back its Equity Shares from any person through negotiated deals, whether on or off the Stock Exchanges, through spot transactions, or through any private arrangement, in the implementation of the Buyback.

7.7 The Company shall not allow the Buyback of its Equity Shares unless the consequent reduction of its share capital is effected in accordance with the Companies Act

7.8 The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buyback Regulations, BSE circular bearing notice. no. 20260731-9 dated July 31, 2026 read along with BSE Circular bearing reference number 20230328-24 dated March 28, 2023 and NSE Circular bearing ref no. 112/2026 with download ref. no. NSE/CMTR/75734 read along with NSE circular bearing ref. no. 36/2023 with download ref no. NSE/CMTR/56034 dated March 17, 2023 ("**Stock Exchange Circulars**"), to the extent applicable and in accordance with the SEBI circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, Operational Guidance - Amendment to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018.

7.9 In relation to the Buyback of Demat Shares, the execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the broker, appointed by the Company, in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI.

8. THE AGGREGATE SHAREHOLDING OF THE PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP, DIRECTORS OF THE PROMOTER (WHERE PROMOTER IS A COMPANY), DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY

Details of the aggregate shareholding of the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter is a company), directors and key managerial personnel of the Company as on the date of the Board Meeting (i.e., September 17, 2026) is as below.

8.1 The aggregate shareholding of the promoters and promoter group as on the date of the Board Meeting:

Sr. No	Name of the Shareholders	No of Equity shares held	% of the paid up equity share capital	Category
1.	Priti A Sureka	1,65,04,702	3.78	Promoter
2.	Radhe Shyam Goenka	4,03,876	0.09	Promoter
3.	Prashant Goenka	3,53,017	0.08	Promoter
4.	Mohan Goenka	6,70,373	0.15	Promoter
5.	Sushil Kumar Goenka	5,19,270	0.12	Promoter
6.	Harsha Vardhan Agarwal	2,29,074	0.05	Promoter
7.	Aditya Vardhan Agarwal	1,96,795	0.05	Promoter
8.	Radhe Shyam Agarwal	1,95,000	0.04	Promoter
9.	Rajkumar Goenka	11,95,247	0.27	Promoter Group
10.	Usha Agarwal	8,74,929	0.20	Promoter Group
11.	Sachin Goenka	7,17,750	0.16	Promoter Group
12.	Shobhana Agarwal	6,30,000	0.14	Promoter Group
13.	Darsh Goenka	5,65,000	0.13	Promoter Group
14.	Advay Goenka	5,54,000	0.13	Promoter Group
15.	Reyansh Goenka	4,07,750	0.09	Promoter Group
16.	Devarsh Goenka	4,07,750	0.09	Promoter Group
17.	Santosh Goenka	3,07,426	0.07	Promoter Group
18.	Saroj Goenka	2,97,452	0.07	Promoter Group
19.	Ashish Goenka	2,87,025	0.07	Promoter Group
20.	Rashmi Goenka	2,80,957	0.06	Promoter Group
21.	Rachna Bagaria	2,70,000	0.06	Promoter Group
22.	Indu Goenka	2,69,700	0.06	Promoter Group
23.	Manish Goenka	2,54,947	0.06	Promoter Group
24.	Reha Goenka	2,40,000	0.05	Promoter Group
25.	Aditya Vardhan Agarwal HUF	2,04,278	0.05	Promoter Group
26.	Sushil Kumar Goenka HUF	1,74,000	0.04	Promoter Group
27.	Manish Goenka HUF	1,74,000	0.04	Promoter Group
28.	Mohan Goenka HUF	1,74,000	0.04	Promoter Group
29.	Smriti Agarwal	1,74,000	0.04	Promoter Group
30.	Harsha Vardhan Agarwal HUF	1,72,000	0.04	Promoter Group
31.	Puja Goenka	1,69,398	0.04	Promoter Group
32.	Jayant Goenka	1,57,004	0.04	Promoter Group
33.	Chikky Goenka	1,48,942	0.03	Promoter Group
34.	Jyoti Goenka	1,42,483	0.03	Promoter Group
35.	Rachana Goenka	1,36,988	0.03	Promoter Group
36.	Mansi Agarwal	1,33,691	0.03	Promoter Group
37.	Richa Agarwal	1,33,691	0.03	Promoter Group
38.	Laxmi Devi Bajoria	1,06,000	0.02	Promoter Group
39.	Abhishek Agarwal	84,000	0.02	Promoter Group
40.	Ashish Goenka HUF	74,000	0.02	Promoter Group
41.	Jayant Goenka HUF	74,000	0.02	Promoter Group
42.	Prashant Goenka HUF	74,000	0.02	Promoter Group
43.	Kusum Agarwal	34,450	0.01	Promoter Group
44.	Divya Agarwal	24,975	0.01	Promoter Group
45.	Pradip Kumar Agarwal	23,380	0.01	Promoter Group
46.	Sangita Agarwal	16,000	0.00	Promoter Group
47.	Shruti Goenka	14,719	0.00	Promoter Group
48.	Shubham Agarwal	14,700	0.00	Promoter Group
49.	Dhiraj Agarwal	8,375	0.00	Promoter Group
50.	Vishal Agarwal	8,200	0.00	Promoter Group
51.	Sumangal Agarwal	8,200	0.00	Promoter Group
52.	Rohin Raj Sureka	5,000	0.00	Promoter Group
53.	Nimisha Goenka	100	0.00	Promoter Group
54.	Vidhishree Agarwal	100	0.00	Promoter Group
55.	Vidula Agarwal	100	0.00	Promoter Group
56.	Sashwat Goenka	100	0.00	Promoter Group
57.	Shreya Goenka	100	0.00	Promoter Group
58.	Vibhash Vardhan Agarwal	100	0.00	Promoter Group
59.	Vihan Vardhan Agarwal	100	0.00	Promoter Group
60.	Manan Goenka	100	0.00	Promoter Group
61.	Jyoti Agarwal	NIL	0.00	Promoter Group
62.	Avishi Sureka	NIL	0.00	Promoter Group
63.	Suraj Finvest Private Limited	10,56,30,326	24.20	Promoter Group
64.	Diwakar Finvest Private Ltd	9,87,94,786	22.63	Promoter Group
65.	PANEmami Cosmed Limited	31,17,160	0.71	Promoter Group
66.	Emami Paper Mills Ltd	9,33,000	0.21	Promoter Group
67.	Emami Frank Ross Limited	10,000	0.00	Promoter Group
68.	Ajanta Suppliers Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
69.	Aviro Vanijya Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
70.	Aviro Vyapaar Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
71.	Aviro Writing Instruments Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
72.	Bondhampuli Crops Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
73.	CRI Limited	NIL	NIL	Promoter Group
74.	Deluxe Builders & Promoters Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
75.	Emami Education & Research Foundation	NIL	NIL	Promoter Group
76.	Emami Estates Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
77.	Emami Group Of Companies Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
78.	Nayee Deesha Communications Private Limited	NIL	NIL	Promoter Group
79.	Amitabh Goenka	5,71,496	0.13	Promoter Group

Sr. No	Name of the Shareholders	No of Equity shares held	% of the paid up equity share capital	Category
80.	Ritu Goenka	4,54,930	0.10	Promoter Group
81.	Nikunj Goenka	2,65,000	0.06	Promoter Group
82.	Yogesh Goenka	2,45,400	0.06	Promoter Group
83.	Amitabh Goenka HUF	74,000	0.02	Promoter Group
	Total	**23,93,93,412**	**54.84**	

8.2 The aggregate shareholding of the directors of the corporate promoter (other than those included above) as on the date of the Board Meeting: **Not Applicable since the Company does not have any corporate promoter.**

8.3 The aggregate shareholding of the directors and key managerial personnel of the Company as on the date of the Board Meeting:

Sr. No.	Name	Designation	No of Equity shares held	% of the paid up equity share capital
1.	Radhe Shyam Agarwal	Chairman Emeritus and Non-Executive Director	1,95,000	0.04
2.	Radhe Shyam Goenka	Chairman And Non-Executive Director	4,03,876	0.09
3.	Anand Nandkishore Rathi	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
4.	Chandra Kumar Dhanuka	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
5.	Debabrata Sarkar	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
6.	Anjani Kumar Agrawal	Non-Executive – Independent Director	1000	0.00
7.	Anjanmoy Chatterjee	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
8.	Avani V Davda	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
9.	Rajiv Khaitan	Non-Executive – Independent Director	2000	0.00
10.	Mamta Binani	Non-Executive – Independent Director	NIL	NIL
11.	Sushil Kumar Goenka	Whole Time Director	5,19,270	0.12
12.	Mohan Goenka	Vice Chairman And Whole Time Director	6,70,373	0.15
13.	Aditya Vardhan Agarwal	Non-Executive Director – Non Independent Director	1,96,795	0.05
14.	Harsha Vardhan Agarwal	Vice Chairman And Managing Director	2,29,074	0.05
15.	Priti A Sureka	Whole Time Director	1,65,04,702	3.78
16.	Prashant Goenka	Whole Time Director	3,53,017	0.08
17.	Naresh Hiralal Bhansali	CEO - Finance, Strategy & Business Development and CFO	67,476	0.02
	Total		**1,91,42,583**	**4.38**

8.4 Except as disclosed below, no Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter is a company), directors of the Company and key managerial personnel, during a period of 12 (twelve) months preceding the date of this Public Announcement (i.e., Friday, September 18, 2026):

Sr. No.	Name of the Shareholders	Aggregate number of Equity Shares purchased/ (sold)	Nature of transactions	Minimum Price (₹)	Date of Minimum price	Maximum Price (₹)	Date of Maximum price
1.	Radhe Shyam Goenka	12,000	Transferred through gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
2.	Manan Goenka	5,64,900	Transferred through gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
3.	Shruti Goenka	1,82,036	Transferred through gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
4.	Avishi Sureka	14,00,000	Transferred through gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
5.	Mohan Goenka	1,500	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
6.	Manish Goenka	1,500	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
7.	Rajkumar Goenka	5,26,883	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
8.	Prashant Goenka	41,017	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
9.	Santosh Goenka	1,84,286	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
10.	Ashish Goenka	750	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
11.	Sushil Kumar Goenka	1,500	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
12.	Jayant Goenka	750	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
13.	Sachin Goenka	750	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026
14.	Priti A Sureka	14,00,000	Received through Gift	NA	26 Feb 2026	NA	26 Feb 2026

**the above inter se transfer was made by way of gifts and hence there was no purchase consideration.*

^ Maximum & Minimum price represents net amount received on purchase or sale of equity shares by promoter or promoter group or by directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter is a company), directors and key managerial personnel. Also, the Minimum and Maximum price are calculated based on the number of transactions during the period.

8.5 Except as disclosed below, no Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters (where the promoter is a company) and directors and key managerial personnel, during a period of 6 (six) months preceding the date of the Board Meeting (i.e. Thursday, September 17, 2026): **None**

9. INTENTION OF THE PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO OFFER THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK

9.1 In accordance with Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, since the Buyback is being implemented by way of open market purchases through the Stock Exchanges, the Buyback shall not be made by the Company from the promoters, members of the promoter group, persons in control and their associates.

9.2 Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, neither the promoters and promoter group nor their associates have dealt in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the Stock Exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the promoters or promoter group) from the date of the Board Meeting till the closing of the offer.

9.3 Further, as per Regulation 24(i)(ea)(i) of the Buyback Regulations, the shares or other specified securities held by the promoter(s) and promoter group including their associates, for which buyback is undertaken, shall remain frozen at the International Securities Identification Number (ISIN) level during the period from the date of passing of the resolution by the board of directors i.e. September 17, 2026, till the closing of the offer of Buyback. The transfer of Equity Shares pursuant to invocation of encumbrances created prior to the commencement of Buyback, may be allowed subject to the freeze on such Equity Shares continuing to apply pursuant to invocation of encumbrances, and also subject to the conditions as may be specified by SEBI. The operationalisation of this ISIN-level freeze mechanism is governed by the SEBI circular dated July 21, 2026 on Operationalisation of Freezing of Holdings of Promoter and Promoter Group (including their associates) at the ISIN Level under Regulation 24(i)(ea) of the Buyback Regulations, and the operational guidelines issued by the depositories pursuant thereto.

10. SUBSISTING DEFAULTS

The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of Companies Act, 2013, interest payment thereon, redemption of debentures or interest payment thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or any bank.

11. CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OFTHE BUYBACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT

11.1 Equity Shares of the Company are fully paid-up.

11.2 The Company has not undertaken a Buyback of any of its securities during the period of 1 (one) year immediately preceding the date of Board Meeting.

11.3 The public announcement of the offer or any other advertisement, circular, brochure, publicity material contains true, tactual and material information and shall not contain any misleading information and the directors of the Company accept the responsibility for the information contained in such documents.

11.4 The Company shall not issue any shares or other specified securities including by way of bonus till the date of expiry of Buyback period for the offer made under these regulations, except in discharge of subsisting obligations through conversion of warrants, slock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.

11.5 The Company shall pay the consideration only by way of cash.

11.6 The Company shall not buy back its shares or other specified securities from any person through negotiated deal whether on or off the Stock Exchanges or through spot transaction or through private arrangement.

11.7 The total number of Equity Shares to be bought back shall not exceed ten percent of the total paid up equity share capital of the Company in the financial year.

11.8 The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company to the paid-up capital after the Buyback shall not be more than twice the post Buyback paid-up share capital and free reserves, based on both standalone and consolidated financial statements of the Company, whichever is lower, as prescribed under the Buyback Regulations

11.9 The Company shall not make any offer of Buyback within a period of 1 (one) year reckoned from the expiry of the Buyback period, i.e. the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback.

11.10 There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act.

11.11 The Company shall not withdraw the Buyback after the public announcement in relation to the Buyback is made.

11.12 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buyback Regulations and in such form as may be prescribed by SEBI and the Company shall also upload the information regarding Equity Shares bought back on its website on a daily basis.

11.13 The Equity Shares of the Company are frequently traded shares.

12. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

(i) The Board has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that:

a) that immediately from the date of board meeting held on September 17, 2026, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;

b) as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board meeting held on September 17, 2026 approving the Buyback, and having regard to the Board's intention with respect to the management of Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in the Board's view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that date of the Board Meeting held on September 17, 2026; and

c) in forming an opinion as aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 1956 (to the extent not repealed), or Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code 2026 (including prospective and contingent liabilities).

13. REPORT BY THE COMPANY'S STATUTORY AUDITOR

The text of the Report dated September 17, 2026 received from S.R. Batliboi & Co. LLP, Chartered Accountants (Firm's Registration No. 301003E/E300005), the Statutory Auditors of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

"***Quote***

Independent Auditor's Report on the proposed buy back of equity shares pursuant to the requirements of Section 68 and Section 70 of the Companies Act, 2013, as amended and Clause (xi) of Schedule I of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended

The Board of Directors
Emami Limited
Emami Tower
687 Anandpur, EM Bypass
Kolkata 700107

1. This Report is issued in accordance with the terms of our service scope letter dated September 12, 2026 and master engagement agreement September 12, 2022 with Emami Limited (hereinafter the "Company").

2. The proposal of the Company to buy back its equity shares in pursuance of the provisions of Section 68 and 70 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Clause (xi) of Schedule I of Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the SEBI Buyback Regulations") has been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on September 17, 2026. The Company has prepared the attached "Statement of determination of the amount permissible capital payment for proposed buyback of equity shares" (the "Statement" or "Annexure"), which we have initialed for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility

3. The preparation of the Statement is the responsibility of the Board of Directors of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the date of the board meeting dated September 17, 2026. The Board of Directors are also responsible for ensuring that the Company complies with the requirements Act and SEBI Buyback Regulations.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the Act and SEBI Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance:

(i) Whether we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements for year ended March 31, 2026.

(ii) Whether the amount of permissible capital payment for the proposed buyback of the equity shares as included in the Statement has been properly determined in accordance with the provisions of Section 68(2)(b) and 68(2)(c) of the Act and Regulation 4(i), 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulations;

(iii) Whether the Board of Directors have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the Board Meeting dated September 17, 2026.

6. The audited standalone and consolidated financial statements, referred to in paragraph 5(i) above, have been audited by us on which we issued an unmodified audit opinion vide our reports dated May 21, 2026. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

9. Our scope of work did not involve us performing audit tests for the purposes of expressing an opinion on the fairness or accuracy of any of the financial information or the financial results of the Company taken as a whole. We have not performed an audit, the objective of which would be the expression of an opinion on the financial results, specified elements, accounts or items thereof, for the purpose of this report. Accordingly, we do not express such opinion.

10. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the applicable criteria mentioned in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated with the applicable criteria. Our procedures included the following in relation to the Statement:

i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2026. We have obtained and read the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2026;

ii) Read the Articles of Association of the Company and noted the permissibility of buy back;

iii) Traced the amounts of paid up Equity share capital and free reserves as mentioned in Statement from the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2026.

iv) Obtained the minutes of the meeting of the Board of Directors in which the proposed buy-back was approved and compared the buy-back amount with the permissible limit computed in accordance with Section 68(2)(b) and 68(2)(c) of the Act and Regulation 4(i), 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulations detailed in the Statement;

v) Obtained the minutes of the meeting of the Board of Directors in which the proposed buy back was approved and read the Board had formed the opinion as specified in SEBI Buyback Regulations on reasonable grounds that the Company will not, having regard to the state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the Board meeting dated September 17, 2026.

vi) Read the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2026 in order to assess whether all shares for buy-back are fully paid-up;

vii) Verified the arithmetical accuracy of the amounts mentioned in the Statement.

viii) Obtained necessary representations from the management of the Company.

Opinion

11. Based on our examination as above, and the information and explanations given to us, we report that:

(i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements for year ended March 31, 2026.

(ii) The amount of permissible capital payment for proposed buyback of the equity shares as included in the Statement has been properly determined in accordance with the provisions of Section 68(2)(b) and 68(2)(c) of the Act and Regulation 4(i), 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulations;

(iii) the Board of Directors have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I of the SEBI Buyback Regulations on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the Board Meeting dated September 17, 2026.

Restriction on Use

12. The Report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of Section 68 and Section 70 of the Act read with Clause (xi) of Schedule I of SEBI Buyback Regulations solely to enable them to include it in the public announcement to be made to the Shareholders of the Company, and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For **S.R. Batliboi & Co. LLP**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 301003E/E300005
Shivam Chowdhary
Partner
Membership Number: 067077
UDIN: 26067077GJDTZD4487

Place of Signature: Kolkata
Date: September 17, 2026

Annexure- Statement of determination of the amount permissible capital payment for proposed buyback of equity shares

(₹ in lakhs)

Particulars	Standalone	Consolidated
Paid up equity share capital as on March 31, 2026# (43,65,00,000 equity shares of face value Re. 1 each) **(A)**	4,365.00	4,365.00
Free reserves as on March 31, 2026#		
- General reserve	51,616.52	51,616.52
- Retained earnings*	2,47,992.41	2,26,624.31
Total Free Reserves (B)	**2,99,608.93**	**2,78,240.83**
Total paid up Equity capital and free reserves (C=A+B)	**3,03,973.93**	**2,82,605.83**
Maximum amount permissible for buyback with the approval of Board of Directors of the Company under Section 68(2)(b) of the Companies Act and proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-back Regulations (10% of the aggregate of paid-up capital and free reserves of the company, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever sets out a lower amount (C*10%)	28,260.58	
Amount proposed by Board Resolution dated September 17, 2026 approving the Buyback based on the audited accounts for the year ended March 31, 2026	28,200.00	

The above calculation of the paid-up Equity Capital and Free Reserves as at March 31, 2026 for Buyback of equity shares is based on the amounts appearing in the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the year ended March 31, 2026. These financial statements of the Company are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Act. Free reserves as defined in Section 2(43) of the Companies Act, 2013 as amended.

* Retained earnings have been computed after elimination of following unrealized gains:-

a) Unrealized gain on Mutual Funds / AIF / Foreign Exchange

b) Unrealized gain on fair valuation of option available in Investment

For and on behalf of the Board of Directors of Emami Limited
Harsha Vardhan Agarwal
Vice-chairman and Managing Director
DIN:00150089

Place: Kolkata
Date: September 17, 2026

Unquote"

14. Prior approval obtained from the lenders of the Company in case of a breach of any covenant with such lender(s). The Company has obtained consent from its lenders and it is confirmed that there is no breach of any covenant with such lenders.

PART B - Disclosures in accordance with Schedule IV of the Buyback Regulations

1. DETAILS OF BOARD APPROVAL DATED SEPTEMBER 17, 2026 FOR THE BUYBACK, IF APPLICABLE

The Maximum Buyback Size represents 9.28% and 9.98% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2026, respectively whichever is lower (being the latest available audited standalone and consolidated financial statements of the Company) which is not more than 10% of the total paid-up capital and free reserves of the Company in accordance with the proviso to the Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and Section 68(2)(b) of the Companies Act.

2. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUYBACK.

2.1 Maximum Buyback Size and the Maximum Buyback Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 59,36,842 (Fifty Nine Lakhs Thirty Six Thousand Eight Hundred and Forty Two Only) Equity Shares ("Maximum Buyback Shares"), which will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming full deployment of the Maximum Buyback Size) but will always be subject to the Maximum Buyback Size.

2.2 The actual number of Equity Shares bought back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back, and the aggregate consideration paid in the Buyback, subject to the Maximum Buyback Size. The actual reduction in existing number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buyback period.

2.3 The Company shall utilise at least 75% of the amount earmarked as the Maximum Buy Back Size for the Buy Back i.e. ₹ 21,150.00 Lakhs (Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Fifty Lakhs Only) **("Minimum Buy Back Size")**. Based on the Minimum Buy Back Size and Maximum Buy Back Price, the Company would purchase indicative minimum of 44,52,632 (Forty Four Lakhs Fifty Two Thousand Six Hundred and Thirty Two) Equity Shares **("Minimum Buyback Shares")**. Further the Company shall utilize a minimum of 40% of the amount earmarked for the Buy Back i.e. ₹ 11,280.00 Lakhs (Rupees Eleven Thousand Two Hundred and Eighty Lakhs Only) within the initial half from the opening of the offer.

2.4 Based on the Minimum Buyback Size and Maximum Buyback Price, the Company would purchase a minimum of 44,52,632 (Forty Four Lakhs Fifty Two Thousand Six Hundred and Thirty Two) Equity Shares. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming full deployment of the Maximum Buyback Size) but will always be subject to the Maximum Buyback Size. However, the Maximum Buyback Shares will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company.

2.5 The amount required by the Company for the Buyback (including the Transaction Costs) will be funded out of the internal accruals of the Company including free reserves, in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 16(iv) of the Buyback Regulations.

3. PROPOSED TIMETABLE FOR BUYBACK

Activity	Date
Date of Board resolution approving Buyback	September 17, 2026
Date of publication of the Public Announcement	September 19, 2026
Date of opening of the Buyback	September 22, 2026
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialised mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges
Extinguishment of Equity Shares	The Equity Shares (in dematerialised form) will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, as amended, and the bye-laws, the circulars and guidelines framed thereunder. The Company shall ensure that all Equity Shares bought back are extinguished within 7 (seven) Working Days of the expiry of the Buyback period.

Activity	Date
Last date for the completion of the Buyback	Earlier of: (a) sixty-six Working Days i.e. Tuesday December 29, 2026 from the date of the opening of the Buyback; or (b) when the Company completes the Buyback by deploying the amount equivalent to the Maximum Buyback Size; or (c) at such earlier date as may be determined by the Board (including a committee thereof, constituted by the Board or persons nominated by the Board / committee to exercise its powers, and / or the powers conferred by the Board resolution in relation to the Buyback), after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buyback Size (even if the maximum Buyback Size has not been reached or the Maximum Buyback Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the Buyback shall be completed before the last date for the Buyback.

4. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUYBACK

4.1 The Buyback is open to all shareholders of the Company holding Equity Shares in dematerialised form (“**Demat Shares**”). Shareholders holding Equity Shares in physical form can participate in the Buyback, only after such Equity Shares are dematerialized.

4.2 Further, as required under the Companies Act and Buyback Regulations, the Company will not Buyback Equity Shares which are partly paid-up, the Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, until they become fully paid-up, or until the pendency of such lock-in, or until the time such Equity Shares become freely transferable, as applicable.

4.3 The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except “all or none” order matching system, as provided under the Buyback Regulations and price-time priority-based order matching principle, as provided under the Stock Exchange Circulars, to the extent applicable and in accordance with the SEBI circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, Operational Guidance - Amendment to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018

4.4 For the implementation of the Buyback, the Company has appointed IIFL Capital Services Limited *(formerly known as IIFL Securities Limited)* as the registered broker (“**Company’s Broker**”) through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company.

The contact details of the Company’s Broker are as follows:

IIFL CAPITAL

IIFL Capital Services Limited
(formerly known as IIFL Securities Limited)
24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg
Lower Parel (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India
Email: emamibuyback.2026@iiflcap.com
Tel. No.: +91 22 4646 4600
Fax No.: +91 22 2493 1073
Contact Person: Kunal Thakkar/Vishal Hase
Website: www.iiflcapital.com
SEBI Registration No.: INZ000164132
CIN: L99999MH1996PLC132983

4.5 The Equity Shares are traded in dematerialised mode under the trading codes EMAMILTD at NSE and EMAMILTD / 531162 at BSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE548C01032.

4.6 The Company shall, commencing from September 22, 2026 (i.e., the date of opening of the Buyback), place “buy” orders on the Stock Exchanges on the normal trading segment under BO series to Buyback the Equity Shares through the Company’s Broker, in such quantity and at such price which will be in accordance with SEBI circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, Operational Guidance - Amendment to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 and Stock Exchange Circulars, not exceeding the Maximum Buyback Price of ₹ 475.00/- (Rupees Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share, as it may deem fit.

4.7 **Procedure for Buyback of Demat Shares:** Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buyback, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a “buy” order for Buyback of the Equity Shares. The Company shall place a “buy” order for Buyback of Demat Shares, by indicating to the Company’s Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price offered by the beneficial owners and that price would be the Buyback price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company’s Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI. Orders for Equity Shares can be placed on the trading days of the Stock Exchanges. The Company is under no obligation to place “buy” order on a daily basis. The orders for buying back the Equity Shares will be placed on normal trading segment of Stock Exchanges atleast once a week.

4.8 It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders / beneficial owners pursuant to the Buyback and that the same would depend on the price at which the trade with that particular shareholder / beneficial owner was executed on the Stock Exchanges.

4.9 **Procedure for Buyback of Physical Shares:** As per the proviso to regulation 40(1) of Listing Regulations read with SEBI’s press releases dated March 27, 2019, effective from April 1, 2019, transfers of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository (“**LODR Amendment**”). In light of the LODR Amendment, the Company shall not accept the Equity Shares offered under the Buyback unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF OFFERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUYBACK BEFORE BUYBACK CLOSING DATE AS PER APPLICABLE BUYBACK REGULATIONS.

4.10 Shareholders are requested to get in touch with the Manager to the Buyback or the Company’s Broker or the Registrar and Share Transfer Agent of the Company to clarify any doubts in the process.

4.11 Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buyback Size i.e. ₹ 21,150.00 Lakhs (Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Fifty Lakhs Only), nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buyback any additional Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buyback Size has not been reached, and / or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buyback, to the extent permissible by law. The Company is under no obligation to utilize the entire amount of Maximum Buyback Size or buy all the Maximum Buyback Shares. However, if the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size or is not able to utilize a minimum of 40% of the amount earmarked for the Buyback i.e. ₹ 11,280.00 Lakhs (Rupees Eleven Thousand Two Hundred and Eighty Lakhs Only) within the initial half from the date of the opening of the Buyback, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the escrow account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

4.12 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buyback Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www.emamiltd.in) on a daily basis.

4.13 Eligible shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

5. METHOD OF SETTLEMENT

5.1 Settlement of Demat Shares: The Company will pay consideration for the Buyback to the Company’s Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account (“**EMAMI LIMITED BUYBACK DEMAT ACCOUNT 2026**”) with IIFL Capital Services Limited *(formerly known as IIFL Securities Limited)* for the purpose of Buyback. The Equity Shares bought back in the demat form would be transferred directly to the escrow account of the Company i.e. EMAMI LIMITED BUYBACK DEMAT ACCOUNT 2026. After completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to follow procedure applicable to normal secondary market transactions.

5.2 Extinguishment of Demat Shares: The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018 and the bye-laws, the circulars, and guidelines framed thereunder, each as amended from time to time, in the manner specified in the Buyback Regulations and the Companies Act. The Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within 7 (seven) Working Days from the expiry of the Buyback period.

5.3 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

6. BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

6.1 Emami Ltd was incorporated on March 11, 1983 as A.M.P Udyog Viniyog Limited under the Companies Act, 1956. In 1994, Himani Ltd was merged with AMP Udyog Viniyog Ltd., vide Hon’ble Calcutta High Court order dated February 8, 1994 and its name was changed as per fresh certificate of incorporation dated May 5, 1994. In 1998, Emami Ltd was then merged with Himani Ltd. vide Hon’ble Calcutta High Court order dated July 21, 1998 and its name was changed as Emami Ltd. as per fresh certificate of incorporation dated September 1, 1998. The Equity Shares of the Company are listed since, 1995 on BSE and 2006 on NSE.

6.2 Emami Limited is the flagship company of the Emami Group and one of India’s leading FMCG companies in the personal care and healthcare space. With a portfolio of over 1000 products, Emami’s iconic brands include Navratna, BoroPlus, Zandu, Kesh King, Dermicool, Smart & Handsome, Mentho Plus, 7 Oils in One, Creme 21 among others. Emami’s products reach over 5.4 million retail outlets in India through a network of 4000+ distributors, while its international presence spans 70+ countries. Known for its strong consumer connect, innovative marketing and distinctive brand-building capabilities, Emami continues to leverage its deep consumer insights, brand-building expertise and strategic investment approach to create enduring brands and new avenues for growth in India and international markets. The Company has consistently strengthened and diversified its portfolio through strategic acquisitions and investments across high-growth consumer segments. In addition to acquisitions such as Zandu, Kesh King, Creme 21 and Dermicool, Emami has strategically invested in a new generation of consumer brands, including The Man Company, Brillare Science, Axiom Ayurveda, and IncNut Digital which have since become subsidiaries of the Company. Other strategic investments include The Furball Story and TruNative, reflecting Emami’s focus on identifying and nurturing emerging consumer businesses.

7. BRIEF FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

7.1 The selected financial information of the Company on standalone basis, as extracted from the un-audited limited review standalone financial statements for the period of three months ended June 30, 2026, and audited standalone financial statements for the last 3 (three) financial year ended March 31, 2026, 2025 and 2024 is given below:

(₹ In Lakhs)

Particulars	For three months period ended on June 30, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2025 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2024 (IND-AS)
	Un-audited limited reviewed	Audited	Audited	Audited
Months	**3**	**12**	**12**	**12**
Revenue from Operations	77,991.80	3,04,826.05	3,12,354.62	2,92,157.05
Other Income	5,318.40	11,853.71	15,743.51	6,924.44
Total Income	**83,310.20**	**3,16,679.76**	**3,28,098.13**	**2,99,081.49**
Total Expenses (excluding finance cost and depreciation, amortization, Tax and Exceptional Items)	56,447.27	2,09,827.03	2,18,627.12	2,06,958.24
Finance Cost	88.73	196.44	211.42	212.39
Depreciation and amortization expense	3,414.11	15,562.65	15,837.88	16,656.92
Exceptional items	-	(1,014.84)	-	(589.54)
Profit/(Loss) before Tax (after exceptional items)	23,360.09	90,078.80	93,421.71	74,664.40
Provision for Tax (including Deferred Tax and MAT Credit)	5,137.97	5,916.61	7,502.21	5,325.77
Profit/(Loss) after Tax	18,222.12	84,162.19	85,919.50	69,338.63
Other Comprehensive Income/(Loss) for the year net of tax	2,147.27	(2,936.30)	(2,581.10)	418.46
Total Comprehensive income for the period	20,369.39	81,225.89	83,338.40	69,757.09
Equity Share capital	**NA**	**4,365.00**	**4,365.00**	**4,365.00**
Other Equity	NA	3,11,196.63	2,82,350.73	2,33,932.33
Net worth/Shareholders Fund	NA	3,15,561.63	2,86,715.73	2,38,297.33
Total Debt	NA	7,500.00	29.22	738.85

***Note:** The above information has been furnished based on the standalone audited financial statements prepared under Indian Accounting Standards (‘Ind AS’) for FY2026, FY2025, FY2024 and three months period ended June 30, 2026. The financial information for three months period ended June 30, 2026 is unaudited but was subjected to a limited review by Statutory Auditors of the Company under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended.*

Key Ratios	For three months period ended on June 30, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2025 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2024 (IND-AS)
Earnings Per Share (₹) (Basic)	4.17*	19.28	19.68	15.86
Earnings Per Share (₹) (Diluted)	4.17*	19.28	19.68	15.86
Return on Net Worth (%)	NA	27.95%	32.73%	29.85%
Book Value Per Share (₹)	NA	72.29	65.68	54.59
Debt-Equity Ratio	NA	0.0237	0.0001	0.0031

*not annualized

The key financial ratios, mentioned herein above, have been computed as under:

Net worth	Equity Share Capital + Other Equity (excluding revaluation reserves and miscellaneous expenditure to the extent not written off)
Earning Per Share (Basic)	Profit / (Loss) for the period Attributable to Equity Shareholders / Weighted Number of Equity Shares outstanding
Earning Per Share (Diluted)	Profit / (Loss) for the period Attributable to Equity Shareholders / Weighted Number of Equity Shares outstanding
Book Value per share	Net worth / Number of Equity Shares outstanding at year-end
Debt-Equity Ratio	Total Debt/ Net Worth
Return on Net Worth (%)	Profit / (Loss) for the period / Net worth

7.2 The selected financial information of the Company on consolidated basis, as extracted from the unaudited limited review consolidated financial statements for the period of three months ended December 31, 2026, and audited consolidated financial statements for the last 3 (three) financial year ended March 31, 2026, 2025 and 2024 is given below:

(₹ In Lakhs)

Particulars	For three months period ended on June 30, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2025 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2024 (IND-AS)
	Un-audited limited reviewed	Audited	Audited	Audited
Months	**3**	**12**	**12**	**12**
Revenue from Operations	1,03,920.63	3,77,951.30	3,80,918.86	3,57,809.46
Other Income	1,849.71	8,511.36	6,811.39	4,679.78
Total Income	**1,05,770.35**	**3,86,462.69**	**3,87,730.25**	**3,62,489.24**
Total Expenses (excluding finance cost and depreciation, amortization, Tax and Exceptional Items)	81,303.46	2,81,587.59	2,78,407.86	2,62,855.75
Finance Cost	560.61	1,113.00	933.69	997.72
Depreciation and amortization expense	4,275.40	17,734.22	17,821.40	18,590.59
Exceptional items	-	(1,014.84)	-	(589.54)
Share of (Loss) associate	(160.49)	(406.68)	(1,181.02)	(372.36)
Profit/(Loss) before Tax (after exceptional items)	19,470.88	85,621.20	89,386.28	79,083.28
Provision for Tax (including Deferred Tax and MAT Credit)	5,576.76	7,080.86	9,111.82	6,669.68
Profit/(Loss) after Tax	13,894.12	77,526.49	80,274.46	72,413.60
Profit attributable to:				
Owner of the Company	13,735.36	77,527.15	80,646.81	72,353.97
Non-controlling Interest	158.75	(0.66)	(372.35)	60.63
Other Comprehensive Income/(Loss) for the year net of tax	2,270.30	(2,238.01)	(3,010.44)	(153.09)
Total Comprehensive income for the period	16,163.04	75,288.14	77,264.02	72,260.51
Equity Share capital	**NA**	**4,365.00**	**4,365.00**	**4,365.00**
Other Equity	NA	2,88,032.55	2,65,114.29	2,40,293.79
Net worth	NA	2,92,397.55	2,69,479.29	2,44,658.79
Total Debt	NA	12,238.46	6,208.47	6,568.92

***Note:** The above information has been furnished based on the consolidated audited financial statements prepared under Indian Accounting Standards (‘Ind AS’) for FY2026, FY2025, FY2024 and three month period ended June 30, 2026. The financial information for three months period ended June 30, 2026 is unaudited but was subjected to a limited review by Statutory Auditors of the Company under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended.*

Key Ratios	For three months period ended on June 30, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2026 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2025 (IND-AS)	For the year ended March 31, 2024 (IND-AS)
Earnings Per Share (₹) (Basic)	3.15*	17.76	18.48	16.55
Earnings Per Share (₹) (Diluted)	3.15*	17.76	18.48	16.55
Return on Net Worth (%)	NA	27.6%	31.4%	30.5%
Book Value Per Share (₹)	NA	66.99	61.74	56.05
Debt-Equity Ratio	NA	0.04	0.02	0.03

*not annualized

The key financial ratios, mentioned herein above, have been computed as under

Net worth	Equity Share Capital + Other Equity (excluding revaluation reserves and miscellaneous expenditure to the extent not written off)
Earning Per Share (Basic)	Profit / (Loss) for the period Attributable to Equity Shareholders / Weighted Number of Equity Shares outstanding
Earning Per Share (Diluted)	Profit / (Loss) for the period Attributable to Equity Shareholders / Weighted Number of Equity Shares outstanding
Book Value per share	Net worth / Number of Equity Shares outstanding at year end
Debt-Equity Ratio	Total Debt/ Net Worth
Return on Net Worth (%)	Profit / (Loss) for the period / Net worth

8. DETAILS OF ESCROW ACCOUNT OPENED AND THE AMOUNT DEPOSITED THEREIN

8.1 In accordance with Regulation 20 of the Buyback Regulations and towards security for performance of its obligations under the Buyback Regulations, the Company has entered into an escrow agreement (**“Escrow Agreement”**) with the Manager to the Buyback and HDFC Bank Ltd. who has been appointed as escrow banker (**“Escrow Bank”**) pursuant to which the Company has opened an escrow account (**“Emami Ltd Escrow Buyback 2026”**) (“**Escrow Account**”) and a special account **“Emami Ltd Special Escrow Buyback 2026”**. The Company has authorized the Manager to the Buyback to operate the Escrow Account in compliance with the Buyback Regulations and the Escrow Agreement. The Company will deposit requisite cash, being 25% of the Maximum Buyback Size in the Escrow Account (**“Escrow Amount”**) aggregating to ₹ 7,050.00 lakhs (Rupees Seventy Thousand Fifty Lakhs Only) in accordance with the Buyback Regulations.

8.2 The funds in the Escrow Account may be released for making payment to the shareholders subject to at least 2.5% of the Maximum Buyback Size remaining in the Escrow Account at all points in time.

8.3 The balance lying to the credit of the Escrow Account will be released to the Company on completion of all obligations in accordance with the Buyback Regulations.

8.4 If the Company is not able to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size i.e. ₹ 21,150.00 Lakhs (Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Fifty Lakhs Only) or is not able to utilize a minimum of 40% of the amount earmarked for the Buyback i.e. ₹ 11,280.00 Lakhs (Rupees Eleven Thousand Two Hundred and Eighty Lakhs Only) within the initial half of the sixty six working days from the date of the opening of the Buyback, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

9. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

9.1 The Company’s Equity Shares are listed on the BSE and NSE.

9.2 The high, low and weighted average prices for the last three years and the monthly high, low and weighted average prices for the six months preceding this PA and the corresponding volumes on BSE and NSE where equity shares of the Company are listed and traded are as follows:

BSE

Period	High (₹)*	Date of High	No. of equity shares traded on that day	Low (₹)*	Date of Low	No. of equity shares traded on that day	Weighted Average Price (₹)**	Total volume traded in that period (No of Equity Shares)	Total turnover transacted in the period (in ₹)
Last three Financial years (F.Y.)									
F.Y. 2026	655.40	19-May-25	10,108	385.35	30-Mar-26	39,981	535.83	1,33,62,384	7,16,00,05,970.00
F.Y. 2025	859.20	06-Sep-24	19,210	429.05	19-Apr-24	12,750	638.45	92,78,046	5,92,35,39,170.00
F.Y. 2024	588.65	01-Jan-24	1,02,647	353.50	06-Apr-23	15,377	476.85	67,93,020	3,23,92,72,759.00
Preceding six months									
Period	**High (₹)***	**Date of High**	**No. of equity shares traded on that day**	**Low (₹)***	**Date of Low**	**No. of equity shares traded on that day**	**Weighted Average Price (Rs₹.)****	**Total volume traded in that period (No of Equity Shares)**	**Total turnover transacted in the period (in ₹)**
Aug-2026	416.00	07-Aug-26	49,581	362.50	31-Aug-26	11,15,896	390.84	38,01,887	1,48,59,25,357.00
Jul-2026	434.85	03-Jul-26	74,081	394.75	22-Jul-26	40,244	414.99	18,51,285	76,82,72,500.00
June-2026	418.65	22-Jun-26	3,12,983	376.05	08-Jun-26	17,376	404.40	15,63,038	63,20,86,130.00
May-2026	463.95	04-May-26	50,414	393.50	29-May-26	41,474	417.72	11,43,489	47,76,55,270.00
April-2026	477.25	23-Apr-26	13,354	385.75	02-Apr-26	19,895	440.41	5,14,376	22,65,38,127.00
Mar-2026	474.45	05-Mar-26	23,728	385.35	30-Mar-26	39,981	429.57	8,52,517	36,62,12,797.00

Source: www.bseindia.com

**High and low prices are based on the high and low of the daily prices.*

*** Weighted Average Price (Total Turnover / Total Traded Quantity) for all trading days during the period*

Note 1: In case where the same price is reflected for more than one date during the relevant periods mentioned above, the latest date is being considered for the purposes of disclosure in the above table.

NSE

Period	High (₹)*	Date of High	No. of equity shares traded on that day	Low (₹)*	Date of Low	No. of equity shares traded on that day	Weighted Average Price (₹)**	Total volume traded in that period (No of Equity Shares)	Total turnover transacted in the period (in ₹)
Last three Financial years (F.Y.)									
F.Y. 2026	653.35	06-May-25	7,14,307	385.95	30-Mar-26	12,433	548.71	14,92,14,018	81,87,55,91,552.00
F.Y. 2025	860.00	06-Sep-24	43,615	428.20	19-Apr-24	15,022	650.25	23,08,10,759	1,50,08,46,42,538.30
F.Y. 2024	588.60	01-Jan-24	24,42,680	353.35	06-Apr-23	4,60,297	477.39	15,03,92,589	71,79,65,05,234.00
Preceding six months									
Period	**High (₹)***	**Date of High**	**No. of equity shares traded on that day**	**Low (₹)***	**Date of Low**	**No. of equity shares traded on that day**	**Weighted Average Price (₹)****	**Total volume traded in that period (No of Equity Shares)**	**Total turnover transacted in the period (in ₹)**
Aug-2026	416.20	07-Aug-26	9,94,119	362.00	31-Aug-26	22,82,719	397.81	1,96,03,909	7,79,85,62,995.45
Jul-2026	435.00	03-Jul-26	9,55,477	394.75	22-Jul-26	7,84,639	412.77	1,34,04,860	5,53,31,15,136.50
June-2026	418.80	22-Jun-26	2,69,616	376.40	08-Jun-26	4,36,832	398.74	1,36,10,563	5,42,70,62,248.15
May-2026	464.15	04-May-26	4,80,095	393.30	29-May-26	10,65,444	424.31	91,64,679	3,88,86,83,897.50
April-2026	477.00	23-Apr-26	6,19,841	385.50	02-Apr-26	4,99,759	436.73	1,19,17,377	5,20,46,61,561.50
Mar-2026	474.75	05-Mar-26	4,36,592	385.95	30-Mar-26	4,68,817	422.55	1,29,26,412	5,46,20,98,603.00

Source: www.nseindia.com

** High and low prices are based on the high and low of the daily prices.*

*** Weighted Average Price (Total Turnover / Total Traded Quantity) for all trading days during the period*

उदारीकरण का विरोधाभास: राज्यों में एफडीआई का प्रवाह कारोबारी सुधारों के अनुरूप नहीं

बिनय सिन्हा

जनवरी 2000 से मार्च 2026 के बीच कुल एफडीआई इक्विटी का 82 फीसदी हिस्सा सिर्फ 7 राज्यों में आया

यश कुमार सिंघल

राज्यों में विदेशी निवेश 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद समान रूप से नहीं पहुंचा। इसका बड़ा हिस्सा कुछ ही राज्यों को मिला। जनवरी 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत में आए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी का करीब 82 फीसदी हिस्सा केवल छह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना समेत) में आया।

जब भारत ने एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के लिए अपने दरवाजे खोले, उस समय देश में पूंजी निवेश कम था। यह आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार की एक बड़ी वजह थी। उम्मीद थी कि विदेशी निवेश बढ़ने से पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और इससे पूरे देश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

भारत में वित्त वर्ष 2021 में शुद्ध एफडीआई का प्रवाह बढ़कर करीब 44 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2001 में यह सिर्फ 3.27 अरब डॉलर था यानी इस दौरान इसमें 1,245.56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद लगातार चार वर्षों तक एफडीआई में गिरावट आई और वित्त वर्ष 2025 में यह घटकर करीब 1 अरब डॉलर रह गया। हालांकि, इसके अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर करीब 7 अरब डॉलर हो गया।

क्षेत्रों की बात करें तो जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के बीच कुल एफडीआई इक्विटी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 16.37 फीसदी रही। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की 15.62 फीसदी और कारोबारी (ट्रेडिंग) क्षेत्र की 6.55 फीसदी हिस्सेदारी रही। सेवा क्षेत्र के भीतर वित्तीय सेवाओं को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला।

राज्यों की बात करें तो जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के बीच सेवा क्षेत्र में आए कुल एफडीआई इक्विटी का 45.22 फीसदी हिस्सा महाराष्ट्र को मिला। वहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर और कारोबारी क्षेत्र में कर्नाटक सबसे आगे रहा।

महाराष्ट्र सबसे आगे

जनवरी 2000 से मार्च 2006 तक कुल एफडीआई इक्विटी निवेश में 24.69 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दिल्ली सबसे आगे थी। इसके बाद महाराष्ट्र शीर्ष पर आ गया। तब से महाराष्ट्र लगभग हर साल सबसे आगे रहा और जनवरी 2000 से मार्च 2026 की पूरी अवधि में उसकी हिस्सेदारी 30 फीसदी से ज्यादा रही। इस दौरान 17.39 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर रही। महामारी के बाद कर्नाटक और गुजरात की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि दिल्ली की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2025 के बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एफडीआई इक्विटी निवेश सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) ने किया। उसने रिलायंस रिटेल वेंचर्स के जरिए भंडारण और वेयरहाउसिंग कारोबार में 1.29 अरब डॉलर का निवेश किया। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 4.03 अरब डॉलर का एफडीआई स्विट्जरलैंड की रॉबर्ट बॉश इंटरनैशनल से आया। यह निवेश मोटर वाहन के इंजन बनाने के लिए किया गया। गुजरात में गूगल इंटरनैशनल एलएलसी सबसे बड़ा निवेशक रहा। उसने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के जरिए आईटी और कंप्यूटर सेवाओं में 4.58 अरब डॉलर का एफडीआई किया। तमिलनाडु में अमेरिका की ब्रिलिएंस टेक्नॉलजीज ने कार्यालय प्रशासनिक सेवाओं के लिए 50 करोड़ डॉलर का एफडीआई किया। इसी तरह, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी के जरिए दिल्ली में 1.4 अरब डॉलर का एफडीआई किया। यह निवेश ग्राहकों को कंप्यूटर सेवाएं देने के लिए किया गया।

अगर राज्यों में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और खनन अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के कारण कुछ प्रस्तावित निवेश रद्द या रोक नहीं दिए गए होते, तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। इनमें ओडिशा की पॉस्को स्टील परियोजना शामिल थी। इससे करीब 12 अरब डॉलर का एफडीआई आने की उम्मीद थी और उस समय इसे सबसे बड़ा विदेशी निवेश सौदा बताया गया था। इसी तरह, फॉक्सकॉन के आईफोन असेंबली संयंत्र से महाराष्ट्र में करीब 5 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद थी।

अलग-अलग रुझान

शुरुआत में ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में सुधार कम हुए और कारोबार करना आसान होने की रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां एफडीआई भी कम आया। हालांकि, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों का भी पिछले दशक में अलग-अलग वर्षों में सरकार की ओर से जारी कारोबारी सुगमता (ईओडीबी) रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर रहा था। मिसाल के तौर पर, दिल्ली और तमिलनाडु 2015, 2016, 2017 और 2019 में शीर्ष 10 राज्यों में जगह नहीं बना सके। वहीं, इन चार वर्षों में महाराष्ट्र और कर्नाटक की सबसे अच्छी रैंक आठवीं रही। इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश ने इन चार में से तीन वर्षों में कारोबारी सुगमता रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, जबकि एक साल वह दूसरे स्थान पर रहा।

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग अपेक्षाकृत बेहतर रही, लेकिन इन राज्यों में एफडीआई का प्रवाह काफी कम रहा। यह रुझान अब भी जारी है। हालांकि, कारोबारी सुगमता की रैंकिंग को सीधे नंबर देने के बजाय अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाता है। इनमें सबसे ऊपर 'सबसे अच्छा प्रदर्शन', इसके बाद 'अच्छा प्रदर्शन', 'तेजी से सुधार करने वाले' और 'सुधार की ओर बढ़ने वाले' श्रेणियां हैं। एफडीआई के मामले में शीर्ष दो राज्य महाराष्ट्र और दिल्ली कारोबारी सुधार कार्ययोजना (बीआरएपी) की रैंकिंग में अभी भी 'सुधार की ओर बढ़ने वाली' श्रेणी में हैं। यह रैंकिंग कारोबार से जुड़े सुधारों के आधार पर राज्यों का आकलन करती है। 2024 की सबसे हालिया रैंकिंग में एफडीआई पाने वाले शीर्ष राज्यों में से कोई भी शीर्ष दो श्रेणियों में नहीं था।

विशेषज्ञों का कहना है कि कारोबारी सुगमता और बीआरएपी की रैंकिंग एफडीआई आने की मुख्य वजह नहीं हैं। एफडीआई का प्रवाह राज्यों के बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों तक पहुंच, आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक नेटवर्क की मौजूदगी पर अधिक निर्भर करता है।

सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) में विशिष्ट प्रोफेसर विश्वजीत धर कहते हैं कि कारोबारी सुगमता और बीआरएपी की रैंकिंग ज्यादा राजनीतिक प्रकृति की हैं और इनमें पारदर्शिता की कमी है। उनके मुताबिक, एफडीआई उन राज्यों में जाता है जहां बुनियादी ढांचा बेहतर है, बाजार मजबूत हैं और बंदरगाहों तक अच्छी पहुंच है। उनका कहना है कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ बंदरगाहों तक पहुंच भी है। वहीं, दिल्ली में बंदरगाह नहीं हैं, लेकिन यहां बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जिससे निवेशकों को बड़ा बाजार मिलता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कारोबारी सुगमता को एक सहायक कारक मानते हैं। उनका कहना है कि यह सुगमता सिर्फ निवेश को आकर्षित करने में थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन असली वजह निवेश के अवसर और उद्योगों की मौजूदगी है। सबनवीस के मुताबिक, वित्तीय क्षेत्र में एफडीआई मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में आता है, जबकि तकनीकी क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों को अधिक निवेश मिलता है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में उद्योग कम हैं और मजबूत वित्तीय ढांचा नहीं है, वहां एफडीआई आने की संभावना भी कम रहती है।

Note 1: In case where the same price is reflected for more than one date during the relevant periods mentioned above, the latest date is being considered for the purposes of disclosure in the above table.

9.3 The stock prices on the Stock Exchanges on relevant dates are:

Date	Description	BSE			NSE		
		High (₹)	Low (₹)	Closing (₹)	High (₹)	Low (₹)	Closing (₹)
September 11, 2026	Day prior to notice of Board Meeting to consider proposal of Buyback was given to the Stock Exchanges	371.00	363.00	363.90	370.00	363.00	363.80
September 14, 2026	Date on which notice of Board Meeting to consider proposal of Buyback was given to the Stock Exchanges	Not Applicable as it was a trading Holiday for Stock Exchanges					
September 17, 2026	Board Meeting day	396.30	370.00	376.10	396.45	370.00	376.10
September 18, 2026	First trading day post Board Meeting day	380.00	367.00	368.30	380.05	366.55	368.45

10. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHARE HOLDING PATTERN-

10.1 The capital structure of the Company as on the date of this Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buyback is set forth below:

(₹ in Lakhs)

Share Capital	Pre Buyback	Post Buyback
Authorized		
50,00,00,000 Equity Shares of Re 1/- each	5,000.00	5,000.00
Issued Subscribed and Paid-up Capital		
43,65,00,000 Equity Shares of Re. 1/- each fully paid up	4,365.00	
43,05,63,158 Equity Shares of Re. 1/- each fully paid up		4,305.63*

** Assuming that as a part of Buyback all the 59,36,842 (Fifty Nine Lakhs Thirty Six Thousand Eight Hundred and Forty Two Only) Equity Shares (Maximum Buyback Shares) are bought back at Maximum Buyback Price. Please note that the shareholding post the Buyback may differ depending on the actual number of equity Shares bought back under the Buyback.*

10.2 The shareholding pattern of the Company as on September 17, 2026 (**"Pre-Buyback"**) and the proposed shareholding pattern of the Company post completion of the Buyback are given below:

Sr. No.	Category of Shareholders	Pre Buyback (as on September 17, 2026)		Post Buyback*	
		Number of Equity Share held	% to the existing Equity Share capital	Number of Equity Share held	% to the Equity Share capital
A.	**Promoter and Promoter Group**	23,93,93,412	54.84	23,93,93,412	55.60
B.	**Public Shareholders**	19,71,06,588	45.16	19,11,69,746	44.40
C1	**Shares underlying DRs**	-	-	-	-
C2	**Shares held by Employee Trust**	-	-	-	-
C.	**Non Promoter-Non Public (C1+C2)**	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	43,65,00,000	100.00	43,05,63,158	100.00

**Assuming the Buyback of Maximum Buyback Shares, i.e., 59,36,842 (Fifty Nine Lakhs Thirty Six Thousand Eight Hundred and Forty Two Only) Equity Shares, at the Maximum Buyback Price, i.e., ₹ 475.00 per Equity Share. The actual shareholding pattern post-Buyback may vary depending upon the actual number of Equity Shares bought back under the Buyback.*

10.3 There are no partly paid-up or Equity Shares or calls in arrears as on the date of this Public Announcement.

10.4 There are no outstanding instruments convertible into shares.

10.5 No scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the Companies Act is pending in relation to the Company as on the date of this Public Announcement.

10.6 The Promoters, members of the Promoter Group and Persons in Control of the Company are not permitted to deal in the Equity Shares on the Stock Exchanges or off-market, including inter-se transfer of Equity Shares among the Promoters and members of the Promoter Group from the date of the Board meeting approving the Buyback until the closure of the Buyback.

10.7 While the Promoters, members of the Promoter Group and Persons in Control of the Company are not eligible to participate in the Buyback, depending on the number of Equity Shares bought back by the Company, their effective shareholding percentage in the Company will increase

10.8 Such an increase in the percentage holding/voting rights of the Promoters, members of the Promoter Group and persons in control of the Company, is not an active acquisition and is incidental to the Buyback and if such increase is beyond the limits prescribed under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, then Promoters and members of the Promoter Group will avail an exemption from the SEBI under Regulation 10 of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or will reduce their shareholding within ninety days from the Buyback Closing Date, such that their voting rights fall below the level at which the obligation to make an open offer under sub-regulation (2) of Regulation 3 of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 will not trigger

11. DETAILS OF PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL AND DIRECTORS OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

11.1 For the details of the aggregate shareholding of the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter is a company), directors, key managerial personnel and of persons who are in control of the Company as on the date of this Public Announcement, please refer to paragraph 8.1, 8.2 and 8.3 of Part A above.

11.2 For the details of Equity Shares sold or purchased by the persons mentioned in paragraph 11.1 above during a period of 12 (twelve) months preceding the date of this Public Announcement and 6 (six) months preceding the date of the Board Meeting, please refer to paragraph 8.4 and 8.5 of Part A above.

12. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUYBACK ON THE COMPANY

12.1 The Buyback is expected to enhance overall long-term shareholders' value for continuing shareholders, without compromising on the future growth opportunities of the Company, as well as provide an exit opportunity to the public shareholders. The Buyback is not likely to cause any material adverse impact on the earnings of the Company, except a reduction in the treasury income which the Company could have otherwise earned from investments. The Company will also bear the cost of the Buyback transaction.

12.2 The Buyback is proposed, considering the accumulated surplus funds available with the Company, after considering the funds required for future growth of the Company as envisaged by the Board.

12.3 The Buyback will be funded out of the internal accruals of the Company including free reserves of the Company, in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 16(iv) of the Buyback Regulations.

12.4 The Buyback will lead to reduction in existing Equity Shares and consequently, is expected to improve the 'earnings per share' and enhance return on equity, assuming that the Company would earn similar profits as in the past.

12.5 Pursuant to Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company will not participate in the Buyback. The Buyback will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

12.6 Consequent to the Buyback (which excludes participation by the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company) and based on the number of Equity Shares bought back by the Company from the shareholders including resident outside India, erstwhile overseas corporate bodies, foreign portfolio investors and non-resident Indian shareholders, the shareholding pattern of the Company would undergo a change; however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up equity share capital of the Company.

12.7 In accordance with Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) of the Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company to the paid-up equity share capital and free reserves after the Buyback shall be (i) less than or equal to 2:1, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever is lower or (ii) be less than or equal to 2:1, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever is lower, after excluding financial statements of all subsidiaries that are non-banking financial companies and housing finance companies regulated by Reserve Bank of India or National Housing Bank, as the case may be as on March 31, 2026;

12.8 The Company shall not issue any Equity Shares or other securities including by way of bonus issue except in discharge of subsisting obligations through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares, till the date of expiry of the Buyback period in accordance with the applicable provisions of the Companies Act and the Buyback Regulations. The Company shall not make any further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares or other specified securities within a period of 6 (six) months after the completion of the Buyback except by way of bonus shares or equity shares issued in order to discharge subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into Equity Shares. Further, in accordance with Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (one) year from the expiry of the Buyback period, except in discharge of its subsisting obligations.

12.9 Unless otherwise determined by the Board or Buyback Committee or as may be directed by the Appropriate Authorities, the Buyback will be completed within a maximum period of sixty six Working Days from the date of opening of the Buyback. In accordance with Buyback Regulations, the Company shall not withdraw the Buyback once this Public Announcement has been made.

13. STATUTORY APPROVALS

13.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions of the Companies Act and applicable Rules thereunder and the provisions of the Buyback Regulations and Article 52A of the Articles of Association of the Company, the Company has obtained the Board of Directors approval as mentioned above.

13.2 The Company has obtained the prior consents from its lenders for the Buyback.

13.3 Buyback from each shareholder is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the Reserve Bank of India and / or SEBI, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buyback. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

13.4 The Buyback from erstwhile overseas corporate bodies and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time.

13.5 To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buyback as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their Equity Shares to the Company as set out in paragraph 13.2 and 13.3 of Part B above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buyback.

14. COLLECTION AND BIDDING CENTERS

The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centres and bidding centres is not applicable.

15. COMPLIANCE OFFICER TO THE BUYBACK

The Company has designated/nominated Mr. Arpit Shah (AGM), a qualified Company Secretary as the Compliance Officer for the purposes of the Buyback, to ensure continuous compliance with the applicable provisions of the Buyback Regulations, as amended time to time, including the Companies Act, 2013, the rules made thereunder and the other applicable regulations.

Investors may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during office hours i.e., 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on all Working Days except Saturday, Sunday and public holidays.

Name: Mr. Arpit Shah

Designation: Compliance Officer to the Buyback

Emami Limited

687, Emami Tower, Anandapur E M Bypass, Kolkata, West Bengal, 700 107

Tel No.: +91- 33 - 66136264

Email: investors@emamigroup.com

The Compliance Officer for the buyback is authorized by the Company to discharge the functions and responsibilities relating to the Buyback, including addressing and facilitating the redressal of grievances and queries of shareholders/security holders and ensuring compliance with the applicable statutory and regulatory requirements in relation to the Buyback, communication to the stock exchanges, SEBI, intermediaries and other regulatory authorities as applicable including all regulatory filings thereto.

16. INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any query, the shareholders may also contact Maheshwari Datamatics Pvt Ltd, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, appointed as the Investor Service Centre for the purposes of the Buyback, any day except Saturday and Sunday and public holiday between 10.30 a.m. to 5.30 p.m. at the following address:

Maheshwari Datamatics Pvt Ltd

23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata, West Bengal - 700001

Tel No.: +91 33 - 22482248 / 22435029;

Contact Person: Mr. Subhabrata Biswas

Email: contact@mdplcorporate.com

Website: www.mdpl.in

SEBI Registration No.: INR000000353

Validity Period: Permanent

(Unless suspended or cancelled by SEBI)

CIN: U20221WB1982PTC034886

17. MERCHANT BANKER FOR THE BUYBACK

The Company has appointed the following as Manager to the Buyback:

IIFL CAPITAL

IIFL Capital Services Limited

(formerly known as IIFL Securities Limited)

24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg

Lower Parel (West), Mumbai 400 013

Maharashtra, India

Tel. No.: +91 22 4646 4728

Email: emamibuyback_2026@iiflcap.com

Website: www.iiflcapital.com

Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com

SEBI Registration No.: INM000010940

Validity Period: Permanent

(**unless** suspended or cancelled by SEBI)

Contact Person: Gaurav Mittal/ Jesica Thakkar

CIN: L99999MH1996PLC132983

18. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc., which may be issued by the Company in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of **Emami Limited**

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Harsha Vardhan Agarwal	**Mr. Sushil Kumar Goenka**	**Mr. Arpit Shah**
Designation: Vice-chairman and Managing Director **DIN:** 00150089	**Designation:** Whole-time Director **DIN:** 00149916	**Designation:** Compliance Officer to the Buyback **Membership No:** ACS 35265

Place: Kolkata

Date: September 18, 2026

'एमडीआर से नहीं बढ़ेगा नकद लेन-देन'

डिप्टी गवर्नर एस सी मुर्मू ने कहा कि एमडीआर से यूपीआई भुगतान ढांचा अपनी लागत की भरपाई कर पाएगा

सुब्रत पांडा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने के बाद नकद लेन-देन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने की आशंका में दम नहीं है। मुर्मू ने कहा कि एमडीआर से यूपीआई भुगतान ढांचा अपनी लागत की भरपाई कर पाएगा। उन्होंने कहा कि यह सच है कि डिजिटल भुगतान ने नकद लेन-देन की जगह ले ली है मगर नकद रकम की भूमिका अब भी बनी हुई है और कई मौकों पर इसका अपना महत्त्व है।

कोलकाता में बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम मुर्मू ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि एमडीआर लगने से कोई असर होगा। कुछ लोग यह आशंका जरूर जता रहे हैं कि यूपीआई पर शुल्क लगने से नकदी का इस्तेमाल बढ़ सकता है।'

इस सप्ताह की शुरुआत में यूपीआई भुगतान ढांचा का संचालन करने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने घोषणा की कि 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेन-देन के लिए यह शुल्क अधिक से अधिक 300 रुपये होगा। 2,000 रुपये तक के पी2एम लेन-देन एमडीआर के दायरे में नहीं आएंगे, साथ ही परिवार और दोस्तों के बीच रकम लेन-देन (पी2पी) भी इससे मुक्त रहेंगे। यूपीआई पर एमडीआर 15 अक्टूबर से लागू होगा।

हालांकि, एनपीसीएल ने साफ कर दिया है कि यह शुल्क कारोबारी या कारोबारी प्रतिष्ठान पर लगाया जाएगा और ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान निःशुल्क रहेगा। मगर ऐसी चिंताएं भी सामने आई हैं कि कारोबारी आखिरकार यह लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कुछ ग्राहक बड़ी रकम के लेन-देन फिर नकद में कर सकते हैं।

आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि 2,000 रुपये से कम के पी2एम यूपीआई लेन-देन कारोबारियों के लिए निःशुल्क रहेंगे जबकि पी2एम लेन-देन के लिए उन पर एमडीआर लगाया जा सकता है।

आरबीआई ने कहा, 'इससे यूपीआई को देश भर में ग्राहकों और व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने, नई चीजें लाने और सेवाएं देने में मदद मिलेगी। पूरे तंत्र में शामिल लोगों के बीच एमडीआर का उचित विभाजन तकनीक अवसंरचना और स्वीकार्य तंत्र (एक्सेप्टेंस नेटवर्क) में लगातार निवेश को बढ़ावा देगा। इससे यूपीआई और अधिक जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही लेन-देन की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होगी।'

मुझे नहीं लगता कि एमडीआर लगने से कोई असर होगा। कुछ लोग यह आशंका जरूर जता रहे हैं कि यूपीआई पर शुल्क लगने से नकदी का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

शिरीष चंद्र मुर्मू,
डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि यूपीआई सभी के लिए सुरक्षित, आसान, किफायती और सभी की पहुंच में रहे और साथ ही भारत के विश्व-स्तरीय डिजिटल भुगतान ढांचे को बढ़ावा और स्थिरता दे।

मुर्मू ने नकद से जुड़े विरोधाभास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह सच है कि जहां एक ओर डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चलन में मौजूद मुद्रा भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है जबकि सैद्धांतिक तौर पर इसमें उल्टा संबंध होना चाहिए। मुर्मू ने 13 अगस्त को जकार्ता में बैंक इंडोनेशिया द्वारा आयोजित वैश्विक नकदी प्रबंधन पर एक चर्चा में कहा, 'पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान में प्रगति अभूतपूर्व रही है मगर चलन में मौजूद नकदी में कोई कमी नहीं आई है, खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कम आय वाले समूहों, बुजुर्गों और छोटे व्यवसाय लगातार नकद लेन-देन कर रहे हैं।'

मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही लेन-देन के लिए नकद की जगह डिजिटल भुगतान ने ले ली है मगर नकद लेन-देन भी खूब हो रहे हैं।

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 के अंत में चलन में मौजूद मुद्रा 42.86 लाख करोड़ रुपये थी जो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में 41.66 लाख करोड़ रुपये और उससे एक वर्ष पहले 37.24 लाख करोड़ रुपये थी। डिजिटल भुगतान में तेजी के बावजूद नकद की मांग में तेजी मुद्रा की मांग का अनुमान लगाने में आरबीआई के सामने आने वाली चुनौती को उजागर करती है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के तौर पर देखें तो चलन में मुद्रा का स्तर वित्त वर्ष 2021 के बाद कम हो रहा है जब यह 14.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। लगातार चार वर्षों तक गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2026 में इस अनुपात में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह 12.1 प्रतिशत हो गया।

डिजिटल लेन-देन में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद नकद रकम का इस्तेमाल भी बढ़ा है। अगस्त में यूपीआई लेन-देन की संख्या में सालाना 22.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि मूल्य के हिसाब से यह बढ़ोतरी लगभग 20 प्रतिशत रही।

छोटे दुकानदार ग्राहकों पर डाल सकते हैं बोझ

शार्लीन डिसूजा

उद्योग संगठनों के मुताबिक, छोटे और मध्यम दुकानदार और कारोबारी 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) से बचने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। वे इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं या यूपीआई से भुगतान लेने के बजाय बैंक के जरिए लेनदेन कर सकते हैं। सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर को एमडीआर की नई व्यवस्था की घोषणा की है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होगी।

दैनिक उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) क्षेत्र के संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एमडीआर के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इसका असर देश के लाखों छोटे दुकानदारों, वितरकों और कम मुनाफे पर काम करने वाले कारोबारियों पर ज्यादा पड़ेगा। एआईसीपीडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील एच. पाटिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'यूपीआई भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी तकनीकी उपलब्धियों में से एक है। इसने देश की भुगतान व्यवस्था को बदल दिया है और लाखों दुकानदारों और ग्राहकों तक डिजिटल भुगतान पहुंचाया है। हमें यूपीआई की सफलता की वजह बनी इसकी सरलता, कम लागत, आसान उपलब्धता और हर जगह स्वीकार्यता को बनाए रखना चाहिए।'

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने भी कहा है कि भारत के खुदरा बाजार का 80 फीसदी हिस्सा छोटे और मध्यम दुकानदारों के पास है। आरएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन ने कहा कि छोटे दुकानदार एमडीआर का भुगतान करने से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं। उन्होंने कहा, 'ज्यादातर दुकानदारों का शुद्ध मुनाफा 2 से 3 फीसदी के बीच होता है। ऐसे में 0.4 फीसदी एमडीआर लगने से उनके मुनाफे पर बड़ा असर पड़ सकता है।' राजगोपालन ने आगे बताया कि अगर कोई दुकानदार अपने आधे भुगतान यूपीआई से और बाकी नकद में लेता है, तो भी एमडीआर का खर्च उसके शुद्ध मुनाफे का करीब 0.2 फीसदी होगा। उन्होंने कहा, 'खुदरा कारोबार में एमडीआर को लेकर काफी सावधानी बरती जाती है और छोटी से छोटी लागत भी मायने रखती है। ऐसे में दुकानदार यूपीआई से होने वाले लेनदेन से बचने के लिए बैंक ट्रांसफर बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं।' कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय खाद्य तेल कारोबारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने भी कहा कि दुकानदार या तो लेनदेन को अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं या एमडीआर की लागत ग्राहकों पर डालने का रास्ता अपना सकते हैं। इसके लिए वे बिना ब्रांड वाले उत्पादों की कीमत बढ़ा सकते हैं। राजगोपालन ने यह भी कहा कि दुकानदार अपने इलाके में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एमडीआर की लागत ग्राहकों से वसूलने के तरीके तलाशेंगे।

'निलेकणी समिति की रिपोर्ट पेश करें'

भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की सुरक्षा व विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्च समिति की कार्यस्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से अब तक हुई प्रगति का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। विभाग के संयुक्त सचिव समिति के समन्वयक भी हैं। उन्हें यह हलफनामा दो हफ्ते में जमा करना है और मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कामकाज और आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के लिए उसके मुख्यालय का दौरा कर सकती है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, 'हम एक दिन वहां आएंगे, मैं और मेरे साथी जज।' न्यायालय को बताया गया कि एनटीए को मिंटो रोड के पास एक स्थायी जगह आवंटित की गई है।

पीठ ने कहा कि फिजिकल इंस्पेक्शन से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एजेंसी के पास पर्याप्त मानवश्रम है या नहीं और जो तरीके लागू किए गए हैं, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। न्यायालय ने दूसरे सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय एनटीए में स्थायी मानवश्रम होने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीठ ने कहा, 'वहां स्थायी स्टाफ होना चाहिए। साथ ही, दूसरी काम करने वाली संस्थाओं के साथ आपके संबंध, आप उनके साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, कितने आंकड़े हैं... क्या हमें सांविधिक आधार की जरूरत है?'

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि निलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने साझेदारों के साथ व्यापक बातचीत की है। उम्मीद है कि समिति सितंबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस कवायद का नतीजा संस्थागत सुधारों के रूप में निकलना चाहिए, न कि सिर्फ ऐसी रिपोर्ट के तौर पर जो कागजों तक ही सीमित रह जाए।

पीठ ने कहा, 'सबसे जरूरी चीज संस्थानीकरण है।' पीठ ने कहा कि समिति का हलफनामा रिकॉर्ड पर आने के बाद वह उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई करेगी। मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीठ ने परीक्षा प्रणाली को फिर से डिजाइन करते समय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने के महत्त्व पर भी जोर दिया।

यह कार्यवाही नीट-यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों से संबंधित कई याचिकाओं के कारण शुरू हुई थी। 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन' (एफएआईएमए) की याचिका में एनटीए के पुनर्गठन या उसे बदलने की मांग की गई है। एफएआईएमए ने कई उपाय भी सुझाए हैं। इनमें प्रश्नपत्रों की डिजिटल लॉकिंग, नीट-यूजी को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रारूप में बदलना और गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए केंद्र-वार परिणाम प्रकाशित करना शामिल हैं।

पड़ोसी देशों से संबंध साधने की कवायद तेज

अर्चिस मोहन

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को भूटान की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी कर ली। जयशंकर की इस यात्रा के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी संपर्क और ऊर्जा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 सितंबर तक श्रीलंका के दौरे पर थे। पिछले 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की श्रीलंका की यह पहली यात्रा थी।

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। वागले ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। भारत ने हाल ही अचानक आई बाढ़ से प्रभावित अपने उत्तरी पड़ोसी देश को राहत, नुकसान से उबरने और पुनर्निर्माण के प्रयासों में लगातार समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

इस बीच, भारत और बांग्लादेश इस वर्ष के अंत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष आपसी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में चल रही यह खबर देखी है कि बांग्लादेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में हुए द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश ने इस बारे में भारत को आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त नदी तंत्र पानी के बंटवारे से जुड़े सभी मुद्दों पर तकनीकी स्तर की बैठकें हो रही हैं जिसमें गंगा जल बंटवारा संधि भी शामिल है जो 30 साल पुरानी है और दिसंबर में खत्म हो रही है।

भारत ने शुक्रवार को यह भी कहा कि मालदीव सरकार ने 17 सितंबर को ट्रेजरी बिल की 5 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया। यह कुल 15 करोड़ डॉलर का हिस्सा था जिसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने खरीदा था जिसमें भारत ने ब्याज भुगतान के तौर पर पूरे 4.5 करोड़ डॉलर का बोझ उठाया। जायसवाल ने कहा कि एसबीआई ने वर्ष 2019 से ट्रेजरी बिल खरीदे थे और उन्हें अब तक छह बार, हर बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि जहां टी-बिल की मूल राशि का भुगतान मालदीव सरकार ने किया वहीं पिछले पांच वर्षों में सभी 15 करोड़ डॉलर के टी-बिल पर ब्याज का भुगतान भारत सरकार ने किया। जायसवाल ने कहा, 'भारत ने ब्याज के निपटान के तौर पर कुल मिलाकर लगभग 4.5 करोड़ डॉलर का भुगतान किया।'

भारत ने मालदीव की वित्तीय व्यवस्था को सहारा देने के लिए उसे 30 अरब रुपये की मुद्रा अदला-बदली (स्वैप) सुविधा भी दी है। जयसवाल ने बताया कि इसके अलावा भारत ने 35 करोड़ डॉलर मूल्य के टी-बॉन्ड भी खरीदे हैं जो 2029 और 2030 तक मान्य हैं।

जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर की भूटान यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से पांच विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया।

यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी से की बात

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति नाहयान ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगातार सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी। यूएई के राष्ट्रपति ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भी बधाई दी।

भारत ने पाकिस्तान के आरोप किए खारिज

भारत ने शुक्रवार को अरब सागर में पाकिस्तानी जहाज और भारतीय नौसेना के युद्धपोत के बीच टक्कर से जुड़े पाकिस्तान के आरोप खारिज कर दिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि यह घटना पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईई) में भारतीय जहाज की 'बेहद उकसावे वाली और अस्वीकार्य कार्रवाई' के बाद हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने हमारे विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी है। यह वही आम टालमटोल वाला रवैया है जिसकी हमें अनुमान था। हम उसमें लगाए गए आरोपों और इशारों को खारिज करते हैं।' **(साथ में एजेंसियां)**

मराठी फिल्म 'गोंधल' ऑस्कर के लिए नामित

मराठी फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर पुरस्कार 2027 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। 'फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एफएफआई) ने शुक्रवार को यह घोषणा की। संतोष डावखर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म ग्रामीण महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसकी कहानी एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ी पारंपरिक रस्म वाली एक रात के इर्द-गिर्द घूमती है। चयन समिति के अध्यक्ष पी. शेषाद्रि ने कहा कि 33 फिल्मों की सूची में से इस फिल्म को 99वें एकेडमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। शेषाद्रि ने कहा, 'इस साल हमारे पास चार मराठी फिल्में, 14 हिंदी फिल्में और अन्य फिल्में थीं। सभी फिल्में अच्छी थीं। यह भारतीय सिनेमा और मराठी सिनेमा के लिए खुशी का पल है। इस बार आधिकारिक प्रविष्टि 'गोंधल' है।' **भाषा**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

कॉर्पोरेट कार्यालय, मोंटक्लेयर, 134/1, बानेर- पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र एवं प्रतिष्ठित बोलीदाताओं / सेवा प्रदाताओं से "**आरएफपी 28/2026-27 : पाँच (05) वर्षों की अवधि हेतु DPDP गवर्नेंस एवं अनुपालन (Governance and Compliance) के लिए एंटरप्राइज समाधान की आपूर्ति, कार्यान्वयन एवं रखरखाव**" के लिए मुहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofmaharashtra.bank.in** पर 'टेंडर सेक्शन' में और जेम पोर्टल **https://gem.gov.in/** पर दिनांक 17.09.2026 से उपलब्ध है।

आरएफपी संख्या: आरएफपी - 28/2026-27

जीईएम बोली संख्या: GEM/2026/B/7993915

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 09.10.2026, 17:00 hrs.

इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त साइट से आरएफपी दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं से संबंधित सभी अन्य अपडेट **GeM पोर्टल** पर भी उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ह/-

दिनांक : 18.09.2026 **मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**